प्रभात

अंदर के पन्नों में .....

★ नंदीग्राम ने सीपीएम का लाल नकाब उतार फेंका 11
★ सलवा जुडूमी आतंक के साये में शिक्षा 17
★ भाषा पर डीके एसजेडसी का वक्तव्य 18
★ संघर्षों की रपटें... 19
★ सभा-सम्मेलनों की रपटें 22
★ पीएलजीए के हमलों से धधकता दण्डकारण्य 27
★ शहीदों को श्रद्धांजली 33
★ देश-दुनिया की खबरों पर एक नजर 38

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

20वीं वर्षगांठ का विशेषांक

वर्ष-20 अंक-4 अक्टूबर-दिसम्बर 2007 सहयोग राशि-10 रुपए

'प्रभात' के बीस जुझारू बरस पूरे !

दण्डकारण्य में जनयुद्ध के साथ-साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती 'प्रभात' का लाल अभिनन्दन !!

1980 में दण्डकारण्य में 'इलाकावार राजसत्ता की स्थापना' के लक्ष्य से क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल बजा। देश में इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज आपातकाल (1975-77) के खत्म होने के बाद आंध्रप्रदेश के करीमनगर-आदिलाबाद जिलों में किसान आंदोलन का जबर्दस्त उभार आया। उसी उभार में से दण्डकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन के बीज पड़े। यह आंदोलन पिछले 27 सालों से कई उतार-चढ़ावों से और जीत-हार-जीत के क्रम में नई बुलंदियों पर पहुंचते हुए विस्तारित हो रहा है। आंदोलन के इन 27 सालों में 'प्रभात' को पैदा हुए 20 साल पूरे हो रहें हैं। इन 20 बरसों में एक क्रांतिकारी पार्टी के मुखपत्र के रूप में 'प्रभात' ने जो उपलब्धियां हासिल कीं, जिन समस्याओं व मुश्किलों का सामना किया और फिलहाल वह जिन चुनौतियों का सामना कर रही है वो सब दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के विकासक्रम का हिस्सा ही है। आइए, इसकी 20वीं वर्षगांठ के मौके पर उन सभी पहलुओं पर सरसरी नजर डालें।

1987 में 'प्रभात' की शुरूआत हुई। तत्कालीन दण्डकारण्य फॉरेस्ट कमेटी के राजनीतिक मुखपत्र के रूप में शुरू हुई 'प्रभात' ने 1997 में अपने दस साल पूरे किए। उन दस सालों के दौरान 1992-94 के बीच तकरीबन दो साल तक 'प्रभात' का प्रकाशन रुक गया था। नागपुर और रायपुर में हुई गिरफ्तारियों के चलते इस पत्रिका का ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ था। दुश्मन द्वारा चलाए गए दमनचक्र के मद्देनजर इस पत्रिका को शहरों से प्रकाशित कर पाने की स्थिति खत्म हो गई ऐसे हालात में तत्कालीन फॉरेस्ट कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इसे मैदान-ए-जंग से ही प्रकाशित किया जाए। इस पत्रिका के इतिहास में एक अहम मोड़ कहा जा सकता है। इस फैसले के फलस्वरूप ही पिछले 13 सालों से 'प्रभात' संघर्षशील जनता का गढ़ दण्डकारण्य से प्रकाशित होती रही है।

शुरू से लेकर आज तक चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न आई हो आज अपने 20 बरस पूरे करना अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धी है। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में गुरिल्ला जोन का निर्माण कर आधार इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ रही किसी रणभूमि से इस तरह किसी पत्रिका का निरंतर प्रकाशन हमारी पार्टी के लिए भी पहला अनुभव है। लाल प्रतिरोधी इलाके के रूप में दण्डकारण्य का संघर्ष जब अपने शुरूआती दौर से गुजर रहा था, तभी अस्तित्व में आई 'प्रभात' संघर्ष के विकास के साथ-साथ आगे बढ़ती आ रही है। क्रांतिकारी आंदोलन में आ रहे सभी सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को पार्टी और क्रांतिकारी जनता के सामने रखने में 'प्रभात' काफी हद तक सफल हुई। पार्टी और पीएलजीए के कार्यकर्ताओं को पार्टी की समझदारियों और नीतियों से शिक्षित करने में 'प्रभात' ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस उपलब्धी के लिए इसके सम्पादकों का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने पत्रिका को नियमित रूप से लाने के भरपूर प्रयास किए। इससे भी बढ़कर 'प्रभात' के स्टाफ के कॉमरेडों और उनका हरदम सहयोग करने वाले क्रांतिकारी जन समुदायों की भूमिका काफी सराहनीय रही जिन्होंने भीषण शत्रु

8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिन्दाबाद!

जेलों व पुलिस हिरासत में क्रांतिकारी महिलाओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करो!!

दमन के बीचोबीच भी इसके प्रकाशन और वितरण हर किस्म का सहयोग दिया। उनके दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम की कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसकी बदौलत ही यह पत्रिका काफी हद तक समय पर निकल सकी और इससे क्रांतिकारी आंदोलन को मदद मिली। 'प्रभात' को सुधारने के लिए पाठकों ने अनमोल सुझाव देकर और सटीक आलोचनाएं करके इसकी जीवटता को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। उन सभी का हम इस मौके पर क्रांतिकारी अभिनन्दन पेश करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले, 'प्रभात' के स्टाफ कॉमरेडों में से एक, उसके विकास के लिए अथक प्रयास करने वाले, 1999 में कोटेनार में हुई झूठी मुठभेड़ में शहीद हुए कॉमरेड सोमन्ना की शैर्यपूर्ण कुरबानी को इस मौके पर विनम्र श्रद्धांजली पेश करते हैं। इनके अलावा कई अन्य वीर शहीदों, जिन्होंने 'प्रभात' के प्रकाशन कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया, को भी हम नम आंखों से श्रद्धांजली पेश करते हैं। ऐसे कई कॉमरेड हैं जिनके नाम हम तकनीकि कारणों से नहीं ले सकते।

इन बीस बरसों के दौरान 'प्रभात' के कई विशेष अंक भी प्रकाशित हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दिनों, पार्टी के महत्वपूर्ण आयोजनों और पार्टी में पनपने वाले गैर-सर्वहारा रुझानों के खिलाफ चलाए गए भूल-सुधार अभियानों के मौकों पर 'प्रभात' के विशेषांक छपे थे। खासकर पिछले ढाई सालों से, दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन का समूल नाश करने की मंशा से राज्य द्वारा प्रायोजित प्रति-क्रांतिकारी और फासीवादी 'सलवा जुडूम' अभियान ने जो कत्लेआम, अत्याचार और तबाही का तांडव मचाया उसका पर्दाफश करते हुए पाठकों को तथ्यों से रूबरू करवाने में 'प्रभात' ने अपना पूरा योगदान दिया। दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन में काम करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की जीवनियों का समय पर संग्रहण करते हुए क्रांतिकारी जनता तक पहुंचाने में 'प्रभात' हमेशा प्रयासरत रही। भारत की नई जनवादी क्रांति को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी और जनता के हित में मुस्कराते हुए अपना खून बहाने वाले बलिदानी वीरों, जिनमें भाकपा (माओवादी) के सैकड़ों नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थक शामिल हैं, के आदर्शों को जनता में प्रचारित करने में 'प्रभात' हमेशा आगे रही। बिरादराना पार्टियों के नेताओं की कुरबानियों को ऊंचा उठाते हुए उनसे दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता से परिचित कराने में 'प्रभात' ने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद का झण्डा हमेशा बुलंद रखा। कई मौकों पर निकाले गए 'प्रभात' के विशेषांकों के जरिए कुछ विशेष मुद्दों पर पाठकों तक पार्टी की नीति और समझदारी पहुचाने में काफी मदद मिली।

देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहे राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम पर पार्टी की समझदारी समय पर पाठकों के सामने रखने में 'प्रभात' कभी पीछे नहीं रही। साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्व जनता का क्यों नंबर एक दुश्मन है, यह राजनीतिक समझदारी हर संभव मौके पर पाठकों तक पहुंचाने में 'प्रभात' ने पूरी कोशिश की। अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका के एकतरफा दुराक्रमणों का खण्डन करने में, फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्षों को कुचल रहे फासीवादी इज्राएल का अमेरिका द्वारा समर्थन की भर्त्सना करने में तथा भारतीय शासक वर्गों द्वारा अपनाई जा रही अमेरिकी साम्राज्यवाद-अनुकूल नीतियों का जनता में पर्दाफाश करने में 'प्रभात' ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत में जारी कई राष्ट्रीयताओं, खासकर कश्मीर और पूर्वोत्तर इलाके के संघर्षों और अलग होने के अधिकार समेत उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का 'प्रभात' ने हमेशा समर्थन किया 'प्रभात' ने कई मौकों पर पार्टी की समझदारी जनता तक ले जाते हुए लेख प्रकाशित किए। कार्गिल युद्ध के संदर्भ में 'प्रभात' ने उसे भारत और पाकिस्तान के शासक वर्गों की साम्राज्यवाद-अनुकूल राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दुष्परिणाम करार दिया। 'कश्मीर खुद कश्मीरियों का है, न भारत का न ही पाकिस्तान का है'। पार्टी की इस राजनीतिक समझदारी को जनता के सामने रखने में 'प्रभात' ने अपनी भूमिका निभाई। देश के कई हिस्सों में पृथक राज्य के गठन की मांग से कई दशकों से जारी आंदोलनों का 'प्रभात' ने सर्वहारा दृष्टिकोण के साथ दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। इन्हें क्षेत्रीय असमानताओं के फलस्वरूप पनप रहे न्यायपूर्ण आंदोलन बताकर पृथक तेलंगाना आंदोलन, आदि का समर्थन कर रही है। पृथक विदर्भ की मांग का भी 'प्रभात' समर्थन करती है। उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ जब पृथक राज्य के बने 'प्रभात' ने उनका पूरा समर्थन किया। साथ ही साथ, इसने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि सिर्फ भौगोलिक सरहदों की बुनियाद पर अलग राज्य बनने से उसकी गिनती देश के पुराने राज्यों के बगल होने से बढ़कर कुछ नहीं हासिल होगा। इसने स्पष्ट किया कि संघीय राज्यों के रूप में जब तक वे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते तब तक जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं। पृथक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 'प्रभात' ने पार्टी की नीति के मुताबिक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठन का मजबूती से समर्थन करते हुए ही बस्तर को उसमें सम्मिलित करने का विरोध किया। यह बस्तर की जनता की तमन्नाओं के खिलाफ था। बस्तर में मौजूद अपार प्राकृतिक संपदाओं को लूटने की ही मंशा से यह फैसला लिया गया। इन बातों का पर्दाफाश करते हुए बस्तर को एक पुथक राज्य के रूप में गठित करने की जनता की मांग का 'प्रभात' ने पूरा समर्थन किया।

आर्थिक मामलों में भारत के शासक वर्गों द्वारा अपनाई जा रही साम्राज्यवाद परस्ती नीतियों का विरोध करते हुए 'प्रभात' समय-समय पर उन नीतियों के विनाशकारी परिणामों के बारे में लोगों को बताती रही। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शोषणकारी नीतियां साम्राज्यवादियों, मुख्य रूप से अमेरिकी साम्राज्यवादियों के संकट से उबर आने के उपायों का हिस्सा हैं। इनके दुष्परिणामों का बोझ मुख्य रूप से उत्पीड़ित देशों के मजदूर-किसानों पर लादा जा रहा है, यह चेतावनी 'प्रभात' समय-समय पर देती रही। बाल्को का निजीकरण, कृषि के क्षेत्र में तीखा होता संकट, उसके नतीजतन हजारों की संख्या में हो रही किसानों की आत्महत्याएं, सरकारों द्वारा हर साल साम्राज्यवादियों के इशारों पर बनाए जा रहे बजट, आदि मुद्दों के बारे में 'प्रभात' ने अपने पाठकों को आर्थिक दृष्टिकोण से अवगत करवाने की कोशिश की। दूसरे दौर के अर्थिक सुधारों के तहत तेजी से और तीव्र रूप से सामने आ रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के निर्माण

के विषय में 'प्रभात' ने अपनी आवाज बुलंदी से उठाई। इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के अंतहीन आर्थिक हितों का भण्डाफोड़ करते हुए स्पष्ट किया कि जनता के विस्थापन का यही मूल कारण है। कलिंगनगर में पुलिस द्वारा 13 आदिवासियों का कत्लेआम कर टाटा कम्पनी को उनकी जमीनें सौम्पने की साजिश का 'प्रभात' ने पर्दाफाश किया। उड़ीसा के जगतसिंगपुर में पोस्को द्वारा प्रस्तावित भारी स्टील प्लांट के निर्माण का भी विरोध कर 'प्रभात' ने जनता का पक्ष लिया। जहां भी रेल लाइनों के निर्माण और उद्योगों की स्थापना होती है उन इलाकों में विकास होगा, लुटेरे शासक वर्गों के इस पूंजीपरस्त दुष्प्रचार की 'प्रभात' ने पोल खोल दी। इस प्रचार के पीछे हो रही धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए हीरानार में शुरू कर फिर नगरनार ले जाए गए रोमेल्ट स्टील प्लांट का विरोध करते हुए 'प्रभात' ने जनता को जागरूक बनाने की कोशिश की। इस धोखाधड़ी का इसने आंकड़ों और उदाहरणों समेत भण्डाफोड किया। नगरनार के विस्थापित लोगों के प्रति 'प्रभात' ने संवेदना प्रकट की। दण्डकारण्य के कुछ हिस्सों में और उससे सटे हुए इलाकों में खनिजों की खुदाई के लिए राज्य सरकारें बड़े पूंजीपतियों से बड़ी तेजी से समझौते कर रही हैं। महाराष्ट्र में गड़चिरोली डिवीजन के सूर्जागढ़ में एक हजार एकड़ के क्षेत्र में उत्खनन कार्य शुरू हुआ है। उत्तर बस्तर के चारगांव इलाके में निको कम्पनी ने खदान शुरू करने की कोशिश की तो जनता ने उसे रोक दिया। कांकेर और राजनांदगांव जिलों की सीमा पर स्थित पल्लामाड़ इलाके में रायपुर एलायज कम्पनी खदान खोलकर सैकड़ों टन लौह अयस्क ले जा रही है जबकि गोदावरी इस्पात और निको कम्पनियां इस कोशिश में हैं। बस्तर के लोहण्डीगुड़ा और दन्तेवाड़ा जिले के धुरली में टाटा और एस्सार कम्पनियां अपने स्टील कारखाने खोलने की कोशिशों में हैं और जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। उधर दल्ली-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए केन्द्र-राज्य सरकारों और सेल (भारतीय इस्पात प्रधिकरण लिमिटेड) ने पूरी तैयारियां कर लीं। इन सबके परिणामस्वरूप दण्डकारण्य और उससे सटे हुए वनांचलों में मौजूद आदिवासी और गैर-आदिवासी शोषित जनता अपना अस्तित्व खोने का खतरा झेल रही है। जनता को इस खतरे से आगाह करते हुए तथा इसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाने का आह्वान करते हुए 'प्रभात' एक संगठक की भूमिका अदा कर रही है।

सामाजिक समस्याओं पर भी 'प्रभात' ने अपनी निगाहें नहीं हटाईं। प्रत्येक सामाजिक समस्या की जड़ समाज के आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं में है, इस दृष्टिकोण से समस्याओं का विश्लेषण करते हुए 'प्रभात' ने सर्वहारा और जनवादी दृष्टिकोण से इनके हल भी दिखाए। चुण्डूर और खैरलांजी में तथाकथित अगड़ी जातियों द्वारा दलितों पर किए गए हमलों और कत्लेआमों की घटनाओं के संदर्भ में 'प्रभात' ने पाठकों का आह्वान किया कि इस नीचतापूर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ दलित और अन्य पिछड़े लोग मिलजुलकर संघर्ष करें। 6 दिसम्बर 1992 को उत्तरप्रदेश के अयोध्या स्थित बाबरी मसजिद को हिन्दू धार्मिक कट्टरपंथियों ने ढहा दिया था। इसका 'प्रभात' ने न सिर्फ खण्डन किया बल्कि उसी जगह पर मसजिद के पुनरनिर्माण की मांग कर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होकर सांझा संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया। 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिन्दू फासीवादियों द्वारा किए गए सामप्रदियक दंगों और कत्लेआम की निंदा करने में 'प्रभात' न सिर्फ आगे रही, हिन्दू फासीवाद के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ने की जरूरत पर जोर भी दिया। दरअसल इस देश को धर्मनिरपेक्ष कहना बिल्कुल गलत है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि चाहे बुर्जुआई या संशोधनवादी पार्टीयां जो भी सत्ता में रहे, भारत की सरकारें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिन्दू अनुकूल नीतियों को लागू करती हैं। इस देश की आबादी में 8 फीसदी का हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासियों को इरादतन हिन्दू बताना उसके हिन्दू अनुकूल नीतियों का एक और उदाहरण है। दण्डकारण्य के आदिवासियों को हिन्दू बताते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा अपनाई जा रही हिन्दू धर्मांतरण की नीतियों का मुकाबला करने में 'प्रभात' ने जनता का हौसला बढ़ाया। इन गलत नीतियों को गहराई से समझाने और दण्डकारण्य की जनता को सचेत करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली पत्रिकाओं में 'प्रभात' एक है। जब तक लुटेरे शासक वर्ग सत्ता में बने रहेंगे तब तक देश में वस्तविक धर्मनिरपेक्षता का लागू होना नामुमकिन है, यह कहते हुए 'प्रभात' ने शासक वर्गों चरित्र को बेनकाब किया।

'प्रभात' उत्पीड़ित जनता की पक्षधर है। उत्पीड़ित जनता के संघर्षों और जनता के आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों की लड़ाइयों को ऊंचा उठाकर उनके प्रति वह हमेशा सर्वहारा के दृष्टिकोण प्रस्तुत करती रही। पंजाबी राष्ट्रीयता के लोगों के न्यायपूर्ण संघर्षों का 'प्रभात' ने (1980 के दशक के आखिरी दौर में) पूर्ण समर्थन किया। श्रीलंका में लम्बे अरसे से जारी तमिल राष्ट्रीयता के लोगों की जायज लड़ाई और मांगों का 'प्रभात' समर्थन करते आ रही है। दुनिया के कई देशों में जारी क्रांतिकारी संघर्षों के प्रति 'प्रभात' ने न सिर्फ भाईचारा प्रकट की, बल्कि उनके संघर्षों की विशेषताओं से पाठकों को रूबरू करवाने की भी उसकी हमेशा कोशिश रही। खासकर हमारे पड़ोस में एक दशक से ज्यादा समय तक जारी महान जनयुद्ध की खबरों पर 'प्रभात' ने विशेष ध्यान देकर उन्हें पाठकों तक ले जाने का प्रयास किया। तुर्की, पेरू, फिलिप्पींस, आदि देशों में जारी माओवादी जनयुद्धों संबंधी खबरों को कभी-कभार ही सही, इकठ्ठा करके पाठकों तक लाने की कोशिश की।

1970 के दशक के बाद क्रांतिकारी राजनीति और क्रांतिकारी संघर्षों के केन्द्रों में से एक बनें आंध्रप्रदेश के सशस्त्र किसान आन्दोलन से जुड़ी खबरें दण्डकारण्य के पार्टी और पीएलजीए के कतारों और जनता तक पहुंचाने में 'प्रभात' ने खासा योगदान दिया। उन संघर्षों के अनुभवों के आधार पर ही यहां पर जन संघर्ष विजय पथ पर आगे बढ़ते रहे। एओबी, उत्तरी तेलंगाना, बिहार-झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, आदि राज्यों के क्रांतिकारी आंदोलन की रिपोर्टें भी कभी-कभार देने से संघर्षशील जनता के बीच भाईचारा पनपने में मदद मिली।

सम-सामयिक देशीय और अंतर्राष्ट्रीय मासलों पर लेखों के

लिये 'प्रभात' मुख्य रूप से केन्द्रीय पत्रिकाओं पर निर्भर कर रही है। वैनगॉर्ड, पीपुल्समार्च, आदि पत्रिकाओं से लेखों का अनुवाद कर 'प्रभात' ने अपने पाठकों के पास पहुंचाया। भारत सरकार और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप पार्टी की कई पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगने के कारण अन्य क्रांतिकारी पत्रिकाओं पर भी निर्भर कर रही है। सरकारी कानून के हिसाब से अघोषित रूप से प्रतिबंधित हमारी 'प्रभात' अनिवार्य रूप से गोपनीय तरीके से ही पाठकों के पास पहुंच रही है और क्रांति का संदेश जन-जन तक पहुंचा रही है।

दण्डकारण्य के जन संघर्षों को रोशनी में लाने पर सहज ही 'प्रभात' खासा ध्यान दे रही है। चूंकि यह इस इलाके से छपने वाला पार्टी का मुखपत्र है, इसलिए इस पर यह इसकी जिम्मेदारी भी है। दण्डकारण्य एक लम्बा-चौड़ा इलाका होने के कारण संघर्ष की खबरों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में 'प्रभात' एक मुख्य माध्यम के रूप में या यूं कहे कि संगठक के रूप में काम करते आ रही है। साथ ही, देश-विदेश की खबरों को दण्डकारण्य के पाठकों तक पहुंचाने और दण्डकारण्य की संघर्ष-खबरों को बाहर की जनता तक पहुंचाने में 'प्रभात' का खासा योगदान है। खासकर हमारे देश में उन्नत क्रांतिकारी कर्तव्य यानी आधार इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे इलाकों में से एक होने के कारण बाहर के पाठक सहज ही दण्डकारण्य की संघर्ष-खबरों के लिए बेसब्री से इंतजार में रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को यहां के तथ्यों से रूबरू करवाते हुए दण्डकारण्य के आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने में 'प्रभात' की भी भूमिका निभा रही है। बांस कटाई की मजदूरी, तेंदूपत्ता रेट को बढ़ाने और वनोपजों के उचित दाम के लिए दण्डकारण्य की जनता द्वारा किए जा रहे संघर्षों और अकाल से बचने के लिए अपनाए गए उपाय आदि 'प्रभात' के पुराने अंकों के पन्ने पलटने से ढेरों दिखाई देते हैं। संघर्षों की इन सारी खबरों को इकट्ठा करेंगे तो जन संघर्षों के स्तर और जनता की चेतना के स्तर में हो रहे विकास की एक तस्वीर मिल जाती है। इन संघर्षों के अलावा इतिहास में दण्डकारण्य में हुए जन विद्रोहों के बारे में भी 'प्रभात' ने करीब तीन साल तक सिलसिलेवार ढंग से प्रकाशित किया था। 1825 से लेकर 1910 तक दण्डकारण्य की आदिवासी जनता ने किस प्रकार ब्रितानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ बगावतें कीं, इसका 'प्रभात' ने रिकॉर्ड (दस्तावेजित) किया। अतीत के इतिहास को समझने में 'प्रभात' के इन प्रयासों से वर्तमान में संघर्षरत लोगों को काफी मदद मिली।

दण्डकारण्य में हर साल मनाए जाने वाले क्रांतिकारी दिवसों की खबरें 'प्रभात' अपने पाठकों को नियमित रूप दे रही है। 10 फरवरी - भूमकाल दिवस, 8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मई दिवस, 28 जुलाई - शहीद सप्ताह, 21 सितम्बर - पार्टी का स्थापना दिवस, 2 दिसम्बर - पीएलजीए का स्थापना दिवस आदि महत्वपूर्ण दिनों को यहां पर पार्टी और क्रांतिकारी जनता द्वारा हर साल मनाया जाता है। शुरू से पार्टी के 'चुनाव बहिष्कार' के आह्वान और बुर्जुवाई और संशोधनवादियों की तिकड़मबाजी को जनता के सामने रखने में 'प्रभात' का बड़ा योगदान रहा। बुर्जवाई पार्टियों के चरित्र और चुनाव के तौर-तरीकों का विश्लेषण करते हुए 'प्रभात' ने कई बार लेख प्रकाशित किए। जनता के सामने 'प्रभात' ने स्पष्टपूर्वक यह बात रखी कि ये चुनाव कतई जनवादी नहीं हैं और इन ढोंगी चुनावों का बहिष्कार करना चाहिये और इसके विकल्प में जनता को अपनी जन सरकारों का चुनाव करना चाहिए।

खासकर पिछले दो सालों से बढ़ रही जनता और जन सैनिकों की प्रतिरोधी कार्रवाइयों को भी 'प्रभात' ऊंचा उठाती आ रही है। पार्टी की एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस ने पार्टी का केन्द्रीय कार्यभार यह निर्धारित किया कि 'दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड को आधार इलाकों में बदल दें और गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में तथा पीएलजीए को पीएलए में विकसित करें।' इस कार्यभार को पूरा करने की दिशा में दण्डकारण्य में बढ़ रहे जनयुद्ध की खबरों को इकट्ठा कर पाठकों तक पहुंचाने पर 'प्रभात' पूरा ध्यान दे रही है। आज यह दरअसल इस पत्रिका का मुख्य कर्तव्य भी है। विभिन्न मौकों पर पीएलजीए द्वारा चलाए जा रहे टीसीओसी (कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों) और अन्य सैन्य प्रतिरोध की खबरों को इकट्ठा कर फौज और युद्ध में आ रहे गुणात्मक बदलावों पर विश्लेषणात्मक लेखों के प्रकाशन करने की जरूरत अब पहले के मुकाबले बढ़ी है।

'प्रभात' में इस्तेमाल की जा रही हिन्दी भाषा को सुधारने में पाठकों के सलाह-सुझावों से काफी मदद मिली है। पाठकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए लेखों का चयन करने के सुझाव पर अमल करते हुए 'प्रभात' ने लोकप्रियता हासिल की। एक आदिवासी इलाके से छपने वाली इस पत्रिका ने अगर आदिवासियों के ऐतिहासिक जन संघर्षों, जन संस्कृति और जनता की भाषा को रोशनी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं तो उसका श्रेय पाठकों को ही जाता है।

एक पत्रिका के रूप में इसके प्रकाशन के साथ-साथ इसने इन 20 सालों में क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरतों के अनुसार कई किताबों का भी प्रकाशन किया। कुछ मुख्य मुद्दों को पार्टी कतारों और जनता में विस्तृत और समग्र रूप से ले जाने के लिए यह जरूरी भी था। इन 27 सालों में दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन में शहीद हुए वीर योद्धाओं की जीवनियों के कई संकलन प्रकाशित किए गए। इसके जरिए 'प्रभात' ने शहीदों के उन्नत आदर्शों को जनता में व्यापक रूप से प्रचारित किया। बस्तर के जन विद्रोहों का संकलन करके एक किताब प्रकाशित की गई। चुनाव बहिष्कार, विस्थापन, सलवा जुडूम, आदि कई मुद्दों पर 'प्रभात प्रकाशन' की तरफ से किताबें प्रकाशित हुईं।

'प्रभात' की प्रेरणा से दण्डकारण्य में कुछ अन्य पत्रिकाएं भी शुरू हुईं। उनमें खासकर 'संघर्षरत महिला' और 'झंकार' के नाम लिए जा सकते हैं। आज दण्डकारण्य के लगभग सभी डिवीजनों में स्थानीय गोण्डी (कोया) भाषा में विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन सारी पत्रिकाओं के लिए 'प्रभात' न सिर्फ प्रेरणा का स्रोत रही, बल्कि खबरों और रिपोर्टों का स्रोत है।

20 सालों का सफर तय करने के बावजूद यह पत्रिका अभी भी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। खासकर 'प्रभात' को संघर्ष के मैदानों से (दण्डकारण्य के विभिन्न

डिवीजनों से) समय पर रिपोर्टें और स्थानीय मुद्दों पर लेख नहीं पहुंच रहे हैं। यह कमी पत्रिका में साफ तौर पर दिखती है। इसके अलावा यह पत्रिका अनुवादकों की कमी की समस्या से बुरी तरह परेशान है। परिणामस्वरूप करीब 8 सालों तक तेलुगु में भी जारी 'प्रभात' का प्रकाशन 2005 में रुक गया। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि मार्च 2006 के बाद करीब एक साल तक 'प्रभात' लगभग रुक सी गई। यह दरअसल महत्वपूर्ण दौर था जब दण्डकारण्य के क्रांतिकारी जनयुद्ध में एक जबर्दस्त मोड़ आया था। इसी दौर में 'प्रभात' का प्रकाशन रुक सा जाना चिंता का विषय है। पत्रिका स्टाफ की कमी की समस्या से भी जूझ रही है। इससे भी इसके नियमित प्रकाशन के रास्ते में कई रूकावटें आ रही हैं। आशा करेंगे कि 'प्रभात' इन सभी कमियों और कमजोरियों से उबरते हुए आगे बढ़े।

'प्रभात' के सामने अब मुख्य चुनौती यह है कि दण्डकारण्य में दुश्मन के घेराव-दमन के हमले तेज हुए हैं। इस इलाके में तैनात 30 हजार से ज्यादा सरकारी सशस्त्र बल क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के षड़यंत्र के तहत 'प्रभात' के कार्यालय को भी ध्वस्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। केन्द्र-राज्य सरकारें भारतीय सेना या सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती की चेतावनियां दे रही हैं। इन सबके बीच ही 'प्रभात' के प्रकाशन को जारी रखना है। किसी भी आंदोलन के लिए पत्रिका एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे कितना दमन आए, दुश्मन के घेराव-दमन के हमले चाहे कितने तीखे हों, पर यह पत्रिका जनता पर आधारित होकर और पीएलजीए बलों की सुरक्षा में जरूर छपती रहेगी। हमेशा की तरह वह क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरतों की पूर्ति करते हुए बुलंदियां छूती रहेगी.... इन्हीं आशाओं और आंकाक्षाओं के साथ फिर एक बार 'प्रभात' का लाल-लाल अभिनंदन करते हैं।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (माओवादी)

दण्डकारण्य के 'प्रभात' का 'क्रांति'कारी अभिनन्दन!

अपने 20 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में 'प्रभात' का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। आमतौर पर एक पत्रिका के 20 साल पूरे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज देश में व्याप्त तीव्र दमनात्मक हालात में एक 'गुप्त' पत्रिका के 20 बरस पूरे हो जाना निश्चित रूप से विशेष महत्व का है। और पाशविक 'सलवा जुडूम' दमनकाण्ड का मुकाबला करते हुए ही 'प्रभात' का आगे बढ़ना और ज्यादा अहमियत रखता है।

इन 20 सालों के सफर में 'प्रभात' ने कितनी मुश्किलों और समस्याओं का सामना किया होगा और अभी भी कर रही होगी, हम समझ सकते हैं। अभी तक हमारी पार्टी का अनुभव पूरा शहरों में ही, जहां सूचना व्यवस्था और आधुनिक मशीनें उपलब्ध रहती हैं, पत्रिकाओं को चलाने का रहा है। लेकिन 'प्रभात' लगभग दस सालों से जंगल के अंदर से ही चलती आ रही है जिससे पार्टी को एक नया और अनमोल अनुभव मिला है। 'आधुनिक' दुनिया से दूर रहकर सूचनाओं और आधुनिक मशीनों को हासिल करने में 'प्रभात' को हो रही मुश्किलों में हम उसके साथ खड़े हैं। भाषा के मामले में भी 'प्रभात' को जो समस्या पेश आई वह कोई छोटी-मोटी नहीं थी, और हम समझते हैं कि इस समस्या को धीरे-धीरे पार करते हुए 'प्रभात' ने काफी प्रगति हासिल की।

ऐसी जगह पर शुरू करके जहां कुछ भी नहीं था, अभी भी सीमित संसाधनों के बल पर चलते हुए 'प्रभात' काडरों और जनता की चेतना बढ़ाने तथा मध्य भारत में क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार-प्रसार करने में विशेष योगदान कर रही है। लेनिन के बताए अनुसार एक संगठक की भूमिका निभाते हुए, सैद्धांतिक व राजनीतिक समझदारी को फैलाते हुए, संघर्ष की खबरों और देश भर में शहीद हुए हमारी पार्टी के कॉमरेडों की जीवनियां प्रकाशित करते हुए, कई अन्य प्रकाशनों से भी राजनीतिक कार्य कर काडरों और जनता को प्रेरणा दे रही 'प्रभात' का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। दमनकारी सलवा जुडूम के बीच भी इस पत्रिका का न रुकना, बल्कि सलवा जुडूम का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और सलवा जुडूम के खिलाफ कई प्रकाशन कर राजनीतिक रूप से उसे नंगा करने में 'प्रभात' ने जो भूमिका निभाई वह सराहनीय है।

बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी अगर 'प्रभात' आगे बढ़ रही है तो उसे जनता से प्राप्त हो रहे सहयोग और समर्थन का हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम समझते हैं कि दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के जनता से मिल रहे इस समर्थन और सहयोग के पीछे 'प्रभात' की भी भूमिका है।

आखिर में, 'क्रांति' के भी इस अक्टूबर के साथ 30 बरस पूरे हुए। आज आंध्रप्रदेश में व्याप्त तीखे दमन के हालात में 'क्रांति' भी कई मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में 'क्रांति' की प्रेरणा से शुरू होने वाली 'प्रभात' आज न सिर्फ 'क्रांति' को प्रेरणा दे रही है, बल्कि हार्दिक रूप से मदद भी दे रही है। इस प्रकार 'प्रभात' के साथ हमारा रिश्ता भावनात्मक और घनिष्ठ है।

हम तहेदिल से कामना करते हैं कि दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन में सुचारू भूमिका निभा रही 'प्रभात' अपनी तमाम समस्याओं को पार करते हुए और ज्यादा शक्तिशाली बने तथा न सिर्फ दण्डकारण्य, बल्कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियों में अपनी भूमिका सक्रियता से अदा करे।

- 'क्रांति' का सम्पादक मण्डल

आंध्रप्रदेश

'प्रभात' की 20वीं वर्षगांठ पर अभिनन्दन

साहित्य समाज का प्रबोधन करता है। जन साहित्य सीधा वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब होता है। अर्ध सामंती-अर्ध औपनिवेशिक भारतीय समाज में गांधीवादी, संशोधनवादी साहित्य खुद को पुरोगामी कहलाते रहे हैं, पर वास्तविकता में वे जनता के जीवन में अंधेरा फैलाते रहे हैं। ऐसे में 'प्रभात' जनयुद्ध की रोशनी लेकर जनता के बीच जा रही है। वास्तव में यह नव जनवादी सूरज का उष:काल है, जो सामंती-साम्राज्यवादी शोषण की जंजीरें पिघला डालेगा।

यह दण्डकारण्य के उस क्रांतिकारी दावनाल का दर्पण है जिसने भारत की नवजनवादी क्रांति द्वारा स्थापित होने वाली जनसत्ता को किताबों से निकालकर दण्डकारण्य में हकीकत में बदल दिया है। यह महान शहीदों के बलिदानों से साकार हुआ है। यह शहीदों का खून ही है जो स्याही बनकर 'प्रभात' के पन्नों पर न सिर्फ प्रिंट हो रहा है, बल्कि उन मुद्रित अक्षरों द्वारा क्रांति की चेतना बन कर लाखों लोगों के मस्तिकों में दौड़ रहा है। और निरंतर सफर में है, जिसका आंकलन करना सत्ताधारी वर्ग के बस की बात नहीं है।

अब इस चेतना से करोड़ों लोग वर्तमान में जारी जनयुद्ध में कूद पड़ेंगे, पीएलजीए को पीएलए में बदलने, गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करने, गुरिल्ला जोन को आधार इलाके में विकसित करने और भारत को नव जनवादी भारत में बदलने।

'प्रभात' 20 साल की हुई। जैसे-जैसे जनयुद्ध का विकास हो रहा है वैसे-वैसे 'प्रभात' भी निखरती रही है। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 'प्रभात' का वो अंक निश्चित निकलेगा जिसके पहले पन्ने पर लिखा होगा "भारत की जनता ने लाल किले पर लाल झण्डा लहराया!" और "भारत में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजिवाद और सामंतवाद का खात्मा!"

मैं 'प्रभात' की इस 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर तमाम 'प्रभात'कारों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुये 'प्रभात' चिरायु होवे, ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं।

कॉमरेड उज्जवल

महाराष्ट्र राज्य कमेटी

भाकपा (माओवादी)

सलवा जुडूम के खिलाफ जारी जन प्रतिरोध के मोर्चे से एक पीएलजीए कमाण्डर का बधाई संदेश

प्रिय कॉमरेडो,

'प्रभात' का सफर दो दशकों से लगातार जारी है। इन बीस सालों में वह सर्वहारा के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न राजनीतिक-सैद्धांतिक मुद्दों पर अपनी नीति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखती रही है। वह उत्पीड़ित-शोषित जनता की पक्षधरता के साथ न सिर्फ दण्डकारण्य में, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के क्रांतिकारी कतारों में लोकप्रिय बन गई। इस पत्रिका का गला घोटने के लिए शोषक शासक वर्ग कई साजिशें और षड़यंत्र रच रहे हैं। इन सबका मुकाबला करते हुए और विभिन्न बाधाओं को लांघते हुए 'प्रभात' का सफर अविराम जारी है। दण्डकारण्य के पार्टी काडरों, पीएलजीए योद्धाओं और क्रांतिकारी जन समुदायों की राजनीतिक चेतना और सैद्धांतिक दृढ़ता बढ़ाने में 'प्रभात' का भी अपना योगदान रहा है।

जबसे सलवा जुडूम शुरू हुआ तब से 'प्रभात' अपने लेखों व रिपोर्टों के जरिए उसकी पाशविकता और बर्बरता का पर्दाफाश करने में आगे रही। मानवता को शर्मशार करने वाली शासकों के कत्लेआमों का खुलासा कर जनता के सामने प्रतिरोध का रास्ता स्थापित करने में 'प्रभात' ने अपनी भूमिका बखूबी से निभाई। जुडूम की शुरूआत से लेकर अब तक निकले सभी अंकों में लगातार कई लेख, शहीदों की सूचियां और उनके आदर्श दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं। शहीदों की जीवनियों का प्रकाशन कर उनकी कुरबानियों को 'प्रभात' ने हमेशा ऊंचा उठाए रखा। सलवा जुडूम के आतंकी चेहरे को व्यापक जनता के सामने नंगा करने के लक्ष्य से 'प्रभात' ने अब तक तीन प्रचार पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं जिससे हजारों लोगों तक न केवल पार्टी का राजनीतिक संदेश पहुंचा, बल्कि संघर्षरत जनता का हौसला भी बढ़ा।

मैं आशा करता हूं कि हमारी यह 'प्रभात' इसी प्रकार आगे-आगे बढ़े। शुरू से लेकर अभी तक इस पत्रिका में काम कर चुके और कर रहे संपादकों, स्टाफ कॉमरेडों और तकनीकी रूप से जुड़े हुए अन्य तमाम कॉमरेडों को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं। इस पत्रिका के सुचारू संचालन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही क्रांतिकारी जनता, जन संगठनों के कॉमरेडों और जन मिलिशिया के योद्धाओं को भी मैं इस उपलक्ष्य में अपना हार्दिक लाल अभिनन्दन पेश करता हूं।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

कॉमरेड एन.

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ-साथ प्रगति पर 'प्रभात'

'प्रभात' के 20 साल पूरे होने के अवसर पर 'प्रभात' की संस्थापक-संपादक कॉमरेड नर्मदा का संदेश

इलाकेवार राजसत्ता का दखल के लक्ष्य से 1980 में दण्डकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हुआ। इस क्षेत्र को लाल प्रतिरोध ी इलाके से गुरिल्ला जोन में बदलने के प्रयास चल रहे थे। एक-एक दस्ते के रूप में विस्तार करते हुए छोटे-छोटे इलाकों से व्यापक इलाकों में बढ़ते हुए तथा विभिन्न डिवीजनों में यह आंदोलन एक समग्र आकार ले रहा था। इस व्यापक इलाके के आंदोलन को तालमेल के साथ आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की फॉरेस्ट कमेटी का गठन किया गया था जो उस समय आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी के अधीन थी। उस कमेटी ने दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन की खबरों को व्यापक जन समुदायों के बीच ले जाने की जरूरत महसूस कर इसके लिए एक पत्रिका शुरू करने का फैसला लिया। लेकिन उसके लिए आवश्यक स्टाफ, छपाई का ढांचा, बंटवारे की व्यवस्था कुछ भी नहीं था। दण्डकारण्य की जनता की बोलचाल की भाषा गोंडी है। पूर्व गोदावरी से लेकर बस्तर, गड़चिरोली, आदिलाबाद तक फैले हुए दण्डकारण्य के क्षेत्र में आंदोलन के विस्तार के राजनीतिक महत्व को देखते हुए पार्टी ने इसे हिन्दी में लाने का निर्णय लिया। तब तक हिन्दी भाषी इलाकों में हमारे संपर्क बहुत कम थे। डीके में उसके लिए आवश्यक आत्मगत ताकतों की कमी थी। पत्रिका की शुरूआत कहां से की जाए? फॉरेस्ट कमेटी की समझ यह थी कि अगर दो साल तक आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी खुद इसे चलाएगी तो बाद में वह उसकी जिम्मेदारी ले लेगी। इससे अनुवाद और छपाई की जिम्मेदारी कॉमरेड सुब्बन्ना जी को सौम्प दी गई थी जो उस समय हिन्दी शिक्षक के रूप में काम करके सेवानिवृत्त हो चुके थे।

'प्रभात' के 20 बरस पूरे होने की बात सोचती हूं तो ऐसा लगता है कि कितना जल्द पूरे हुए। कई बाधाओं को झेलकर भी गंभीरता से आगे बढ़ रही 'प्रभात' को मेरा क्रांतिकारी अभिनन्दन! इस मौके पर मैं 1987 के शुरूआती अंक से लेकर 1994 तक के, जब वह शहरों से प्रकाशित होती रही जो कि दुश्मन के अड्डे हैं, 'प्रभात' के सफरनामे के विभिन्न पड़ावों व मंजिलों और उस दौरान आई रुकावटों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी।

शुरूआत से लेकर 1992 तक पत्रिका के स्टाफ, सम्पादक और कामकाज देखने वाले सब मिलाकर फील्ड में रहने वाले प्रभारी कॉमरेड को छोड़कर तीन ही व्यक्ति थे। इन तीनों में कॉमरेड सुब्बन्ना जी की सेवाओं को 'प्रभात' की 20वीं वर्षगांठ के इस मौके पर जरूर याद करना चाहिए। वे हमेशा पत्रिका को समय पर निकालने की तत्परता से अपने हिस्से का लेखन-कार्य तय समय पर पूरा किया करते थे। अपनी बड़ी उम्र और खराब स्वास्थ्य की परवाह बिल्कुल न करते हुए 'प्रभात' के लिए परिश्रम करते थे। हिन्दी भाषा की शैली को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।

शुरूआती दिनों में 'प्रभात' सैद्धांतिक और अन्य लेखों के लिए 'क्रांति' पर ही निर्भर करती थी। इस तरह वह देश-दुनिया के राजनीतिक हालात पर और राजनीतिक महत्व की घटनाओं पर समय-समय पर स्पष्ट समझदारी पाठकों तक ले जाने में सफल रहती थी। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कुर्द-बाल्टिक गणराज्यों तक सभी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को 'प्रभात' ने ऊंचा उठाए रखा। इराक पर अमेरिकी हमले (खाड़ी युद्ध) का खण्डन करते हुए इसने लेख प्रकाशित किए। मानवाधिकार आंदोलनों पर हमलों और केन सारो विवा को दी गई फांसी की 'प्रभात' ने निंदा की। 1992 में जब हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था, तब 'प्रभात' ने उसके विरोध में लेख प्रकाशित कर अल्पसंख्यक मुसलमानों प्रति हमदर्दी जताई।

साहित्य के दृष्टिकोण से कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन देते हुए 'प्रभात' ने कविताओं के लिए एक पन्ना छोड़ा। संघर्ष के क्षेत्रों से गुरिल्ला लेखकों को प्रोत्साहन देते हुए कई लघुकथाएं प्रकाशित कीं। हर अंक में सैद्धांतिक लेख अनिवार्य रूप से छापा जाता था।

भण्डारा में बांस की टोकरियां बनाकर उसी पर आजीविका चलाने वाले 'बुराड' समुदाय की जनता द्वारा मजदूरी बढ़वाने के लिए किए गए संघर्ष का 'प्रभात' ने समर्थन किया। रावघाट-कुव्वेमारी खदानों के खिलाफ कांकेर में हुए 25 हजार जनता के प्रदर्शन को 'प्रभात' ने ऊंचा उठाया। महिलाओं पर राजकीय हिंसा का 'प्रभात' ने खिलाफत की। बेवरटोला में 4 युवतियों को लापता करने, गर्दापल्ली में 5 महिलाओं के साथ पुलिस के सामूहिक बलात्कार, हर्राकोडेर में रामसिंग की पुलिस के हाथों पीट-पीटकर हत्या, आदि अमानवीय कारनामों का 'प्रभात' ने पर्दाफाश किया। गर्भवती सुकड़ी बाई के साथ बलात्कार करने वाले दोषी पुलिस वालों को सजा देने की मांग की।

बस्तर में पहला जन जागरण अभियान और उसका नेतृत्व करने वाले आदिवासी सामंतों, खासकर सामंती सरगना महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में बस्तर की संघर्षशील जनता के खिलाफ चलाए गए फासीवादी हमले का विरोध किया। उसी समय गड़चिरोली में 'शांतसेना' के नाम से सामने आए प्रतिक्रियावादी बीरा वरसे के सफाए का 'प्रभात' ने पूरा समर्थन किया। अपने प्रतिरोधी संघर्ष के बल पर पहले जन जागरण अभियान को हराने वाली बस्तर की जनता का 'प्रभात' ने अभिनन्दन किया।

संघर्ष के इलाकों से 'प्रभात' को नियमित रूप से रिपोर्टें आती थीं। पाठक 'प्रभात' में छपने वाली हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़कर अपने विचार लिख भेजते थे। भाषा के संबंध में भी कई सुझाव देते हुए चिट्ठियां लिखते थे। उन्हें पसंद आई रिपोर्टों के बारे में भी लिखते थे।

साम्राज्यवादियों की आर्थिक लूटपाट के खिलाफ मैक्सिको के जपातिस्ता गुरिल्लों के संघर्ष का 'प्रभात' ने समर्थन किया। अफ्रीका के सोमालिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में काम्बोडिया की जनता के वीरतापूर्ण संघर्षों के प्रति 'प्रभात' ने भाईचारा प्रकट किया।

उपरोक्त सभी बातें लेखन से संबंधित हैं। आइए, प्रूफ रीडिंग और छपाई के कामों पर नजर डालें -

तब तक आंध्र में पत्रिकाओं पर आघोषित प्रतिबंध और प्रिंटिंग प्रेसों पर निगरानी-हमले शुरू हो चुके थे। 1985 तक कानूनी रूप से प्रकाशित होती रही 'क्रांति' भूमिगत हो चुकी थी। विजयवाड़ा में प्रेसों पर खुफिया विभाग की निगरानी बढ़ चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालात में 'प्रभात' का पहला अंक गुंटूर के एक प्रेस में छापा गया था। हिन्दी से पूरी तरह अछूते रहे तेलुगु इलाके में दण्डकारण्य की हिन्दी पत्रिका का कम्पोजिंग! छपाई की गलतियों के बारे में पूछने का मौका तक नहीं था किसी को। छपवाकर देना ही बड़ी बात थी! तब तक पत्रिका के काम के लिए चुने हुए संपादकों या यूं कहें कि अनुवादकों की भाषा भी तेलुगु से प्रभावित किताबी हिन्दी थी। उन्हें इलाकों में जारी संघर्षों से कोई परिचय नहीं था। तेन्दुपत्ता संघर्ष में 'गुल्ला कट्टालु' का हिन्दी शब्द हम नहीं समझ पाए थे। उस जगह पर हमने खाली छोड़ा था। उसे वैसे ही छापा गया था, सुधारा नहीं जा सका। शुरू में सालाना दो अंक लाने का फैसला तो था, पर जहां तक मुझे याद है दो सालों में बड़ी मुश्किल से हम तीन अंक ही ला पाए थे। बाद में इसे तिमाही बनाया गया। पत्रिका के अनुवादकों में एक आंध्र में तो दूसरा तमिलनाडू में रहते थे। इससे तालमेल में तो समस्या थी ही पर इससे बड़ी समस्या उसकी छपाई की थी। मैंने हिन्दी टाइपिंग सीखना शुरू किया। इंस्टिट्यूट में तीन घण्टे टाइप कर 'प्रभात' का मैटर कॉलम साइज में लम्बाई में टाइप कर लाती थी और हम उसे छिपकाकर ऑफसेट के लिए तैयार करते थे। शीर्षक

डीटीपी/फोटाटाइप के लोगों के पास जाकर बनवाते थे। नेगिटिवों को रिडक्शन से कम करवाकर ऑफसेट के लिए प्लेट बनवाते थे। चूंकि सादी टाइपिंग थी इसलिए लेटर प्रेस के अक्षरों की तरह छोटे नहीं होते थे, इसलिए 'प्रभात' की साइज से डेढ़ गुना ज्यादा साइज में पेज तैयार करवाकर रिडक्शन करवाना पड़ता था। सादा टाइपिंग, रिडक्शन और ऑफसेट प्रिंटिंग में पहला अंक शिवकाशी से 16 पन्नों का निकला था। इस तरह लेटर प्रेस से ऑफसेट मेकानिज्म में 'प्रभात' ने कदम रखा। शुरू में टाइप सेटिंग मशीनें हुआ करती थीं। फोटो पेपर पर प्रिन्टाउट देते थे जिन्हें 'ब्रोमाइड' कहा करते थे। उनके लिए वर्ग इंचों के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। टाइप सेटिंग मद्रास में दो जगहों पर ही था। वहां हिन्दी ऑपरेटरों की कमी थी। टाइप सेटिंग मशीन पर हिन्दी टाइपिंग सीखने के लिए नौकरी के नाम से उसमें ज्वाइन करना पड़ा था मुझे। इस बीच एक और टाइप सेटिंग वालों का परिचय मिला। दिन में उनका जॉब वर्क चलता था। रात में जाकर हिन्दी टाइपिंग करने का मौका दिया। चूंकि हम खुद टाइप करते थे इसलिए भुगतान में आधा पैसा कम करके लेते थे। टाइप सेटिंग और ऑफसेट से छपने वाली 'प्रभात' का स्थान शिवकाशी से मद्रास के एक क्रिश्चियन प्रेस में बदला जहां पर एक साथ 16 पेज छाप सकने वाली वेब मशीन की सुविधा थी। दुश्मन की निगरानी को भेदते हुए वह दण्डक वनों में पाठकों के पास पहुंच पाती थी।

1990 के आखिर से 'प्रभात' का मुकाम भोपाल बदला। भोपाल, पूणे और नागपुर में बदल-बदलकर वह 1992 तक चलती रही। बाद में इस नतीजे पर पहुंच गए कि अपना खुद का ढांचा तैयार किए बिना इसका संचालन मुश्किल है। बेबी ऑफसेट और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जुटाए गए। तब भी टाइप किए हुए मैटर को मास्टर पर उतारने की समस्या रह गई थी। डेस्क टॉप प्रिंटिंग के कारण आईबीएम कंप्यूटरों का दौर चल पड़ा। उसके पहले कटिंग-पेस्टिंग से पेज मेकप और हिन्दी पत्रिकाओं में छपने वाले अक्षरों को काटकर शीर्षक बनाने पड़ते थे। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए तलाशी के दौरान डीटीपी, बेबी ऑफसेट से लैस प्रेस वालों से परिचय हुआ जिससे 'प्रभात' नागपुर में ही छपती रही। एक-दो किताबें भी वहीं छप गईं। लेकिन नागपुर में 'प्रभात' से जुड़े एक-दो कॉमरेडों के साथ-साथ पार्टी के कुछ अन्य कॉमरेडों की गिरफ्तारियों से 1992 में 'प्रभात' रुक गई। फिर 1994 में ही संघर्ष के इलाके से 'प्रभात' का पुन:प्रकाशन शुरू हुआ। जून 1994 में जंगल में पहुंची 'प्रभात' आधुनिक मशीनों की बजाए फिर से टाइप मशीन और साइक्लोस्टाइल के दौर में चली गई। 1997 में फिर कंप्यूटर, जिरॉक्स मशीन से प्रयोग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग की कोशिशें.... इस तरह 'प्रभात' कई प्रकार के बचकाना मर्जों से उबरकर अब जाकर पटरी पर आई है! क्रांतिकारी आंदोलन ने उसे जो कार्यभार सौंपा उसे पूरा करते आगे बढ़ रही है।

1995 में 22 अप्रैल लेनिन के जन्मदिन के अवसर पर 'प्रभात' का पहला तेलुगु अंक निकला था। 2005 तक उसका तेलुगु प्रकाशन भी नियमित चलता रहा। आत्मगत ताकतों की कमी के कारण तेलुगु में रुक गया। आंध्रप्रदेश से अलग होकर ज्यों-ज्यों दण्डकारण्य का क्रांतिकारी आंदोलन एक स्पेशल जोन की हैसियत से आगे बढ़ता जा रहा है, उसके साथ-साथ 'प्रभात' भी आगे बढ़ती जा रही है। लेनिन के बताए मुताबिक 'पत्रिका संगठक है' को वह अपने व्यवहार में साबित कर रही है। ★

भाकपा (माओवादी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सत्तेन्ना और कॉमरेड सुगुणा की गिरफ्तारी की निंदा करो!

आंध्रप्रदेश की बदनाम एसआईबी ने पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य और दक्षिण-पश्चिम रीजनल ब्यूरो के सचिव कॉमरेड सत्तेन्ना और उनकी जीवन-साथी कॉमरेड सुगुणा को 17 दिसम्बर को केरलम के अंगामाली के भीड़ भरे बाजार में गिरफ्तार किया। पार्टी के नेतृत्व का सफाया कर क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से उन्मूलन करने के इरादे से लुटेरे शासक वर्गों ने देश भर में प्रति-क्रांतिकारी सफाया अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत ही पिछले साल दिसम्बर में कॉमरेड बीके और जून 2007 में कॉमरेड प्रसाद की झूठी मुठभेड़ों में हत्या कर दी गई। केन्द्रीय कमेटी के अन्य सदस्य कॉमरेड सुनिर्मल और कॉमरेड मोहित को गिरफ्तार कर क्रूर यातनाएं देकर जेलों में बंद रखा गया है। कॉमरेड सत्तेन्ना की भी इसी प्रकार हत्या करने की मंशा से ही एसआईबी ने एक सोची-समझी साजिश के तहत पकड़ लिया। लेकिन पुलिस के हाथों पड़ते ही कॉमरेड सुगुणा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 'किडनैप-किडनैप' का शोर मचाया। इससे आसपास के लोग इकट्ठे हुए और सादे कपड़ों में आए एसआईबी के हत्यारों को घेर लिया। उन्होंने अपने पहचान-पत्र लहराकर लोगों को चुप कराने की कोशिश की पर लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। स्थानीय पुलिस वाले आ गए। उन्होंने हमारे कॉमरेडों को अपने कब्जे में लिया और कुछ ही घण्टों में मलयालम की टीवी चैनलों के जरिए यह खबर फैल गई कि कॉमरेड सत्तेन्ना और कॉमरेड सुगुणा की गिरफ्तारी हुई है। इससे इन कॉमरेडों की हत्या करने की एसआईबी की साजिश नाकाम हुई।

कॉमरेड सत्तेन्ना और सुगुणा को अगले दिन केरलम की स्थानीय अदालत में पेश करना पड़ा। केरलम और आंध्रप्रदेश की अदालतों में जब इन्हें पेश किया गया, तो इन कॉमरेडों ने क्रांतिकारी नारे लगाकर ऐलान किया कि वे क्रांतिकारी हैं और देश में क्रांति के जरिए वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था को हटाकर नई जनवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। खासकर जब सत्तेन्ना को मंथनी और मेटपल्ली की अदालतों में लाया गया, उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम ही निकल पड़ा जो हमारे कॉमरेडों के साथ नारे लगाते रहे।

कॉमरेड सत्तेन्ना 1970 के तूफानी दशक में आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले में क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने वाले वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हैं। उन्होंने 1980 में दण्डकारण्य में कदम रखकर क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। वे दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माताओं में से एक हैं। दण्डकारण्य में गठित पहली फॉरेस्ट कमेटी के वे सचिव थे। उनकी गिरफ्तारी हमारे लिए बड़ा नुकसान है। अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही 'प्रभात' के लिए यह बेहद दुखद खबर है क्योंकि उन्हीं की अगुवाई वाली दण्डकारण्य की फॉरेस्ट कमेटी ने 'प्रभात' को शुरू किया। लेकिन 'प्रभात' को पूरा यकीन है कि जेल की दीवारें इस मंजे हुए कम्युनिस्ट नेता को नहीं झुका सकेंगी और क्रांतिकारी जनता व जन सैनिक किसी दिन उन्हें जरूर जेल से बाहर निकाल लाएंगे। ★

'प्रभात' के 20 साल पूरे होने के अवसर पर एक पाठक का संदेश

'प्रभात' का प्रकाशन 1987 से शुरू हुआ। 1992 से मैं इसका नियमित पाठक बना। इसके पहले भी मुझे 2-3 प्रतियों को पढ़ने का अवसर मिला था। पहली बार जब 'प्रभात' की प्रति मिली थी तब मेरे जेहन में यही विचार आया था कि अन्य राजनीतिक पत्रिकाओं की तरह 'प्रभात' भी 4-5 अंकों के बाद अनेकों समस्याओं का रोना रोते हुये चिर निद्रा में चला जायेगी। या फिर समस्याओं से घिरी 'प्रभात' दम तोड़ देगी। लेकिन यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 'प्रभात' ने मेरी पूर्वग्रस्त धारणा को ध्वस्त करके रख दिया है। अनेकों समस्याओं, बाधाओं को लांघती हुई, दण्डकारण्य के आन्दोलन की तरह आगे बढ़ती ही गई-चमकती ही गयी आकाश में सूरज की तरह।

शुरुआती 'प्रभात' अपनी अंतरवस्तु में मजबूत, लेकिन भाषा, आकार-प्रकार, चेहरे-मोहरे में अव्यवस्थित थी... लेकिन विषय पर स्पष्टता, सहजता और भविष्य के दण्डकारण्य संघर्ष की झलक सभी का मन मोह लेती थी और बिना पढ़े चैन भी नहीं मिलता था। ठीक धूल में सने बालक की तरह जिसे उठाकर चूम लेने का कोई भी राही लोभ नहीं छोड़ सकता।

....'प्रभात' का संपादन और लेखन जहां गैर-हिन्दी भाषियों के हाथों होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी मजबूती भी यही थी। गैर-हिन्दी भाषी कॉमरेडों ने 'प्रभात' की अहमियत को न सिर्फ समझा, बल्कि उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिये जी-जान लगा दी। सम्पादकमण्डल और अनुवादक साथी इस मामले में क्रांतिकारी अभिवादन के पात्र हैं जिन्होंने भाषा के हिसाब से भी 'प्रभात' को ऊपर उठा दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, जिम्मेदारी के प्रति समर्पण की भावना, दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आन्दोलन में हिन्दी में राजनीतिक पत्रिका के महत्व को दिल की गहराइयों से समझने के पहलू ने 'प्रभात' को आज इस ऊंचाई पर ला खड़ा कर दिया...

'प्रभात' ने भाषा के मामले में न केवल स्वयं का विकास किया है बल्कि दण्डकारण्य में कार्यरत कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों और गुरिल्ला साथियों के हिन्दी भाषा के ज्ञान को उन्नत बनाया है। युद्ध के मैदानों से 'प्रभात' को भेजी जा रही रपटों से यही सिद्ध होता है।

....'प्रभात' ने अन्तर्राष्ट्रीय, देशीय तथा संघर्षरत इलाकों की खबरें सम-समयिक रूप से छपती रही है। साथ में सैद्धान्तिक व राजनैतिक लेखों नें 'प्रभात' की गंभीरता को बनाये रखा। जहां तक मुझे याद है कि कभी कोई 'प्रभात' का अंक ऐसा नहीं निकला जिसे पढ़कर ऐसा लगा हो कि पत्रिका छापना है इसलिये छापा गया हो - महज खानापूर्ति के लिये। बल्कि हर बार की 'प्रभात' अपने पिछले अंक से बेहतर होती गई।

समय के साथ 'प्रभात' की छपाई, गेट-अप सुन्दर होता गया। पुराने मैनुअल कम्पोजिंग से शुरू कर फिर टाइपिंग-साइक्लोस्टाइल और उसके बाद कंप्यूटर के प्रवेश से यह विकास हो सका। शुरू से अच्छा होना एक बात है, लेकिन अपनी कमियों को सुधारते हुये बेहतर से बेहतर होना और भी अच्छी बात है। हमारी 'प्रभात', दण्डकारण्य संघर्ष की 'प्रभात', दण्डकारण्य जनता की 'प्रभात' ठीक ऐसा ही है।...

'प्रभात' में कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है... मेरा ख्याल है इससे 'प्रभात' और निखर जायेगी।

1) 'प्रभात' का आकार बदलें ताकि इसे किट में रखने व पढ़ने में ज्यादा सुविधा हो।
2) 'प्रभात' का मुख्य कवर पृष्ठ दण्डकारण्य के संघर्ष का प्रतीक के रूप में हो। यह मोटे कागज का हो तो बहुत अच्छा होगा।
3) 'प्रभात' के एक अंक से दूसरे अंक की समयावधि बहुत ज्यादा है। उस पर भी कभी-कभी या यों कहें अक्सर अनियमित हो जाती है। जो दण्डकारण्य के विकसित होते संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इसलिये पहले तो 'प्रभात' की अनियमितता दूर की जाये, दूसरा 'प्रभात' को दो माह में एक बार किया जाये।
4) दण्डकारण्य के बढ़ते संघर्ष की तुलना में 'प्रभात' में इलाकों के संघर्षों की रिपोर्टें कम छप रही हैं। अत: इसकी व्यवस्था की जाये कि सभी डिविजनों के संघर्षों की खबरें ज्यादा से ज्यादा छपें।
5) युद्ध के मैदानों से युद्ध की कहानियों, संस्मरणों और कविताओं को प्रभात में स्थान मिलने से अच्छा होगा। खासकर इस में रुचि रखने वाले पाठकों के लिये।

बस इतना ही।

-कॉमरेड एस.

सम्पादक मण्डल का जवाब

प्रिय कॉमरेड एस.,

लाल सलाम।

आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपके सुझावों के लिए हम आपका क्रांतिकारी अभिनन्दन करते हैं। दरअसल आपके सारे सुझाव स्वागतयोग्य हैं। कहानियों को पन्नों में जगह देने के बिंदु पर हमारा संपादकमंडल सोच रहा है। लेकिन आज दण्डकारण्य में व्याप्त शत्रु दमन के हालात को देखते हुए और 'प्रभात' की अपनी तकनीकी समस्याओं तथा हमारी कुछ आत्मगत कमजोरियों के चलते आपके सभी सुझावों को चाहते हुए भी हम तुरन्त लागू करने में असमर्थ हैं। अत: क्रांतिकारी आंदोलन के बढ़ने के दौरान अगर कुछ समस्याओं का हल हो जाता है तो पत्रिका की समयावधि कम करने पर जरूर सोचा जा सकता है। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि हम आगे चलकर इसमें समर्थ होंगे।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

'प्रभात' का सम्पादक मण्डल

कविता

'प्रभात' के लिए

– दिलशाद

'प्रभात' की लालिमा
हर बार पहुंचा देती है
शहीदों के आगोश में
वह लालिमा देख
हर बार तड़पता है दिल
अगले ही क्षण
ज्यों–ज्यों चढ़ता है सूरज
उसकी हर किरण
रोम–रोम, पोर–पोर को देती है तपिश
जो जगाती है
प्रतिशोध की ज्वालाग्राही आग!

'प्रभात' के लिये
जो अंन्धेरे से टकराये
और आज भी निरंतर संघर्षरत हैं
अन्धेरे के खिलाफ
जिन्होंने लालिमा की चमक के
लिये अपना खून दिया है
और जो आज भी आफॅसेट के पहिये की
धुकधुकी बनाये रखते हैं दिन–रात
अपना पसीना बहाकर
अक्षरों को करते हैं मुद्रित
हजारों प्रतियों को अपने हाथों
के नीचे से निकालते
जिनके हाथ कठोर हो चुके हैं
उन सभी प्यारे–प्यारे साथियों के लिये
उन गुरिल्ला लड़कियों के लिये
मेरे रोम–रोम से
हर सांस से सलाम निकलता है
जो खुद अल्प–हिंदी ज्ञान के
होने के कारण कभी 'प्रभात' को पूरा नहीं पढ़ पाते
लेकिन हमारे ज्ञान भण्डार
हमारी चेतना बढ़ाने के पीछे
'प्रभात' के विस्तार के पीछे
उन सबका अथक प्रश्रिम है
निश्चित ही वो 'प्रभात' की
अरुणिम किरणों का हिस्सा हैं
उनका नाम कभी नही छपता
ना ही छाप सकते
पर वो प्रभात की लालिमा में
इस कदर समाये हैं
कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

इसके बाद
मेरे पास उन साथियों के लिये भी
ढेरों सलाम हैं
जिनकी उंगलियों ने एक–एक अक्षर
अक्षर से शब्द,
शब्दों से एक–एक किरण का किया सृजन
जिनकी आंखों की रोशनी खींच ले गई
लैपटाप की स्क्रीन
और हिस्सा बना दिया किरणें की चमक का

और यहां उन कामरेडों का जिक्र किये बिना
'प्रभात' के 20 जुझारू वर्षों का
सफरनामा अधूरा ही रहेगा
जिनके कंधे कभी नहीं झुके
लाखों पेपर के कटे ढोते हुये
जिन्होंने साजोसामान कावड़ों में अपने कंधों पर ढोया
और प्रभात के सफर में सहयात्री बने
प्रभात का परिवार भी कम अनूठा नहीं हैं
एक हिंदी पत्रिका में
गोंडी–बंगाली–तेलगू–हिन्दी
कामरेडों की संचित एकता है।
ये बहुभाषी कामरेडों की एकता ही है जिसने
इस हिंदी पत्रिका को इतनी उंचाई पर पहुंचाया।

मैं उन साथियों को भी सलाम करता हूं।
जिन्होंने साइक्लो से शुरू कर
आफसेट तक पहुंचाया प्रभात को
हर बार प्रभात की रोशनी को बढ़ाया
और जिनकी वजह से प्रभात
दण्डकारण्य के जंगलों से निकल पहुंच गई
भारत के क्रान्तिकारी खेमे में कोनों कोंनो तक
और उनकी प्यारी प्रत्रिका बनी!
अन्त में, मेरे दिल को लगता है
यह बीस बर्षों का विशेषांक
उन्हीं के नाम सर्मिपत होना चाहिये

1 जनवरी 08

नंदीग्राम ने सीपीएम लाल नकाब उतार फेंका

पिछले पूरे साल नन्दीग्राम धधकता रहा। नन्दीग्राम विशेष आर्थिक जोनों, और साम्राज्यवादी परियोजनाओं के खिलाफ संघर्षरत जनता के संघर्ष की एक मिसाल बन कर उभरा है। जिससे पूरे देश की जनता प्रेरणा ले सकती है। एक तरफ यह नक्सलबाड़ी की विरासत के किसान-मजदूरों के प्रतिरोध का झण्डा है तो दूसरी तरफ मार्क्सवाद के नाम पर धंधा करने वाले नामधारी कामरेडों की सरकार को समझने का आईना भी। सीपीएम का दलाल पूंजीपतियों को खुश करने का साम्राज्यवाद प्रस्त चेहरा खुलकर खुंखार रूप में सामने आया है। वो पूंजीपतियों के फायदों के लिये कितने फासीवादी तरीके अपना सकते हैं। कितनी हत्यायें करवा सकते हैं, कितनी महिलओं से सामूहिक बलात्कार करवा सकते हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। 'मानिवय चेहरे वाले भूमंडलीकरण' का नकाब ओढ़े बुद्धदेव का वो नकाब भी उतर गया है व सीपीएम का सामाजिक फासीवाद पूरे अपने नंगे खूनी रूप में जनता के सामने बेपर्द हुआ है। आज बुद्धदेव, मोदी, महेन्द्र कर्मा व जार्जबुश के चेहरे पर समानतायें साफ देखी जा सकती है। नवंबर में सीआरपीएफ की मदद से सीपीएम के गुंडों ने चाहे नंदीग्राम पर पुनः कब्जा कर लिया हो, लेकिन नंदीग्राम की जनता ने दिखा दिया है कि साम्राज्यवादी दलालों को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं दी जायेगी। एसईजेड की स्थापना नहीं करने दी जायेगी। सीपीएम का सामाजिक फासीवादी शासन नहीं सहा जायेगा। हम अपनी सत्ता खुद चला सकते हैं।

नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपूर जिले का एक बलॉक है। अक्टूबर 2006 में बुद्धदेव ने आदेश निकाला कि नन्दीग्राम के नयाचर में एक 'केमिक्ल हब' विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जायेगा। जिसके लिये 28,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। यह 'केमिकल हब' उस दानवी कंपनी 'युनियन कार्बाईड' की जन्मदाता कंपनी का है जिस कारण से 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। जिसके खिलाफ दिल्ली में सीपीएम चीखती रहती है। खास बात यह भी है कि इसमें इंडोनेशिया के 'सलीम ग्रुप' का पैसा भी लगना है जिसके मालिक ने इंडोनेशिया के कम्युनिस्टों को मारने के लिये राष्ट्रपति सुहार्तो को करोड़ों डालर की मदद दी थी और लाखों कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतार दिया था। धन्य है सीपीएम का 'सामाजवाद'!

2007 जनवरी की शुरूआत में ही नंदीग्राम के ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) ने जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया जिसके खिलाफ जनता की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नोटिस के विरोध में नंदीग्राम के मजदूर-किसान, दुकानदार, महिलायें सभी सड़कों पर निकल आये। 3 जनवरी को नंदीग्राम में बहुत बड़ी आमसभा हुई। प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष का बिगुल बजाते हुये ऐलान किया किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे! उस सभा की खास बात यह थी कि उसमें नंदीग्राम की घेराबंदी करने की बात हुई। पूरे इलाके को जनता के हाथ में लेने की बात हुई जिसे बाद में पत्रकारों ने 'मुक्तांचल' का नाम दिया, और 11 महीने तक यह सही साबित हुआ।

महान नक्सलबाड़ी संघर्ष के बाद, सीपीएम के सामाजिक फासीवाद के 30 सालों के आंतकी शासन में यह पहली घटना है जब बंगाल की जनता बड़े पैमाने पर उठ खड़ी हुई। 30 सालों से जनता का दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। नंदीग्राम के बारे में कहा जाता था कि वहां सीपीएम के आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन नंदीग्राम की बाहदूर जनता ने पुरे 11 महीने तक पूरे इलाके को 'बीयूपीसी' (भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी) के नेतृत्व में (जो

आंकड़ों की नजर में बंगाल-

- बंगाल में 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
- 2 सालों में चाय बगान बंद होने से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हुये हैं जिसमें से 700 लोग बेरोजगारी से तंग आकर या तो आत्महत्या कर गये हैं या भूख से दम तोड़ चुके हैं।
- 2001 से 2006 तक राशन बांटने की योजनाओं के जरिये गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिये केवल 49 प्रतिशत ही टारगेट पूरा कर पायें है। 68 प्रतिशत सभी खाद्य सामग्री को जनता तक नहीं पहुंचाया गया जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के गोदामों में चली गई, नतीजा हुआ अक्टुबर में राशन दंगे।
- 9 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 9 प्रतिशत गांवों में ग्रामीण शिक्षण कमेटियां नहीं हैं, 47 प्रतिशल कमेटियां शिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये प्रशिक्षत नहीं है। राज्य की 50,285 प्राथामिक पाठशालाओं में से 20 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही कमरा है और 40 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय नहीं हैं।

तुरुणमूल कांग्रेस, जमाते उलेमा हिन्द, एसयूसीआई व माओवादी क्रांतिकारी ताकतों का सयुंक्त मोर्चा है) अपने आधीन रखा। सभी सड़कों को लाल बेरिकेडस लगा कर रोक दिया गया। नहरों, सड़कों पर शहर से जोड़ने वाले पुलों को ढह दिया गया। बीडीओ कार्यालय, पंचायत भवन, सरकार के सभी सत्ता संस्थानों को पंगू ही नहीं बल्कि खदेड़ कर भगा दिया गया। सभी सरकारी परियोजनाओं को ठप कर दिया गया। 11 महीने तक नंदीग्राम में सरकार की कोई भी संस्था काम नहीं कर रही थी इस सच्चाई को 30 अक्टूबर को प्रैस सम्मेलन में सरकार ने भी स्वीकार किया। खुद बुद्धदेव ने कहा कि ''नंदीग्राम में सरकार नाम की कोई चीज काम नहीं कर रही..... बीडीओ, पंचायत कोई भी कार्यालय कार्यप्रणाली में नहीं है। ... वहां माओवादियों, तुरणमुल और भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के सशस्त्र लोगों का कब्जा है।'' जनता ने खुलेआम हथियार पकड़ कर अपने इलाके की, गांव की सुरक्षा की। सीपीएम के 2500 गुंडों को इलाके से भगा दिया गया। नंदीग्राम सीपीएम के फासीवाद के खिलाफ विशेषकर बंगाल की जनता के लिये भी मिसाल है कि गांव में उनके आंतक के खिलाफ कैसे लड़ा जाये।

पूंजीपतियों की नजर में बंगाल-

ध्यान रहे बंगाल पूंजीनिवेश के मामले में कई राज्यों से अग्रणी स्थान पर है।

"बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जैसा ईमानदार नेता पश्चिम बंगाल में एक भी नहीं हैं। वो ऐसा शख्स हैं जिसके पास बंगाल के विकास की सही योजना है।"

- संजीव गोयंका, दलाल पूंजीपति जिसकी 8 हजार करोड़ की पूंजी है। और लगभग ऐसी स्टेटमेंट रतन टाटा और अंबानी बंधुओं के मुख से भी सुनी जा सकती है।

सीपीएम का फासीवादी आंतक

सीपीएम के नेतृत्व वाली वाममोर्चा सरकार के दमन की तुलना गुजरात के नरंसहार या छत्तीसगढ़ के सलवा जुडूम से करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सीपीएम के सामाजिक गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर जो कहर बरपाया, जो नरसंहार किया वह गुजरात के दंगों से किसी भी मायने से कम नहीं है। 14 मार्च 2007 को बुद्धदेव ने यह कहते हुये पुलिस व सीपीएम के 'एक्शन स्काडस' नंदीग्राम में भेजा कि नंदीग्राम को पुन: अपने कब्जे में लेना है। उसकी बात से एसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई देश दूसरे देश पर आक्रमाण के लिये सेना को भेज रहा हो। एक तरह से वह मान चुके थे कि नंदीग्राम 'मुक्तआंचल' है, जहां सीपीएम को दोबारा अपना फासीवादी शासन लागू करना है। सीपीएम के 'एक्शन स्काडस' पुलिस के साथ खुलेआम हथियारों से लैस होकर, सिरों पर भाजपाईयों की तर्ज पर झण्डे बांध कर मोटरसाईकलों पर सवार होकर निकले। निहत्थे ग्रामिण जनता पर गोलियां बरसाई। महिलाओं से सामूहिक अत्याचार किया। आंतक की हद यह थी कि 'महिलाओं के योन आंगों में लाठियां घुसा-घुसा कर पीटा गया' (मेधा पाटेकर का लगभग रोते हुये इंटरव्यू)। घरों से निकाल कर बेदम पिटाई की गई परिणमस्वरूप 14 लोगों की मौत हुई, दर्जनों महिलाओं से सामूहिक अत्याचार किये गये। 100 के करीब लोग घायल हुये और इतने ही लोगों को लगभग गायब कर दिया गया।

14 मार्च की इस पाशविक घटना के बाद नंदीग्राम एक तरफ सीपीएम के सामाजिक फासीवादी गुंडों, पुलिस और दूसरी तरफ नंदीग्राम की बहादूर जनता, प्रगतिशील, क्रातिंकारी ताकातों के बीच युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। एक तरफ नंदीग्राम की जनता ने अपने गांव को लौह दुर्ग में बदल दिया तो दूसरी तरफ सीपीएम गुंडों ने नंदीग्राम की सभी तरह से नाकेबंदी कर दी। उन्होंने नंदीग्राम में बाहर से कुछ भी अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी। पत्रकारों पर हमले हुये, मेधा पाटेकर जब नंदीग्राम की जनता का सर्मथन करने जा रही थी तो उनकी कार पर हमला हुया। ममता बैनर्जी की कार पर गोलियां दागी गई। यहां तक कि जिस घर में मेधा पाटेकर ने बचने के लिये शरण ली थी उसी रात को 600 लोगों की सीपीएम समर्थित भीड़ ने उसके घर को जला कर राख कर दिया। डाक्टरों को बलात्कार की रिपोर्ट तैयार करने से रोका गया। जिसने ऐसा करने का दुस्साहस किया उसको मारने और नौकरी से निकालने की धमकियां दी गई। कोई दिन एसा नहीं गुजरा जिस दिन सीपीएम के गुंडों और जनता के बीच झड़प ना हुई हो। नंदीग्राम 11 महीने तक 'गुरिल्ला जोन' जैसा बना रहा।

बुद्धिजीवियों की नजर में ...

"ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी सीपीएम के नेता उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या सीपीएम इस बात का समर्थन करती है कि महिलाओं के यौन अंगों में लाठियां डाल कर उनको पीटा जाये? क्या सीपीएम बलात्कार का समर्थन करती है? क्या वो बच्चों को फाड़ का फैंका जाये, इस बात का समर्थन करती है? अगर ऐसा है तो उसे सरकार में बैठे रहने का हक नहीं है।"

- मेधा पाटेकर

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की नेता व प्रसिद्ध समाजिक कार्यकता।

नंदीग्राम बलॉक-1 के बाद जनता अपने इलाके का लगातार विस्तार कर रही थी। सीपीएम को खेजूरी तक समेट कर रख दिया। वहां से भी सीपीएम के तत्वों को खदेड़ा जा रहा था। सीपीएम सरकार व सीपीएम के लिये यह अस्तित्व व प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा था। नंवबर के पहले सप्ताह में नंदीग्राम को पुन: अपने नियंत्रण में लेने के लिये उन्होंने प्रयास तेज किये। मई 2008 में होने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुये उन्होंने इन प्रयासों को दुगना कर दिया। नंवबर के शुरू से ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सीपीएम के 'एक्शन स्काडस' खेजूरी में इक्टठा होने शुरू हो गये। पूरे इलाके को उन्होंने गुंडाई अंदाज में घेरना शुरू कर दिया। यह तैयारियां पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से की गई थीं। 7 नवंबर को खेजूरी से उनका तांडव शुरू हुआ। घरों को जलाना, महिलाओं को पकड़ कर अत्याचर करना, भूमि

उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के प्रतिनिधि व सदस्य और उनके घर खास तौर पर उनका निशाना बने। उनके घरों व उनकी जानकारी की पूरी लिस्ट उनके हाथों में थी। नंदीग्राम में लगातार हो रही हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने 9 नंवबर को प्रेस कान्फरेंस कर के बयान दिया कि 'नंदीग्राम के गांवो को जिस तरह से पुन: कब्जे में लिया जा रहा है वह पूरी तरह गैरकानूनी और असहनीय है।.... नंदीग्राम के इस सारे घटना क्रम के लिये सीपीएम पूरी तरह से जिम्मेवार है।'' इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने सीपीएम के गुंडों को रोकने की बजाय पूरी तरह उनकी सुरक्षा की। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों में पुलिस ने किया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार - नंदीग्राम से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमगाचिया में सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की शान्तिपूर्ण रैली पर गोलियों से हमला किया। इस रैली में निहत्थे बीयूपीसी के 5000 कार्यकर्ता शामिल थे। खेजूरी के पास से 5 लाशें बरामद की जा चुकी हैं बाकी की अभी तलाश जारी है। बहुत सी लाशें लापता बताई जा रही है। वो अपने साथ बीयूपीसी के 200 कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले गये जिसे खेजूरी में बंदी बना कर पिटाई की गई और यातनायें दी गई। स्टानेगबाड़ी व सोनचरा की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से जबरदस्ती और बलात्कार किये हैं। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और उनकी मदद की। बीयूपीसी का कहना है कि वह नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के बाहर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जिस पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने पीछे से हमला किया।

12 नवंबर को इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने बंगाल बंद की अपील की जिससे बंगाल में जनजीवन पूरी तरह से ठप्प रहा। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अर्पणा सेन, रितुपर्णो घोष आदि ने 13वें कोलकात्ता फिल्मोत्सव के बहिष्कार की घोषणा की जिसका उद्घाटन नंदीग्राम की जनता के खून से रंगे हाथों को यानी बुद्धदेव ने करना था। 10 नंवबर को बंगाल सरकार में पीडबल्यूडी मंत्री केशिटी गोस्वामी व प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी भी अपनी अस्वस्थ हालत के बावजूद भी प्रदर्शनों में शामिल हुई।

इस आन्दोलन ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया। 60 के संघर्षपूर्ण तूफानी झांझावतों के दशक के बाद इतने बड़े पैमाने पर बंगाल के मजदूर-किसान, दुकानदार, छात्र, महिलायें बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकर सड़कों पर उतरे हैं। यह गुस्सा 'सेज' और साम्राज्यवादी नीतियों के साथ सीपीएम के बेरोकटोक चल रहे 30 साल के सामाजिक फासीवादी शासन के खिलाफ भी था। आंतक, हत्यायें, बलात्कारों और दमन के दम पर बनाये महल पर यह पहला बड़ा हमला था। निश्चय ही बंगाल की जनता सीपीएम के सामाजिक फासीवादी शासन को नेस्तनाबूद करेगी। इस आंदोलन ने सीपीएम के समर्थक बुद्धिजीवि वर्ग को भी सीपीएम के विपक्ष में खड़ा कर दिया है। वो खुलकर सीपीएम की आलोचना कर रहें है और प्रदर्शनों में शामिल हो रहें हैं। चाहे वह इतिहासकार सुमित सरकार हो, अशोक मित्रा या फिर उपन्यासकर सुनिल गंगोपाध्याय हो। बंगाल के बुद्धिजीवियों व छात्रों ने भी संघर्ष की परंपरा को जीवित रखा है और किसानों के आंदोलन का खुल कर सर्मथन किया है। यह देश के अन्य राज्यों के बुद्धिजीवियों के लिये भी प्रेरणा का स्रोत है खासकर हिन्दी पट्टी के बुद्धिजीवियों के लिये जो बंद कमरों में बैठकें कर कॉफी के प्याले में साम्राज्यवाद को नेस्तनाबूद करने की तुफान बहस उठये रहते हैं। इन 11 महीनों में दर्जन भर 'बंगाल बंद' के आव्हान हुये जिसमें सभी पूरी तरह से सफल हुये। कोलकाता की सड़कों से लेकर गांवों तक जनता ने, छात्रों ने इसमें भाग लिया और लाठियां खाई।

सीपीएम किसी भी कीमत पर नहीं चहाती थी कि नंदीग्राम बंगाल के गांव-गांव में फैले, उनके शासन के खिलाफ लोग खड़े हों। इसलिये 16 नंवबर को सीपीएम ने केंद्र से सीआरपीएफ की 6 बटालियनों के साथ अपने हजारों गुंडों को नंदीग्राम के मैदान में उतारा जिसके दम पर नंदीग्राम में श्वेत आंतक मचाकर नंदीग्राम को अपने कब्जे में ले लिया। क्रान्तिकारी ताकतों को तात्कालिक रूप से पीछे हटना पड़ा। लेकिन साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के साथ-साथ सीपीएम के लूटकारी मंसूबे ध्वस्त हुये हैं। सीपीएम का यह भ्रम भी टूटा है कि वह जैसा चाहे बंगाल में राज चलाये। पूरे देश के लिये व क्रान्तिकारी ताकतों के लिये साम्राज्यवाद व विशेष आर्थिक क्षेत्रों के खिलाफ लड़ने की दिशा व सयुंक्त मोर्चा का शानदार अनुभव हासिल हुआ है। इस से बंगाल में क्रान्तिकारी ताकतों में बहुत जोश बढ़ा है और मजबूती भी मिली है। यह संयुक्त मोर्चा के द्वारा लड़ा जा रहा एक शानदार संघर्ष है। जिसे पूरे देश में दोहराये जाने की जरूरत है। 'प्रभात' खदानों, बड़ी परियोजनाओं, बड़ी स्टील कंपनियों से विस्थापित हो रही तमाम जनता से अपील करती है कि नंदीग्राम की तरह व्यापक स्तर पर सयुंक्त मोर्चों का निर्माण करके देश में विदेशी टापुओं के निर्माण का विरोध करें और अपने-अपने इलाकों में सशस्त्र प्रतिरोध का झण्डा उंचा उठायें, जो रास्ता कलिंगनगर, नंदीग्राम, सिंगूर की जनता ने दिखाया है उस पर चलकर देश से साम्राज्यवाद और उनके दलालों को मार भगाओ। ★

नंदीग्राम ने हथियार नहीं डाले हैं।

सुष्मिता

(यह लेख पश्चिम बंगाल की एक लेखिका ने लिखा है जिसे हमने इंटरनेट से किसी वेबसाइट से हासिल किया। विषय के महत्व को देखते हुए हम इसे हूबहू छाप रहे हैं। - संपादक)

आपने बुद्धदेव के चेहरे की चमक देखी होगी, जब वे घोषणा कर रहे थे कि नंदीग्राम के लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया गया है। यह चमक ठीक वैसी ही मालूम पड़ती थी, जैसी इराक और अफगानिस्तान पर कब्जे की घोषणा करते हुये जॉर्ज बुश के चेहरे की चमक। फर्क केवल इतना ही था कि बुद्धदेव के चेहरे पर अपने ही राज्य के लोगों की हत्या की चमक थी और बुश दूसरे देशों के लोगों की हत्याओं पर मुस्कुरा रहे थे। यदि आपको लगे कि 2002 में नरेंद्र मोदी भी शयादउ कुछ इसी तरह मुस्कुरा रहा था, जब गुजरात में नरसंहारों को जायज ठहराने के लिये क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत को याद कर रहा था तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चेहरे एक-दूसरे से घुल-मिल से गये हैं।

अंतत: नंदीग्राम को फतह कर ही लिया गया। एक भयानक नरसंहार...जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली, दूसरे सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं, दर्जनों महिलाओं का सीपीएम के झंडे तले बलात्कार हुआ और अनेक मकान जला दिये गये।

गांव वालों का कहना है कि दूसरे दौर की हिंसा में करीब 150 लोगों को मार दिया गया है। लगभग 2000 लोग अब भी गायब हैं। घटना के दिन करीब 550 लोगों को रस्सी से बांध कर खेजूरी ले जाया गया जहां इनको सीपीएम ने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि नंदीग्राम के लोग जवाबी कार्रवाई न कर सकें। तमाम स्रोतों का कहना है कि इस हत्या अभियान में पेशेवर अपराधियों एवं डकैतों का सहारा लिया गया था। नंदीग्राम को फतह कर लेने की जिम्मेवारी जिस माकपाई गुंडावाहिनी को दी गयी थी उसका नेतृत्व उसके 4 सांसद कर रहे थे। और उसमें तपन घोष व शकुर अली जैसे कुख्यात अपराधी भी थे। ये दोनों 2001 में छोटा अंगरिया हत्याकांड में सीबीआइ द्वारा घोषित फरार अपराधी हैं।

हमने सुना कि नंदीग्राम के लोगों ने अपनी करतूतों की पाई-पाई चुका दी है।

हमने सुना कि महिलाओं को मेधा पाटकर को अपना पिछवाड़ा दिखाना समाजवाद लाने के कार्यभरों में से है।

हमने यह भी सुना कि नंदीग्राम की महिलाओं की देह में सीपीएम के लाल झंडे गाड़ दिये गये। हमने सुना और शर्मसार हुए। हमने उजाले की संभावनाओं को अंधेरे के सौदागरों के हाथों बेच देने वालों के बारे में सुना। हमने उस मुख्यमंत्री के बारे में सुना जो 150 लोगों के कत्ल के बाद सुगंधित पानी से हाथ धोकर फिल्मोत्सव की तैयारियों में जुटा गया।

नंदीग्राम को फतह कर लिया गया है...और फिजा में विजय के उन्माद से भरे नारों और गीतों का जश्न है। सहमा...वीरान...राख...राख नंदीग्राम! वह नंदीग्राम जो हमारी उम्मीदों का सबसे ताजा मरकज है। वह नंदीग्राम जो पेरिस कम्यून से लेकर रूस, चीन, वियतनाम और नक्सलबाड़ी सहित अनेक महान शहादतों में सबसे गर्म खून है।

नंदीग्राम को फतह करने की पृष्ठभूमि लगभग एक साल से बनायी जा रही थी। सिंगूर के 'सेज' से सबक लेकर नंदीग्राम के लोग पहले से ही सचेत थे। जुलाई 2006 से ही नंदीग्राम में केमिकल हब के लिये 28,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की बात हवा में थी। नंदीग्राम के लोगों ने अपनी जमीन बचाने की लड़ाई शुरू कर दी। पिछले मार्च में सीपीएम ने नंदीग्राम पर कब्जा जमाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दरअसल यह सीपीएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। वह नंदीग्राम की जनता की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिये इस बार सीपीएम ने काफी साजिशपूर्ण तरीके से अपना हमला संगठित किया। सबसे पहले भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के लोगों के साथ समझौता कराया गया एवं उसके बाद फिर उन पर हमला करवाया गया ताकि वे प्रतिरोध के लिये तैयारी ना कर सके। कहा जा रहा है कि इस हमले की तैयारी कई महीनों से खेजूरी में चल रही थी। इसके लिये रानीगंज, आसानसोल कोलबेल्ट, गरबेटा व केशपुर से गुंडों को भाड़े पर लाया गया। इस पूरे अभियान का संचालन सीपीएम के उच्च नेतृत्व के हाथों में था। यह पूरी तरह गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था।

हत्या अभियान के दिन सीपीएम के लक्ष्मण सेठ कह रहे थे - 'मारो, न मरो'। विनय कोनार महिलाओं को आह्वान कर रहे थे कि वे 'अपनी साड़ी उठायें और मेधा पाटकर को अपना पिछवाड़ा दिखायें।' विमान बोस लगातार देश को बता रहे थे - 'नंदीग्राम के लोग हमें रसगुल्ला नहीं खिला रहे थे'

इन्हीं हत्यारों के नारों के बीच कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग

में ठहके गूंज रहे थे और वहां के निवासी आश्वस्ति और उल्लास में एक दूसरे को बधाइयां देते हुये हाथ मिला रहे थे। – 'नंदीग्राम के लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया गया'।

सीआरपीएफ की तैनाती भी साजिशपूर्ण तरीके से की गयी। पहले नंदीग्राम पर बर्बर हमला किया गया और उसके बाद सीआरपीएफ को पश्चिम बंगाल की जनता के तमाम विरोध के बाद तैनात किया गया ताकि वहां की जनता को प्रतिरोध करने से रोका जा सके व नंदीग्राम पर पूरी तरह उनका नियंत्रण बना रहे। इस पूरी प्रक्रिया में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की सरकारों के बीच निर्लज्ज सौदेबाजी हुई। केंद्र सरकार का कोई भी मुख्य अधिकारी नंदीग्राम में नहीं गया। उसने सीआरपीएफ की कंपनियां दीं और इसके एवज के बतौर वाममोर्चा ने परमाणू समझौते पर आईएईए से बात करने की हरी झंडी दे दी। साम्राज्यवाद की चमचागिरी का यह एक और नायाब नमूना है।

अब नंदीग्राम में शांति है। एक मरी हुई शांति, जो श्मशान में होती है, बस चीख रहा है, जल्लाद नंदीग्राम के लोगों को तहजीब बता रहा है। वह पूरे देश की जनता को लोकतंत्र के मायने समझा रहा है। बृदां करात और प्रकाश करात 'मारो-मारा' की हत्यारी पुकारों के बीच बेशर्म होकर हमें लोकतंत्र की तहजीब के बारे में बता रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि चूंकि वहां बहुमत की सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है इसलिये नंदीग्राम का हत्या अभियान जायाज है। हमें कहा जा रहा है कि नंदीग्राम के बारे में सवाल उठाने वाले लोग एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 2002 में नरेंद्र मोदी की भाषा यही थी या नहीं, क्या हमें याद करने की इजाजत है 'कॉमरेडो,? क्या जॉर्ज बुश की भाषा इससे अलग होती है जब वह इसी लोकतंत्र का हवाला देकर दुनिया के कमजोर व प्रतिरोध करने वाले देशों पर हमला करता है।

सीपीआई के डी. राजा व सीपीएम के प्रकाश करात कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को नंदीग्राम में कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। मतलब कि इनके लोकतंत्र में नंदीग्राम के लोगों से खतरा था तो क्या अब लोकतंत्र केवल सत्ता द्वारा जनता की हत्याओं को जायाज ठहराने का औजार मात्र रह गया है? क्या सत्ता को आम जनता को उसके घरों से खदेड़ने व हत्या करने का अधिकार केवल इसलिए मिल गया है कि तथाकथित रूप से वह चुनी हुई है? यदि इस लोकतंत्र को नंदीग्राम के लोगों से खतरा है तो नंदीग्राम के लोगों को भी यह कहने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि यदि यह लोकतंत्र हमारे जीने के अधिकारों पर पाबंदी लगाता है तो उन्हें भी इस लोकतंत्र से खतरा है? सच तो यह है कि नंदीग्राम की जनता तो अपने जीने के अधिकार के लिये ही लड़ रही है, जो अंतिम रूप में अपनी मातृभूमि की रक्षा की भी लड़ाई है।

लेकिन इस हत्या व उत्पीड़न का गवाह अकेले नंदीग्राम नहीं हैं, साम्राज्यवादी ताकतों ने पूरी दुनिया में नंदीग्राम की तरह ही अभियान चलाया। पूरे लैटिन अमेरिका व वियतनाम में साम्राज्यवादी लूट को चलाने के लिये वहां के स्थानीय आदिवासियों को भयानक हत्या के जरिये उनकी वास्तविक जगहों से भगा दिया गया। कहीं-कहीं तो उनकी पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया गया। भारत में भी साम्राज्यवाद के चमचे उनकी ही रणनीति अपना रहे हैं। वर्षों पहले केरल में मुथंगा में सत्ता ऐसा ही नरसंहार रचा था। मुथंगा में भी आदिवासियों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया। लेकिन अंततः सत्ता के योजनाबद्ध व खूनी हमले में उनको कुचल दिया गया। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में अपनायी जा रही है। आदिवासियों में पहले फूट डाली गयी एवं एक हिस्से को अपने पक्ष में करके उन्हें उनकी जगहों हटा कर कैंपों में लाया गया जबकि दूसरे हिस्से पर भयानक हमला कर उन्हें भी वहां नहीं रहने दिया गया। अब वहां राहत शिविरों को ही गावं में बदलने की योजना है। इन सबको अपनी जमीन से उजाड़ दिया गया और उनकी जमीनें बहुराष्ट्रीय को कंपनियों को दी जा रही है। यही प्रक्रिया उड़ीसा, झारखंड, व पश्चिम बंगाल में भी चलाने की साजिशें जारी हैं। पहले निवासियों को उनकी जमीन से हटाओ (चाहे जैसे भी हो), फिर उसे साम्राज्यवाद के कदमों में हस्तांतरित कर दो। नंदीग्राम की जनता के साथ भी यही किया जा रहा है। प्रतिरोध करने वाले लोगों को उनकी जगहों से खदेड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब वे सीपीएम की मर्जी पर ही वहां लौट सकते हैं।

हमें लगता है कि हम अपनी जगह में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, इसलिए कि अशांति तो हमसे दूर कहीं मुथंगा, छत्तीसगढ़ या फिर नंदीग्राम में है। लेकिन वह हरा सांप हमें अचानक रेंगता हुआ अपनी खाट के नीचे महसूस होता है। वह हरी घासों में इस तरह छिपा होता है कि पता ही नहीं चलता कि वह है कहां? ऐसे में हमारे पास अपनी खाट छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। वह सांप हरी घास में छिपा हुआ रेंग रहा है। मुथंगा से छत्तीसगढ़, कलिंगनगर, झारखंड, सिंगूर, नंदीग्राम और न जाने कहां-कहां।

सीपीआई-सपीएम के लोग उन तामाम लोगों को विकास विरोधी बता रहे हैं, जो नंदीग्राम अभियान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पहले से ही पश्चिम बंगाल में लगभग 55 हजार कारखाने बंद पड़े हैं। बीमारू उद्योगों की संख्या 1,13,846 है, जो पूरे देश का 45.60 प्रतिशत है। पिछले 15 सालों में लगभग 15 लाख मजदूरों को उनके काम से

निकाल दिया गया है, जबकि महज 43 हजार 888 लोगों को काम मिला। सरकारी व निजी संगठित क्षेत्रों में 1980 में कुल 26 लाख 64 हजार लोग कार्यरत थे। जब औद्योगीकरण का मंत्र पढ़ा जा रहा है, इस दौर में यह गिर कर 22 लाख 30 हजार पर आ गया है वहीं रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 1977 (जब वाम मोर्चा सरकार में आया) 22 लाख 27 हजार से बढ़कर 2005 में 72 लाख 27 हजार 117 हो गयी है। यहां यह जानना जरूरी है कि 35 साल से अधिक उम्र के लोग इसमें नहीं लिये जाते। कृषि संकट ने और बुरे हालात पैदा किये हैं। सीपीएम के नेता भूमि सुधार की डींग हांकते नहीं थकते। वे तर्क दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कृषि ने उद्योग के लिए आधार तैयार किया है। लेकिन इनका ढोंग तब सामने आ जाता है जब पता चलता है कि 1982 में विधानसभा चुनाव व 1983 में पंचायात चुनाव के बाद ऑपरेशन बर्गा या बंजर जमीनों को जोतने लायक बनाने का काम भी रुक गया। यही नहीं, 2004 की मानव विकास रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 14.31 प्रतिशत बर्गादार अलग-अलग जगह विस्थपित हो गये हैं। यह प्रतिशत जलपाईगुड़ी में 31.60, कूचबिहार में 30.2, उत्तर दिनाजपुर में 31.42 व दक्षिण दिनाजपुर में 30.75 है। यही नहीं, पट्टा दिये गये लोगों का विस्थापन भी लगभग 13.23 प्रतिशत है। 1992-2000 में 48.9 प्रतिशत गांवों के परिवार भूमिहीन हो गये। जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का सवाल है वह भी पश्चिम बंगाल में कृषि की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करता है। 1976 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पूरे देश में खद्यान्न उपलब्धता 402 ग्राम के मुकाबले पश्चिम बंगाल में 412 ग्राम था। यह 1999 में 502 ग्राम के मुकाबले 444 ग्राम हो गया। 2001 में यह आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 413 ग्राम तक पहुंच गया। (स्रोत-अजीत नारायण बसु, बंगाल की अर्थनीति और राजनीति) यह कृषि संकट की भयानकता स्पष्ट करता है। यदि विकास के सिद्धांतों पर गौर करें तो पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का आधुनिकता और विकास का सिद्धांत मूलत: सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) व और औद्यिगीकरण के स्तर पर विकास का आधार मानता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पिछड़े देशों में नव उपनिवेश की अवस्था में इन्होंने आधुनिकता के पश्चिमी मॉडल पर जोर दिया। यह मूलत: चीन एवं रूस में खड़े हो रहे एक सामाजवादी विकल्प को नकारता था। मार्क्स ने अपने विकस के सिद्धांत में सामंतवाद या पूर्व पूंजीवादी संबंधों के विनाश पर औद्यिगिकीकरण की बात की थी। पश्चिम अर्थशास्त्रियों का आधुनिक का सिद्धांत 1970 के बाद ही गरीब देशों में बुरी तरह विफल साबित हुआ। अब साम्राज्यवादी देशों के अपने संकट को भी हल करने के लिए विश्व बैंक एवं अन्य साम्राज्यवादी संस्थाओं ने इसी सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। बुद्धदेव ने भी इसी सिद्धांत को उधार लेते हुये इंडोनेशिया में घोषणा की कि कृषि पिछड़ेपन की निशानी है, जबकि वितरण में भारी असमानता, महाजनी वृद्धि, बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये जगह बनाना, भारी पैमाने पर शॉपिंग मॉल एवं उपजाऊ जमीनों को नष्ट करते हुये हाइवेज का निर्माण करना है। जो बुद्धदेव सरकार ने किया है।

सीपीएम के विकास की अवधारणा मूलत: साम्राज्यवाद के हित में अपनायी जाने वाली अवधारणा है जो किसानों को और गहरे संकट में धकेल देगी। इसके साथ ही साथ, यह राज्य में भयानक लूट को जन्म देगी। उपजाऊ जमीनों के भयानक पैमाने पर अधिग्रहण से खाद्यान्न उत्पादन में और गिरावट होती है तथा एक बड़ी जनसंख्या और बदहाली में जीयेगी।

लेकिन नंदीग्राम ने स्पष्ट कर दिय है कि यह सरकार अपनी साम्राज्यवाद परस्त नीति के खिलाफ उठने वाली हरेक आवाज को खूनी पंजों से मसल देगी। सीपीएम ने अपने तमाम विपक्षियों के साथ यही भुमिका निभाई है। इनके खिलाफ खड़ी होने वाली तमाम ताकतों को शुरू से ही भयानक सशस्त्र दमन का शिकार होना पड़ा है। सीपीएम ने कभी भी अपने खिलाफ विपक्ष को पनपने नहीं दिया। वह उन्हें भ्रूण रूप में ही मसल देती है। सीपीएम की 30 सालों की सफलता का यही राज है। लेकिन जिन इलाकों में प्रतिरोध के स्वर ने लगातार सीपीएम के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, अब सीपीएम वहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गरबेटा इसका उदहारण है और अब वहां के इनके गुंडे नंदीग्राम व सिंगूर में काम आ रहे हैं। नंदीग्राम में तो सीपीएम के नेताओं ने स्वीकार भी किया है कि वे इस तरह से इलाकों को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते (तहलका), अर्थात पश्चिम बंगाल में वही विपक्ष में खड़े रह सकते हैं जो सीपीएम की गुंडावाहिनी का प्रतिरोध कर सके। इसी प्रतिरोध का भय उन्हें माओवादियों से होता है। सीपीएम ने बार-बार कहा कि नंदीग्राम में हिंसा इसलिए हुई चूंकि वहां माओवादी थे। अर्थात अगर वहां माओवादी नहीं होते तो सीपीएम शांतिपूर्ण तरीके से अपना पूरा काम निपटा लेती।

1970 से ही सीपीएम पर सामाजिक फासीवादी होने के आरोप रहे हैं। ये आरोप धीरे-धीरे सही भी साबित हुए हैं। सामाजिक फासीवाद व सांप्रदायिक फासीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं - नंदीग्राम ने तो यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सीपीएम पर नंदीग्राम में अल्पसंख्यकों को लेकर कई सांप्रदायिक आरोप भी लगते रहे। यह महत्वपूर्ण है विपक्षहीन बंगाल में नंदीग्राम ने वास्तविक विपक्ष की भूमिका निभायी। उसने अपने प्रतिरोध संघर्ष को सालभर तक टिका कर रखा है।

अब नंदीग्राम को फतह कर लिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे पेरिस कम्यून से लेकर रूस, चीन व अन्य देशों में जीते सर्वहारा की सत्ता पर फिर से पूंजीवादियों की फतह ! ठीक वैसा ही जश्न जैसे हरेक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता का जश्न!

तो क्या अब उम्मीद कविता की आखिरी पंक्ति में भी नहीं बची रह पायेगी? क्या फिल्मों के समापन दृश्य में बच्चों की किलकारियां असंभव बना दी जायेंगी? चिड़ियों की उड़ान से महकते आसमान और चींटियों के सपनों से भरी जमीन की दुनिया खत्म हो जायेगी? क्या बसंत अब फिर नहीं आने के लिये आखिरी बार जा चुका है? लेकिन युद्ध के मोर्चे पर आग बढ़ना या पीछे हटना हथियार डालना नहीं होता। जनता के सपने अब भी जिंदा हैं।

सुना है नंदीग्राम में इस बार फसल नहीं बोयी जा सकी है। सुना है परती खेतों में लोगों की लाशें हैं और ईंट-पत्थर हैं।

मगर नंदीग्राम की माटी में उम्मीद की जो फसल लहलहा रही है उसके बारे में क्या किसी ने नहीं सुना है?

आइये, इस नयी फसल के स्वागत में हम सभी खड़े हों -हाथ उठाते हुये। ✶

बस्तर में सलवा जुडूम के आंतक के साये में शिक्षा !

आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की रमन सरकार की साजिश!

बस्तर में चल रहा आदिवासी किसानों के क्रांतिकारी आन्दोलन को खत्म करने के लक्ष्य से जून 2005 में सलवा जुडूम दमनकारी सैनिक अभियान लूटेरी सरकार ने शुरू किया। कारॅपेट सुरक्षा के नाम पर सैंकड़ों पुलिस कैम्प एवं अर्ध सैनिक बलों के कैम्प स्कूल एवं आश्रमों में बनाये गये हैं। दांतेवाड़ा एवं बिजापूर जिलों में 156 स्कूलों को पुलिस के कैम्पों में बदल दिया है। भैरमगढ़, उसूर, भोपालपटलम, कोंटा इसके शिकार बने हैं।

सलवा जुडूम से दोनों जिलों में 640 गांव प्रभावित हुये है। 500 गांव के हजारों घरों को जला कर तबाह कर दिया गया है। 550 बेकसूर लोगों की पुलिस और विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है। सलवा जुडूम के आंतक के कारण हजारों की संख्या में ग्रामीण तथाकथित सरकारी राहत शिविरों में चले गये हैं। करोड़ों की संपत्ति को सलवा जुडूम के गुण्डों और पुलिस ने लूटा है। अभी भी ऐरिया डामनेशन के नाम से गश्त, सलवा जुडूत सभा के नाम से गांवों पर विदेशी सेना की तरह आ कर आंतक का नगां नाच करते हैं। हरियाल, पोंजेर, कमकानगर, मनकिल, परके, कोया नेंड्रा आदि गावों में निर्दोष ग्रामिणों की झूठी मुठभेड़ों में सामूहिक हत्य की गई है। इस आंतक के चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है।

''नक्सलियों के आंतक से स्कूल आश्रम बंद हैं'' नक्सली स्कूलों भवनों को बमों से उड़ा रहे हैं। इसलिये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नक्सली आदिवासी बच्चों को शिक्षित नहीं होने देना चहाते।'' एसे झुठे व मनघंड़त प्रचार सरकार व मीडिया द्वारा किया जा रहा है।

दरअसल सच्चाई इसके विपरीत है। क्रांतिकारी आन्दोलन ने कभी भी शिक्षा को मना नहीं किया है, बल्कि उसे प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा का निजीकरण करके शसान द्वारा गरीब बच्चों को एवं आदिवासी बच्चों को शिक्षा से दूर रख जा रहा है। शिक्षा के निजीकरण के चलते आज शिक्षा अमीरों की बपोती बन कर रह गई है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का ढ़िढ़ोरा पीट रही है जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 60 सालों में दंतेवाड़ा में 25 प्रतिशत से भी कम लोग साक्षर हो पाये हैं, उच्च शिक्षा की बात तो कोसों दूर है। इसलिये आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वचिंत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकार व उस की साम्राज्यवाद प्ररस्त शिक्षा नीति जिम्मेदार है।

बीजापुर व दंतेवाड़ा के पांच ब्लॉकों में सलव जुडूम का आंतक जहां-जहां ज्यादा है, वहां कारपेट सैक्युरिटी के नाम पर, जिन स्कूलों व आश्रमों का भवन अच्छा था उनमें पुलिस व सीआरपीएफ के कैम्प डाल दिये गये हैं। मिसाल के लिये चेरापाल, पामलवाय, चेरामंगी, मुर्कीनार, नैमड़, माटवाड़ा, जैवाड़ा, पिनकोण्डा, नेलनार, रानीबोदली, तोयनार, गुदमा, बोदली, पोलमपल्ली, इंजरम, मराईगुड़ा, अरनपुर और पालना आदि गावों की शालाओं में पुलिस कैम्प बना दिये गये हैं। इसके अलावा क्रांतिकारी आन्दोलन का बहाना बना कर पदेड़ा, पिड़िया, तमेड़ी, कड़ेनार, वेच्चापाल मुण्डेर, तूड़ेम, धर्मापुरम, रेगड़गटटा, तोड़का, तोर्रेम, इलिंगेर, दाड़ेली, डब्बाकुन्टा आदि आश्रम शालाओं को पुलिस थानों के पास, राहत शिविरों के पास स्थानातंरित कर दिया है। इन आश्रमशालाओं के भवन निर्माण के नाम पर सलवा जुडूम के नेता, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी गण और पुलिस के अधिकारी मिलबांट कर अपनी जेबे गरम करने में लगे हुये हैं। पूरी धनराशि को डकार रहे हैं। दूसरी ओर बासागुड़ा, उसूर, गंगालूर, मिरतूल, कुटटरु, भोपालपटनम, कोंटा और किस्टाराम आदि इलाकों के अंदुरुनी गांव में स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस के आंतक के चलते शिक्षक गांव में पढ़ाई करवाने नही आते। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सलवा जुडूम के श्वेत आंतक से आलम यह है कि गावों उजड़ चुके हैं। ग्रामीण जनता जंगल, पहाड़ों में रहकर अपनी सुरक्षा कर रही है। गश्त के नाम पर पुलिस ने छोटे-छोटे बच्चों की भी हत्यायें कीं हैं। कईका गांव में कार्यरत शिक्षक विजय लाल दुग्गा की नक्सलियों का सर्मथक बता कर स्कूल में ही हत्या गई। कई शिक्षकों को इसी शक पर पीटा गया और झूठे मुकदमें लगा कर जेल भेज दिया। अंदुरनी इलाकों में कार्यरत सभी शिक्षक उन्हें नक्सलियों के समर्थक नजर आते है, यही कारण है कि उनके ऊपर सदा कड़ी नजर रखी जाती है। पुलिस ने स्कूलों, आश्रमों में शिक्षकों के कवार्टरस को भी कब्जा कर लिया है। सरकार 'सामूहिक बसाहट' के नाम पर लोगों को सड़क के किनारे बसा रही है और वहां पर संगीनों के साये में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र चलाये जा रहे हैं।

संयुक्त दंतेवाड़ा-बीजापुर जिला शैक्षणिक स्तर 2006-2007 में 6 वर्ष की आयु के 1 लाख 31 हजार 232 बच्चों ने प्रवेश लिया था। इनमें से 40 हजार 427 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। कहां कितने बच्चों ने छोड़ा स्कूल?

ब्लाक	दर्ज संख्या	ड्रापआउट
बीजापुर	12204	7206
उसूर	12411	7616
भैरमगढ़	13929	8793
भोपालपटनम	11368	3717
कोन्टा	17232	10618

उपरोक्त आंकड़ों के अलाव 11से 14साल तक के 57 हजार 486 बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया था। किन्तु सलवा जुडूम के

(शेष पृष्ठ 40 में...)

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा काफी नहीं !
गोण्डी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए !!
राज्योत्सव के नाम से जारी फिजूलखर्ची
छत्तीसगढ़ की गरीबी के साथ मजाक !!!

छत्तीसगढ़ राज्य की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। सभी को मालूम है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर ही उसने यह लोकलुभावन घोषणा की है। 2 करोड़ छत्तीसगढ़िया लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने में सरकार को 7 साल का इंतजार करना पड़ा, जोकि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति शासकों की उदासीनता का परिचायक है। हमारी पार्टी ने सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का स्वागत करते हुए ही यह बात स्पष्ट की थी कि सिर्फ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने से काफी नहीं है, बल्कि शोषणविहीन व जनवादी छत्तीसगढ़ चाहिए। हमने उसी समय यह भी मांग उठाई थी कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देकर इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। हमारा मानना है कि किसी भी भाषा का विकास तभी सम्भव होगा जब उसे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई का माध्यम बनाया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा मुहैया कराना सरकारों की नैतिक व संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन आज भी हमारे देश के करोड़ों लोग इस अधिकार से वंचित है। हम छत्तीसगढ़ की तमाम जनता व जनवादी बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई शुरू करने की पुरजोर मांग उठाएं और उसके लिए संघर्ष करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का स्वागत करते हुए ही हमने बस्तर को इसमें शामिल करने का विरोध भी किया था। हमारी पार्टी के साथ-साथ लाखों बस्तरवासियों का मानना है कि छत्तीसगढ़ की तरह पृथक व जनवादी बस्तर राज्य के गठन से ही आदिवासी बहुल बस्तर के विकास के रास्ते खुल सकते हैं। क्योंकि बस्तर की अपनी अलग संस्कृति, अलग भाषा और अलग जीवनशैली हैं, जो छत्तीसगढ़ से भिन्न हैं। बस्तर की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा गोण्डी है और इसके अलावा हल्बी, भतरा जैसी कई अन्य भाषाएं भी हैं। पृथक व जनवादी बस्तर के लिए बस्तर की जनता ने कई संघर्ष किए जिनका लगातार दमन किया जाता रहा है। हमारी पार्टी हर साल 1 नवम्बर को 'पृथक बस्तर राज्य' की मांग के समर्थन में बंद आदि का आयोजन करते आ रही है। (बदकिस्मती से मीडिया में इसे तोड़-मरोड़कर हमेशा ऐसी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं कि नक्सली छत्तीसगढ़ के गठन का विरोध कर रहे हैं।) हमारी पार्टी का मानना है जिस प्रकार छत्तीसगढ़ी जनता के लिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार बस्तरिया जनता की पृथक बस्तर राज्य की मांग भी वजिब और न्यायसंगत है। बस्तर की जनता छत्तीसगढ़ के शासकों से शुरू से ही इस मांग को लेकर अलगाव महसूस कर रही है। अब छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने वाली भाजपा सरकार का गोण्डी भाषा पर चुप्पी साधे रहना आदिवासियों के प्रति, उनकी भाषाओं के प्रति उसकी घोर लापरवाही का साफ सबूत है। दरअसल, इतिहास के मुताबिक गोण्डी भाषा छत्तीसगढ़ी से भी प्राचीन है, जो आज शासकों की आपराधिक लापरवाही के कारण लुप्त होने का खतरा झेल रही है। यह एक समृद्ध भाषा है और इसका मौखिक साहित्य का समृद्ध भण्डार है। मुख्य रूप से गीतों, नाटकों व लोककथाओं में निक्षिप्त गोण्डी भाषा के साहित्य को बचाने, लिपिबद्ध करने व विकसित करने की सख़्त जरूरत है। इसलिए, हम छत्तीसगढ़ी जनता व छत्तीसगढ़ी बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि छत्तीसगढ़ी के साथ-साथ गोण्डी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा देकर इन दोनों ही भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने की मांग करें। हल्बी, भतरा जैसी अन्य भाषाओं के विकास के लिए समुचित प्रयास करने की मांग भी करें। हम तमाम बस्तरवासियों व बस्तरिया बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि पृथक बस्तर राज्य की मांग के साथ-साथ गोण्डी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर संघर्ष को तेज करें। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि गोण्डी भाषा के प्रति उसकी लापरवाही से बस्तर की जनता में अलगाव की भावना और भी बढ़ जाएगी।

हम इस मौके पर राज्योत्सव के नाम पर की जा रही फिजूलखर्ची का भी कड़ा विरोध करते हैं। एक तरफ प्रदेश की जनता गरीबी, पलायन, अशिक्षा, महंगाई, विस्थापन, बेरोजगारी, आदि समस्याओं से बुरी तरह ग्रस्त है और नेता-अफसर घूसखोरी, भ्रष्टाचार व घोटालों में करोड़ों रूपए गबन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 'राज्योत्सव' के नाम पर करोड़ों रूपए पानी की तरह बहाना, मनोरंजन के नाम पर फूहड़ फिल्मी नाच-गानों का आयोजन.... ये सब इस अमीर धरती के गरीब बाशिन्दों के साथ मजाक नहीं तो क्या है? सरकार इस तड़क-भड़क वाले आयोजनों की आड़ में अपनी नाकामियों और जनता की वास्तविक समस्याओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। हम प्रदेश की मेहनतकश व जनवादी जनता का आह्वान करते हैं कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें और शोषणविहीन व जनवादी समाज के निर्माण के लिए कदम बढ़ाएं।

(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (माओवादी)

दिनांक : 03-11-2007

दुश्मन को ललकारती और संघर्षों में सैलाब की तरह उमड़ती दण्डकारण्य की बहादूर जनता की जय-जयकार !

(पिछले कुछ समय से 'प्रभात' के प्रकाशन में लगातार हो रही देरी के कारण सभा-सम्मेलनों और विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ रिपोर्टें हम समय पर प्रकाशित नहीं कर पाए जिसका हमें खेद है। एक बात यह भी है कि संघर्ष के मैदानों से कुछ रिपार्टें हमें देर से प्राप्त हो रही हैं। इन कारणों से इन पन्नों पर हम नई रिपोर्टों के साथ-साथ कुछ पुरानी रिपार्टें भी छाप रहे हैं। आशा है, पाठक गण इस असुविधा के बावजूद हमारा साथ देंगे। - सम्पादकमण्डल)

आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की!
हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की!!

यह ललकार दे रही है दक्षिण बस्तर की बहादूर जनता, वर्तमान समय के सर्वाधिक क्रूर व पाशविक फासीवादी सैनिक अभियान 'सामूहिक शिकार' को। दक्षिण बस्तर की क्रांतिकारी जनता ने जितने बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर पार्टी स्थापना दिवस और पीएलजीए स्थापना दिवस मनाया है उसने सलवा जुडूम और कारपेट सेक्यूरिटी की धज्जियां उड़ा दी हैं। लगातार जारी दमन अभियान के खिलाफ प्रतिरोध की तथा पार्टी व जन सेना के प्रति प्रतिबधता की यह सभाएं नई मिसालें हैं।

पार्टी स्थापना दिवस

दक्षिण बस्तर डिविजन के जेगुरगुंडा इलाके में बोडकेल एलओएस व बासागुड़ा एलओएस की जनता ने मिलकर जन सभा का आयोजन किया। लाल-लाल झंडों, बैनरों, पोस्टरों से मैदान चमक रहा था। जनता ने दमन की परवाह ना करते हुये हजारों की संख्या में भाग लिया, जो लड़ने की उनकी ताकत और लाल सेना पर उनका अडिग विश्वास को दर्शाता है। दोनों इलाकों से 2000 महिलाओं और 3000 पुरषों ने जन सभा में भाग लिया।

वक्ताओं के सम्बोधन में जनता की जय-जयकार और युद्ध को तेज करने का दृढ़ सन्देश था। वक्ताओं ने कहा - '2 साल से जारी फासीवादी सैनिक अभियान सलवा जुडूम के कारण भारी तबाही हुई है। 600 गांवों को उजाड़ दिया गया है। 50 हजार से ज्यादा जनता अपने घरों से बेदखल कर दी गई है और यातना शिविरों में रहने को मजबूर है। अब तक 500 आम जनता, जन संगठनों व पीएलजीए के लाल योद्धा अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। परंतु बहादुर जनता ने दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिरोध का झण्डा ऊपर उठये रखा है। वो लड़ रही है और दुश्मन के हमलों को परास्त कर रही है।' उन्होंने बार-बार आह्वान किया - प्राण प्रिय जनता हमने यूं ही अपने इलाके में व्यापक जन समर्थन से युद्ध को तेज करना है, पार्टी को मजबूत करना है व अपनी जनताना सरकार की रक्षा व मजबूती करनी है।

जनता ने भी उतनी ही दृढ़ता के साथ नारा लगा कर जवाब दिया - सीपीआई (माओवादी) जिंदाबाद! जनता ना सरकार की रक्षा करेंगे! इसके बाद जनता अपने तीर-धनुषों को ताने हुये सर्तकता से अपने-अपने गांव को लौट गई ।

पीएलजीए दिवस पर आमसभाएं

दक्षिण बस्तर डिविजन में 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए दिवस को जोर शोर से मनाया गया और सफल सभाओं का आयोजन किया गया। डिविजन में जन प्रतिरोध जारी है और दमन भी। इनके बीच ही जन सभाओं में जनता बेखौफ होकर जन मुक्ति छापामार सेना का स्थापना दिवस मनाने के लिये शामिल हुई। जेगरगुंडा में 11 जगहों पर 2 दिसंबर को सभाएं संमन्न हुईं। 6 दिसंबर को दो एलओएस एरिया की जनता 3000 की भारी तादाद में एक जगह इकट्ठा होकर सभा संपन्न की। नगाराम एरिया एलओएस कमांडर के नेतृत्व में 2200 लोगों ने पीएलजीए दिवस पर रैली निकाली व सभा की। सभाओं में पीएलजीए द्वारा जारी साहसिक हमलों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

किस्टाराम एरिया में एरिया कमेटी के द्वारा 6 दिसंबर को पीएलजीए दिवस मनाया गया जिसमें 2000 महिलाओं और 2000 पुरुषों ने भाग लिया। सभा को जन संगठन के नेताओं ने बारी-बारी से संबोधित किया। पीएलजीए को मजबूत करने और जनाता की लड़ाई का विस्तार करने के लिये जनता का आह्वान किया गया।

पामेड़ एरिया में 2 दिसंबर को पीएलजीए सभा मनाई गई। इस सभा को एरिया के जन संगठनों के नेतृत्व में सफल किया गया। इसमें 4850 महिलाओं व 5790 पुरुषों ने भाग लिया। सभा में बैनर, पोस्टर, पर्चों के जरिये व सिनेमा, नाटक, गाना, नाच आदि के द्वारा पीएलजीए का संदेश दिया गया।

कोंटा इलाके में 2 सभाएं हुईं जिसमें 7400 जनता ने भाग लिया। इन सभाओं को संबोधित करने वाले वक्ताओं ने पीएलजीए के प्रतिरोध की घटनाओं को विस्तार से बताते हये उरपलमेट्टा, ताड़मेट्ला, तोगुंड़ेम, मुरलीगुड़ा और पामुलवाही हमलों को जन युद्ध के तेज होने के बारे में बताया और जनता से छापामार युद्ध से चलायमान युद्ध में विकसित करने व दण्डकारण्य को आधार इलका बनाने व पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने का आह्वान किया गया।

वो नहीं चहाते बस्तर में एक दाना तक भी पहुंचे!

दक्षिण बस्तर डिवीजन के किष्टारम एरिया में 9 फरवरी 2007 की घटना है यह। इस इलाके के गांव मचनपल्ली में साप्ताहिक बाजार बैठता है। सरकार व सलवा जुडूम चाहता है कि बस्तर में बाहर से दैनिक जरूरतों की एक भी चीज ना पहुंच पाये। वो पहले भी बहुत बाजारों को बंद करवा चुके हैं ताकि जनता को रोजमर्रा की चीजों के लाले पड़ जाये। उनको खाने को कुछ ना मिले। इसलिये गांव मचनपल्ली उनके कहर का निशाना बना। मिजो, नगा, एसटीएफ, पुलिस व एसपीओ के साथ सलवा जुडूम के गुंडे दंतेवाड़ा से 9 फरवरी को अपने दल-बल के साथ सैंकड़ों की संख्या में निकले। दंतेवाड़ा से 15 किलामिटर तक का सफर पैदल तय किया।

गांव के 43 धान की कोठियां, घर, सुअर बाड़े, बकरी बाड़े समेत कुल 65 घरों को जला डाला। घरों में रखा धान, बर्तन व

व्यापारी लोगों का रखा हुआ सारा सामान जला कर राख कर दिया। बाजार साप्ताहिक होता है इसलिये व्यापारी अपना कुछ सामान बाजार वाले गांव में ही रख कर चले जाते हैं। व्यापारियों को लगभग 50 हजार रूपये के सामान का नुकसान हुआ। इसके साथ मुर्गे, बतख, बकरियां यहां तक कि मुर्गीयों के अंडे भी अपने साथ लूट कर ले गये।

पश्चिम बस्तर रिपोर्ट

बीच बाजार में एसपीओ नरेश कुत्ते की मौत! 300 सीएएफ व मिजो जवान देखते रह गए!!

भांसी के बीच बाजार में विशेष पुलिस अधिकारी नरेश को एक्शन टीम ने कुत्ते की मौत मार गिराया। जब उसको सजा दी जा रही थी, 300 सीएएफ व मिजो के जवान बाजार में मौजूद थे। मगर जनता की दिली मदद से एक्शन टीम अपनी कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देकर निकल गई। प्रति-क्रांतिकारी फोर्स हाथ मलते हुये चकित रह गई।

भोगामी गुड्डी उर्फ नरेश पश्चिम बस्तर के भैरमगढ़ इलाके के दोरूम गांव का निवासी था। भोगामी गुड्डी पहले जन संगठन में काम करता था। 1997 में महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में शुरू हुये 'जन जागरण अभियान' का संगठन में रहते हुये विरोध किया था। संगठन में काम करते हुये वह 1998 में भैरमगढ़ दस्ते में शामिल हो गया। परंतु दस्ते में उनका व्यवहार लंपट तत्वों जैसा था। इसलिये वह 2001 में वापस गांव चला गया। 2005 में सलवा जुडूम शुरू होने के कारण वह अपने परिवार को लेकर उरेपाल गांव चला गया। वहां रहते हुये कुछ समय जन मिलिशिया में भी काम किया। 2006 नवंबर में पुलिस ने उसके घर से उसकी पत्नी राधे को उठा लिया और उससे सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसे लालच दिया तो सब कुछ भूलकर आसानी से उसने आत्मसमर्पण कर दिया और गुंडों की टोली का सदस्य बन गया।

किरंदुल थाने में आत्मसमर्पण करने के साथ ही उसके काले कारनामों की सूची बढ़ती ही गई। एसपीओ बनने के साथ-साथ भैरमगढ़ व गंगलूर इलाके के गांवों पर हुये हमलों और लूटपाटों में वह शामिल रहा। उरेपाल गांव में जिस घर में वह रहता था, जिस महिला के हाथ की रोटियां खाता था इस दरिंदे ने उसी महिला के साथ पुलिस वालों के साथ सामूहिक बलात्कर किया। भांसी, बचेली, किरन्दुल के बजारों में इसने खूब लंपटबाजी की, बेवजह पिटाई करना, सामान छीनना, विरोध करने पर पकड़कर थाने ले जाना झूठे केस लगवाकर फंसाना इसका सगल बन गया था। बावड़ी गांव के कॉमरेड कोया पाण्डू (कीर्ति) और पूनेम सन्नू को बचेली की एक दुकान में पकड़ा और झूठी मुठभेड़ में मार डाला। ऐसा ही बचेली बाजार में गये जन मिलिशिया कॉमरेड कड़ति रामाल व कॉमरेड संपत (कुंजामी सोमारू) को पकड़कर मारने में इसका ही हाथ था।

जब जख्म पककर नासूर बन जाता है तो उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है। और वो पीड़ा बैलाडीला, पिड़िया, गंगालूर और बचेली के आसपास की जनता काफी समय से झेल रही थी। 27 अगस्त को जब उसे शानदार बहादुराना कार्रवाई में एक्शन टीम ने जड़ से खत्म कर दिया तो स्वाभाविक ही पूरे एरिया व बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। सच है, जनता के दुश्मन कितने ही कवचों में रहें वो नहीं बच पाते।

जन मिलिशिया की शनदार प्रतिरोधी कार्रवाइयां

28 जुलाई को एसपीओ, पुलिस, सीएएफ के 30 जवानों का गश्ती दल इस मंसूबे के साथ पामुलवाया की तरफ निकला कि नहीं होने देंगे शहादत सप्ताह का कार्यक्रम। लेकिन जन मिलिशिया के बूबी ट्रैप के जाल में फंस गये। और जाते हुये उनके कंधों पर दो एसपीओ की लाशें थी।

26 अगस्त को जंगल वारफेर स्कूल में प्रशिक्षित एसटीएफ, सीएएफ व जिला पुलिस का संयुक्त गश्ती दल चार बैच में अलग-अलग दिशाओं से चला। निशाना था पीएलजीए के बहादूर लड़ाकों पर, परन्तु पुल्लुम गांव के पास ही उनकी हवा सरक गई जब एसटीएफ के एक जवान का पांव प्रेशर बम पर रखा गया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अब आगे बढ़ना उनके लिये कहां संभव था? इसी दिन पातरापारा सलवा जुडूम शिविर पर हमला किया गया जिसमें दो सलवा जुडूम गुंडों को मार गिराया गया। इसी दिन एक और अन्य घटना में दो सीएएफ जवान पीएलजीए के हमलों में घायल हुये। ये सरकारी गुंडे भैरमगढ़, बोदिली, पिण्डूम थाने से चार बैचों में गश्त पर निकले थे।

सितंबर 3 तारीख को बरदेली जंगल में हमारे स्थानीय मिलिशिया ने एसपीओ मिड़ियामी कोसू को खत्म कर दिया। माटवाड़ा एरिया में सलवा जुडूम के स्थानीय नेता गंगू पटेल के साथ दो अन्य को मौत के घाट उतार दिया, जिससे स्थानीय जनता को उनकी जन विरोधी कार्यवाहियों से निजात मिली।

उत्तर बस्तर डिवीजन के प्रतापुर एरिया में पीएलजीए की 7वीं वर्षगांठ जोर-शोर से मनी

'अगर जनता के पास जन सेना नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है', 'गांव-गांव में जनसत्ता की रक्षा के लिये, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार कायम करने के लिये कोया भूमकाल मिलिशिया व लाल सेना में भर्ती हो जाओ' के संदेश के साथ प्रतापुर एरिया के काकनार, बड़गांव, मेंढ़की, कड़मे इलाकों के अंतर्गत जोर-शोर से पीएलजीए की 7वीं वर्षगांठ मनाई।

सभी जन संगठन और मिलिशिया दलों ने अलग-अलग टीमें बनाकर व्यापक प्रचार अभियान चलाया। पोस्टर, बैनरों, पर्चे लगाए गए और जनता ने भी सभाओं में अपने पारम्परिक हथियारों के साथ व्यापक स्तर पर भागीदारी की। कुल मिलाकर 4 सभाएं आयोजित की गईं। सभाओं की अध्यक्षता एलओएस कमांडरों ने की। एलओएस कमांडरों ने पीएलजीए के चमकते लाल झण्डे को फहराया। सभाओं में पीएलजीए के महान योद्धाओं को श्रद्धांजली अर्पित की और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने, दण्डकारण्य को आधार इलाके के रूप में विकसित करने का आह्वान किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि दुश्मन के चौतरफा हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये हरदम चौकस और सचेत रहना चाहिये। जनता

की सत्ता के अंगों व हमारे आंदोलन को जड़ से खत्म करने के दुश्मन मंसूबों को ध्वस्त करने के लिये लाल सेना के सिवाय कोई चारा नहीं है। दुश्मन गांवों में मुखबिरगिरी व दलालगिरी करवाने के लिए लोगों को बरगला रहा है। जनता को ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। और उन्हें तुरंत सजा देनी चाहिए। "पीएलए का निर्माण करेंगे" और "आधार इलाके का निर्माण करेंगे" के नारों के साथ सभायें संपन्न हुई।

भूमकाल दिवस-2007 की कुछ रिपोर्टें

उत्तर गडचिरोली डिवीजन के अन्तर्गत आने वाले सातगांव एरिया के गांव बोदिन व गोडेलवाही में भूमकाल सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में 57 गांवों के सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया।

दोनों सभाओं में आदिवासी अमर शहीद गंडाधुर, वीर बाबुराव और गेंदसिंह को लाल श्रद्धांजली अर्पित की गई। गोडेलवाई में सभा अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि 1910 में गुंडादूर ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से टक्कर लेते हुये जल-जंगल-जमीन पर आदिवासी जनता का अधिकार कायम करने के लिये 'माड़िया राज' की स्थापना की थी। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है ताकि जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना की जा सके।

बोदिन की सभा केएएमएस की कार्यकर्ता ने मुख्य बात रखी। उन्होंने -महान भूमकाल की विरासत के तौर पर चल रही लड़ाई में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर संतोष जताया और उसे ओर ज्यादा बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सुरजागढ़ लौह खदान के बारे में बोलते हुये कहा कि सुरजागढ़ की पहाड़ियां जनता की एतिहासिक धरोहर हैं, जिसमें हमारे नायक बाबुराव ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चला कर उनके दांत खट्टे किया थे। आज साम्राज्यवादियों के दलाल व पालतू कुत्ते व शासक वर्ग आदिवासी लड़ाइयों की निशानियों को ध्वस्त कर देना चाहते हैं ताकि हमारे दिमागों में से उनकी तस्वीर मिट जाए। आज जरूरत है कि महान भूमकाल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रण लें कि सुरजागढ़ की एतिहासिक धरोहर को बचाने के लिये, हमारे पुरखों की निशानियों को बचाने के लिये जनयुद्ध को तेज करें। 'भूमकाल दिवस राज्य स्थापना दिवस जिंदाबाद' के जोशीले नारों के साथ लोग सभा से गांव की और लौट गये।

संक्षिप्त खबरें

- चादगांव के बादिन गांव में 2-3 जनवरी 2007 को विस्थापन विरोधी बंद के आहवान पर पांच गांव की सैकड़ों जनता ने सभा में शिरकत की और विस्थापन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया।

- 26 जनवरी गणतंत्र के ढकोसले के विरोध मे चादगांव एरिया में दो जगहों पर आम सभाएं की गईं और रैलियां निकाली गईं। 26 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाया गया।

- 10 अप्रेल 2007 को गडचिरोली डिवीजन व महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने बंद का आहवान किया था। इसको लागू करते हुये चादगांव व पोटेगांव की सैकड़ों बहादूर जनता, जन मिलिशिया व पीएलजीए की टुकड़ियों ने मिलकर सफल बनाया। जन मिलिशिया ने रात के 2 बजे पुलिस थाने पर हमला किया जिसमें एक पुलिस वाले को मार गिराने में सफलता मिली। 10 अप्रैल को धनोरा तहसील कार्यलय में जनता व जन मिलिशिया घुसकर उसे जलाकर राख कर दिया जिससे सरकार को लाखों रूपये का नुकसान हुआ।

उत्तर गडचिरोली तेंदूपत्ता संघर्ष

2007 में उत्तर गड़चिरोली के कसनसूर, चादगांव व टिप्रागढ में तेंदूपत्ता संबंधी रेट बढ़ाने के लिये मजदूरों की क्रमशः 8, 4, 6 कमेटियों का गठन किया गया। सभी कमेटियों ने अपने-अपने इलाकों में सभाएं आयोजित कर रेट तय किया। अगर तय रेट नहीं दिया गया तो काम बंद करने का फैसला लिया। लेकिन ठेकेदारों को जनता की एकता ने मांग मानने के लिये मजबूर कर दिया। ठेकेदार बाहर से आने वाले मजदूरों को कम मजदूरी देते थे। इस पर भी रोक लगाई गई।

संघर्ष से प्राप्त रेट

पत्ता तुड़ाई का रेट प्रति सैंकड़ा -	152
दिवानजी (छोटा फड़) -	3,700
वाचर (छोटा फड़) -	3,600
(बड़ा फड़) -	3,800
वाचर (छोटा फड़) -	3,700
उल्टाई-पल्टाई	19 रूपये (हजार प्रति)
बोरा ढुलाई 3 कि. मी.	2,200
पानी घड़ा -	7.50 (कावड़ी 15 रू.)
भराई प्रति बोरा-	60.00 ★

पाठकों से ....

प्यारे पाठको,

'प्रभात' को सभी शहीद कॉमरेडो की जीवनियां नहीं मिल पा रही है। मिल भी रही है तो उनमें पूरी जानकारी नहीं होती। कृपया शहीदों के बारे में लिखते हुये, निम्न बातों को ध्यान में रखें.....

1. शहीदों का पूरा नाम, मां-बाप का नाम, किस डिवीजन, तहसील, गांव से था/थी। वह कब पैदा हुआ था/हुई थी। शहादत की तारीख। किस कारण से शहीद हुआ/हुई। यह सब भूमिका में जरूर दें।
2. विवरण में उसका व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक-सांगठनिक जीवन के बारे में बतायें, कहां-कहां काम किया, सांगठनिक, फौजी मामलों में उसकी भागीदारी। पार्टी से कब जुड़ा/जुड़ी। पार्टी सदस्यता कब मिली। किस कारण से प्रभावित हुआ/हुई। किस-किस स्तर पर उसने काम किया।
3. अंत में उसके व्यक्तिगत आदर्शों, खूबियों, उससे हम क्या सीख सकते हैं लिखें।

इन सबको जीवंत ढंग से लिखना चाहिये। हम आशा करते हैं कि पाठक इस विषय पर जरूर गौर करेंगे। अगर आप हिंदी में लिख भेजेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा होगी।

संपादक मंडल
'प्रभात'

सभा–सम्मेलन

23 मार्च को साम्राज्यवाद विरोधी दिवस मनाया

गड़चिरोली डिविजन के चादगांव एरिया में जंगे आजादी के वीर शहीद भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु के महान आदर्शों व अरमानों को ऊंचा उठाकार जनयुद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ो! इस अवसर पर सभा का आयोजन एक गांव में किया गया। सभा शुरू होने के पहले नारों के साथ रैली सभा स्थल तक निकाली गई। फिर सभा आध्यक्ष कॉ. सुनिला ने झण्डा पहराया। अमर शहीदों को याद करते हुए दो मिनेट का मौन रखा गया। मीटिंग शुरू कर 23 मार्च का महत्व समझाया गया। फिर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आदर्शों का परिचय किया गया। फिर कॉमरेड दिवाकर ने सभी प्रतिनिधियों को लाल सलाम कर भाषण शुरू किया। 23 मार्च का पूरा विवरण दिया और साम्राज्यवादी उदाहारण का उल्लेख कर समझया कि वर्तमान काल क्या है। और जन संगठन को साक्रिय रूप से निर्माण करना, संगठित व संघर्षशील करना, जन मिलिशिया समेत पीएलजीए के तमाम बलों को मजबूत करने का महौल है। कॉमरेड सावजी ने जन सगंठन के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए भाषण दिया। और कामरेड सुधीर ने महाराष्ट्र शासन के दमन और सी-60 क्रैक कमाण्डों की झूठी मुठभेड़ों के विरोध में भाषण दिया। और झूठी मुठभेड़ों में शहीद कामरेडों को श्रद्धांजली पेश की। कॉमरेड कान्ता ने महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात रखी। कॉमरेड कोसा ने वन सम्पत्ति के बारे में भाषण दिया। मीटिंग के बीच-बीच में एरिया सीएनएम की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। भगत सिंह नाटक और साम्राज्यवाद विरोध नाटक पेश किया। इस मीटिंग मे 17 गांवों से जनता ने भाग लिया। 125 महिलाओं और 50 बच्चों समेत कुल 375 लोगों ने भाग लिया। यह मीटिंग दिन भर चली। लाउड स्पीकर के जरिए मिटिंग को चालया गया। लेकिन जन मिलिशिया इसकी रक्षा करती रही। बैनर, पोस्टर, पर्चा छिपकाया था। इस तरह यह सभा कामयाबी के साथ सम्पन्न हुई। अध्यक्ष कॉमरेड ने उपस्थित जनता का लाल अभिनन्दन किया।

8 मार्च मना

चादगांव एरिया में तीन जगहों में 8 मार्च आंतर्राष्ट्रीय महिला दिवास मानया गया। सलवा जुडूम के नाम पर आदिवासी जनता पर जारी फासीवादी सैनिक आभियान के तहत महिलाओं पर हो रहे कत्लेआम और हिंसा, बलात्कार व अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवास बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूरे इलाके में पोस्टर लगाए गए और पोस्टर 150 और बैनर 8 बांटे गए। 10 गांवों के 300 लोगो ने एक जगह एकट्ठे होकर सभा का आयोजन किया। केएएमएस अध्यक्ष ने केएएमएस का झण्डा फहराकर कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं की समस्याओं पर बात रखी। उन्होंने आव्हान किया कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार मिलना है तो संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है। दूसरी जगह में आयोजित सभा में दो पंचायतों के दायरे के लोगों ने भाग लिया।

यह आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है।

रावघाट एरिया में आजादी का भांडाफोड़ करते हुये 15 अगस्त को काला दिवस मनाया गया। तिरंगे झंडे को जलाकर उसकी जगह पर प्रतिरोध स्वरूप काला झंडा गाड़ दिया गया। वक्ताओं ने इस आजादी को काली आजादी, झूठी आजादी बताया। और कहा कि यह आजादी जमींदार व पूंजीपतियों की आजादी है। आज भी विदेशी कंपनियां हमारे देश को दोनों हाथों से लूट रही हैं। अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुये कहा कि साम्राज्यवादियों को हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की आजदी है, दलाल पूंजीपतियों को उनकी दलाली करके अपना घर भरने की आजादी है, पुलिस व सीआरपी को जन आंदोलनों को कुचलने की आजादी है। यह आजादी के नाम पर ढकोसलेबाजी के सिवाये कुछ नहीं है। जनता को उसकी जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कार्यक्रमों के अंत में चारगांव, लोहंडीगुड़ा में लोहा खदानों के लिये जमीन अधिग्रहण करके जनता को विस्थापन करने का विरोध किया गया। और इस बात पर जोर दिया गया कि इस विस्थापन के खिलाफ देश में उठ रहे जन ज्वार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को तेज करना चाहिये।

ifyl neu dk gjk;x] lyok tMe dk uk'k djx] xko&xko e tu lÙkk dk fuek.k djx के नारों के साथ कार्यक्रम का जोशपूर्ण समापन हुया।

शामिल हुई जनता – महिलायें 932, पुरुष 1147, छात्र 870 कुल 2949। इसके प्रचार अभियान में विभन्न जन संगठनों की बीस टीमों के 132 सदस्यों ने हिस्सा लिया व 700 पोस्टर व 40 बैनरों को लगाया गया।

चातगांव ऐरिया

गडचिरोली डिविजन में 15 अगस्त को झुठी आजादी के अवसर पर दो जगहों पर काला झण्डा गाड़ दिया गया। 150 पोस्टर, 1000 पर्चों व आठ बैनरों से प्रचार किया गया। आजादी की असलियत से जनता को अवगत करवाया गया। ✶

(...पृष्ठ 23 का शेष)

–27 जून को देशव्यापी आर्थिक नाकेबन्दी के अवसर पर बड़े पैमाने पर कोया भूमकाल मिलिशिया, डीएकेएमएस व केएएमएस ने मिलकर बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया। इस मौके पर 377 मिलिशिया सदस्यों ने जगह–जगह पर 1050 पोस्टर, 1000 पर्चे, 30 के आस–पास बैनर लगाये गए और कई जगहों पर रोड को काट कर रोड जाम किया गया। रात को पुलिस थाने पर फायरिंग करके विरोध जताया गया। एक जगह पर आमसभा आयोजित की गई जिसमें हजार की तादाद मे लोगों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया और साम्राज्यवाद की दलाल भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों का विरोध किया। ✶

विस्थापन के खिलाफ आम सभा व रैली

26–27 जून 2007 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने विस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों व भारत सरकार की तमाम साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ दो दिन की देशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया था। पूरे दण्डकारण्य में आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह सफल रही। दण्डकारण्य में इसको लेकर हुये कार्यक्रमों में से एक है दक्षिण बस्तर के किष्टाराम इलाके में हुई एक यादगर आम सभा। यह वह इलाका है जहां युद्ध जैसे हालात बने हुये हैं।

कोई दिन ऐसा नही बीतता होगा जब किसी न किसी गांव पर सलवा जुडूम के गुण्डों का कहर ना बरसता हो या कहीं न कहीं मुठभेड़ ना होती हो। इन्हीं सब परिस्थितियों में दमन को ठेंगा दिखाते हुये हुई है यह आम सभा। जहां भी नजर डालो जनता ही जनता नजर आ रही थी। स्थानीय पार्टी कमेटी के आह्वान के अनुसार करीब–करीब दस हजार से ज्यादा जनता आई थी। सभी लोग खाना बनाने के लिए दाल–चावल साथ में लिये हुये थे। कोई दो घंटे तो कोई दो दिन चल कर आया था।

दोपहर तप रही थी, याद रहे यह जून का महीना है। लेकिन जिधर भी नजर जाती लोगों का आता हुआ रैला ही दिखाई देता। किसी के हाथ खाली नहीं थे। तीर–धनुष, कुल्हाड़ी व भरमार बन्दूकें ज्यादातर के पास थीं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के चेहरों पर हौसले को पढ़ा जा सकता था। आम सभा से पहले जंगल में दो किलोमीटर की लगभग रैली निकाली गई। जगंल गर्ज उठा – साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कारण विस्थापन नहीं सहेंगे! जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी जनता का अधिकार कायम करो। गांव में जनताना सरकार मजबूत करो। नारे हिन्दी में थे, गोण्डी में थे। जूलुस की अगुवाई चेतना नाट्य मंच की टीम कर रही थी। हरी धोतियां, पांव में घुघंरू, हाथों में लाल झण्डे लिये चल रहे थे। गीतों में दुश्मन को ललकार थी। उनके पीछे–पीछे बाल कलाकारों की टोली थी। फिर महिलायें, नौजवान सभी के हाथों में बैनर लहरा रहे थे। कुछ तखतियां उठाये हुये थे। रैली पूरी हुई तो जनता पसीने से तरबतर हो चुकी थी।

आम सभा की अध्यक्षता जिला जनताना सरकार के प्रतिनिधि कॉ. इंगलू ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में कॉ. इगंलू ने कहा कि इतने दमन ओर गर्मी के बावजूद इतनी संख्या में आप लोगों का आना सलवा जुडुम के गुण्डों व उनके आका साम्राज्यवादियों के मुंह पर करारी तमाचा है। मैं आप सब क्रांतिकारी जनता का जिला जनताना सरकार की ओर से यहां पधारने पर क्रांतिकारी अभिनन्दन करता हूं। चेतना नाट्य मंच के जिला अध्यक्ष कॉ. जयराम, डीएकेएमएस के जिला कमेटी सदस्य कॉ. सत्यम व ऐरिया जनताना सरकार की अध्यक्षा कॉ. गंगी ने भी सभा को सम्बोधित किया।

सभी वक्ताओं ने 'सेज' को देश की धरती पर विदेशी टापू बताया और निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण साम्राज्यवाद प्रस्त नीतियों का जमकर विरोध किया गया। जयराम ने कहा कि साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के चलते गलत सांस्कृतिक मूल्य परोसे जा रहे हैं। वहीं सत्यम ने आर्थिक नीतियों को जन विरोधी करार देते हुये कहा कि यह सब किसानों और आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल से खदेड़ने की साजिश है। अब किसानों के पास दो ही रास्ते बचे हैं – भूख से मरो या लड़कर अपनी जमीन, संपदा को बचाओ। कॉमरेड गंगी ने सलवा जुडूम और साम्राज्यवाद के बीच के गठजोड़ की पोल खोली और कहा कि महेन्द्र कर्मा व स्थानीय सामंती तत्व अपनी सत्ता को दोबारा पाने के लिये और साम्राज्यवाद यहां की खनिज संपदा लूटने के लिये एकजुट होकर दमन चला रहे हैं। इस गठजोड़ को जनता को समझना होगा। इस तरह से देखें तो सलवा जुडूम के खिलाफ लड़ाई साम्राज्यवाद के खूनी पजों के खिलाफ भी है। भारत में साम्राज्यवादी लूट के आगे भारत की जनता का माओवादी आन्दोलन सबसे बड़ी रूकावट है। इसलिये उसके चमचे आन्दोलन को कुचलने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गंगी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ अन्तिम समाधान राजनीतिक सत्ता दखल बताया और उसके लिये गांव स्तर, ऐरिया स्तर, जिला स्तर की जनताना सरकारें बनाने और उन्हें मजबूत करने का आह्वान किया।

जिला चेतना नाट्य मंच व स्थानीय सीएनएम टीम ने पूरी सभा के दौरान जनता का जोश बरकरार रखा। साम्राज्यवाद पर दो नाटक और गीतों द्वारा उन्होंने लड़ाई को तेज करने, हथियारबदं संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। अन्तिम समय में गीत स्टेज से नीचे पहुंच कर जनता के होठों पर आ गये और एक लम्बा सा गोल घेरा, घेरे पर घेरे बनते गये। सारा कार्यक्रम सामूहिक नाच में बदल गया। आखिर में लाल सलाम के अभिवादन के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। अन्तिम दृश्य और नाच ऐसा कि जैसे जन सागर हिलोरे ले रहा हो, गर्ज रहा हो।

सभा करीब पांच घंटे तक चली, चारों तरफ पुलिस, अर्ध सैनिक बलों के कैम्प और सलवा जुडूम के गुण्डे भी, तो आम सभा कैसे संभव और सफल हुई। जब इस बारे में सभा के अध यक्ष से पूछा तो उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया–

अगर जनता साथ है तो असंभव कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि देश में जनरल डायरों की कमी नहीं है। इसलिये कोया भूमकाल मिलिशिया, जन मिलिशिया और पीएलजीए के बल चारों तरफ से सभा को सुरक्षा के घेरे में लिये हुये थे। चारों ओर दस–दस किलोमिटर तक गश्त जारी थी, जगह –जगह एम्बुंश लगाये बैठे हुये थे। अगर दुश्मन आ भी जाता तो जनता इसके लिये पूरी तरह से तैयार थी।

उत्तर गड़चिरोली डिवीजन

उत्तर गडचिरोली के टिप्रागढ व चादगाव इलाके में 26

(शेष पृष्ठ 22 में...)

28 जुलाई

नम आंखों व दिलों में जोश के साथ मना शहीद सप्ताह

28 जुलाई को कॉमरेड चारू मजुमदार कलकत्ता के लाल बाजार थाने में संशोधनवादियों के खाकी वर्दीधारी गुण्डा गिरोह के हाथों भंयकर यातनायें सहते हुए शहीद हो गए थे। कॉमरेड सी. एम. और नव जनवादी क्रांति की राह में जिन्होंने आपनी जान न्यौछावर की उन सबकी याद में 1988 से पूरे भारत में शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। दण्डकारण्य में इस बार भी इसे व्यपाक स्तर पर मनाया गया। पेश हैं अलग–अलग डिवीजनों की रपटें।

दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन

इसी कड़ी में दक्षिण गड़चिरोली के भामरागढ़ में 3 स्थानों पर पेरिमिलि में 2 स्थानों पर व अहेरी में 1 जगह पर शहीद सप्ताह के तहत आम सभायें की गईं। और प्रचार अभियान चलाया गया । भामरागढ़ इलाके में सिमेन्ट के 12 स्मारकों का निर्माण किया गया जिसमें जनता और जन मिलिशिया ने बड़ी सख्या में भागीदारी की। सैकड़ों पोस्टर, पर्चों व तीस के लगभग बैनरों से पूरे इलाके में प्रचार किया गया व पुराने स्मारकों को भी रंग– रोगन करके सजाया गया। रोड के गांव में दीवार–लेखन किया ।

भामरागढ़ में सभा को कॉमरेड कविता ने, गट्टा में कॉमरेड कन्ना ने सम्बोधित किया, वहीं पेरिमिलि में जनताना सरकार के अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। अहेरी एरिया में जनसभा की अध्यक्षता कॉमरेड मीना ने की और स्मारक का अनावरण कॉमरेड सबिता ने किया।

जन सभाओं में शहीदों की याद में दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रंद्धंजली अर्पित की गई। बाद में चेतना नाट्य मंच के कलाकारों नें जोश भरे गीत गा कर शहीदों को याद किया। वक्ताओं ने रानीबोदली में जान कुर्बान कर इतिहास रचने वाले योद्धाओं से प्रेरणा लेने और दुश्मन के दमन का डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया। कॉमरेड विकास और कॉमरेड आयतु के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं जनता ने भी अपने–अपने आरपीसी में शहीद सप्ताह मनाया, जिसमें अलग–अलग सभाओं में 1500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इनकी अध्यक्षता जनताना सरकार के प्रतिनिधियो नें की ।

उत्तर गड़चिरोली डिवीजन

उत्तर गड़चिरोली में भी शहीदी सप्ताह मनाया गया। चादगांव एरिया में 2 व टीप्रागढ़ इलाके में 4 स्मारकों का निर्माण किया गया। टिप्रागढ़ में का. सुन्नो, कॉमरेड विकास, कॉमरेड गीता, कॉमरेड आयतु के नाम पर बनाए गये। आम सभाओं का आयोजन डीकेएमएस व डीकेएएमएस की तरफ से किया गया। इसकी तैयारी कई दिनों पहले शुरू की गई जिस में चार टीमें बना कर प्रचार चलाया गया, गीतों, पोस्टरों व पर्चों के माध्यम से लोगों को सभाओं में भाग लेने का आव्हान किया गया। तमाम जनताना सरकार गांव में भी मनाये जाने की खबरें है।

पोटेगांव ऐरिया : तीन जगहों पर स्मारकों का निर्माण करके शहीद सप्ताह मनाया गया। इनमें से एक लकड़ी का स्मारक पोटेगांव कैम्प से केवल 300 मीटर की दूरी पर शहीद स्मारक का निर्माण कर जनता ने बहादुरी का परिचय दिया और पुलिस दमन को करारा जवाब दिया। कुल तीन स्थानों पर सभायें की गई जिनमें सैकड़ों जनता ने हिस्सा लिया।

चादगांव एरिया में शहादत सप्ताह बड़े पैमाने पर मनया गया। पूरे सप्ताह तक विभिन्न जन संगठनों द्वारा गांव-गांव में घूमकर प्रचार अभियान चलाया गया जिसमें गीतों के साथ-साथ 580 पोस्टर और आठ बैनर लगाये गये। इस अवसर पर हुई सभा में कुल 1000 जनता ने भागीदारी की और 2 सिंमेट के शहीद स्मारकों का निर्माण किया गया। साथ में कुछ जगह पर लकड़ी के स्तम्भ बनाकर शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित की गई। जनता ने भी अपने-अपने स्तर पर सभाओं का आयोजन किया।

उतर बस्तर डिवीजन

रावघाट एरिया में पूरा सप्ताह जोशोखरोश के मनाया गया। पूरे एरिया में आठ जगहों बड़े–बड़े सींमेंट के आठ स्मारक बनाये गये। हर समारक रानीबोदली के ऐतिहासिक हमले में शहीद हुये कॉ. मोहन, कॉ. कैलाश, कॉ. लिंगन्ना कॉ. भीमाल, कॉ. भगत और कॉ. चैतू के नाम से बनाये गये। केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड बीके, कॉ. प्रसाद और कॉ. सोमन्ना व बीके के साथ शहीद हुई कॉ. करूणा को नम आंखों से श्रद्धांजली अर्पित की गई। हर सभा में गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करने, जनता की राजसत्ता का निर्माण करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने इसे जन योद्धाओं को सच्ची श्रद्धांजली बताई और उनके नक्शेकदम पर

चलकर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये जनता से आहवान किया।

'कहीं भी शहीद सप्ताह नहीं मनाने देंगे' इस इरादे से दुश्मन ने पूरे सप्ताह अतिरिक्त बल को बुलाकर गश्त को तेज किया। लेकिन पुलिस जनता के जंगी हौसलों को परास्त करने में नाकाम रही। गांव घुमूर की जनता ने कई दिनों की सामूहिक श्रम से शहीद स्मारक का निर्माण किया पुलिस और सीआरपी के गुण्डों ने आकर उसे गिरा दिया लेकिन जनता ने अगले ही दिन दुगनी ताकत से स्मारक का पुनःनिर्माण करके शहीदों को श्रद्धांजली दी। याद रहे इसी साल की शुरूआत में इस गांव की दो छोटी–छोटी लड़कियों को झूठी मुठभेड़ में निर्मम हत्या कर डाली थी। पीएलजीए की सुरक्षा में कार्यकमों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

एरिया में कार्यकमों में भाग लेने वाली जनता : महीलायें 1510, पुरूष 1471, छात्र व बच्चे 3386।

प्रचार टीमें कुल– 31, जिनमें डीएकेएमएस की 12 टीमें और 92 सदस्य, केएएमस की 8 टीमें और 70 सदस्य, सीएनएम की 11 टीमों के 112 सदस्यों ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। प्रचार में 1370 पोस्टर, 79 बैनर और 9 जगहों पर कपड़े से स्मारकों का निर्माण किया गया।

प्रतापुर एरिया में जगहों पर स्मारकों का निर्माण किया। दुर्गकोंदुल से कोयलीबेड़ा जाने वाली सड़क पर कपड़ा से 6 जगह स्मारक बनाये गये। इस इलाके में भी दुश्मन ने न मनाने देने की भरसक कोशिश की झाड़कट्टा गांव के अंदर स्मारक को गिराया गया। जनता ने तुरंत दूसरा बनाकर पुलिस दमन का मुंहतोड़ जवाब दिया। जन मिलिशिया की टुकड़ियां पुलिस से टक्कर लेने के लिये तेनात खड़ी थीं।

कार्यक्रमों में शामिल हुई जनता : महिलायें– 721, पुरुष 1941, छात्र व बच्चे 281 – कुल 2949।

प्रचार टीमें डीएकेएमएस की 10, सदस्य 51 , केएएमएस की 6 टीमें, सदस्य 81, सीएनएम की टीमें 8 और सदस्य 61।

मानपुर डिवीजन

मानपुर डिवीजन के औंधी इलाके में आयोजित एक शहीद सभा में 5 गांवों के लोगों ने भाग लिया। लाल झण्डे हाथों में लेकर कतारबद्ध होकर लोगों ने जुलूस निकाला। इसमें स्थानीय गुरिल्ला दस्ता और सीएनएम की टीम ने भाग लिया। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर बनाए शहीद बालकृष्ण और करुणा के स्मारक तक जुलूस पहुंचा। शहीदों के नाम पर लगाए नारों से जंगल–पहाड़ गूंज उठे। कॉमरेड हरसू ने स्मारक का अनावरण किया और कॉमरेड मन्नेसिंग ने झण्डा फहराया। ये दोनों कॉमरेड स्थानीय जन संगठनों के नेता हैं। गौरतलब है कि इस इलाके में शहीद–स्मारक का पहली बार निर्माण हुआ है।

सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड समीला ने हमारी पार्टी के संस्थापक–नेता और महान शिक्षक कॉमरेड चारू मजुमदार और कॉमरेड कन्नाई चटर्जी की जीवनियों और संशोधनवाद के खिलाफ उनके संघर्ष पर रोशनी डाली। मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था को बदले बिना महिला की मुक्ति असंभव बताते हुए उन्होंने कई महिला योद्धाओं की जीवनियों पर रोशनी डाली जिन्होंने इस देश को शोषण और उत्पीड़न से आजाद करने की खातिर अपनी जानें कुरबान कीं। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि पीएलजीए में बड़ी संख्या में भर्ती होवें। बाद में कुछ अन्य कॉमरेडों ने भी सभा को संबोधित किया। इस सभा में 150 महिलाओं समेत कुल 350 लोगों ने भाग लिया।

इसी डिवीजन के डोरकट्टा सेन्टर में भी 7 गांवों की जनता ने शहीद दिवस मनाया। 3 अगस्त को आयोजित शहीद सभा में कुल 400 लोगों ने भाग लिया जिसमें महिलाओं की संख्या 40 थी। तोड़के सेंटर में आयोजित शहीद सभा में 5 गांवों से 255 लोगों ने भाग लिया। सेंडावाही सेन्टर में आयोजित सभा में 5 गांवों से करीब 400 लोगों ने भाग लिया। इस सभा का आयोजन जन संगठनों के नेताओं की अगुवाई में हुआ। पारडी सेन्टर में हुई सभा मे करीब 350 लोगों ने भाग लिया जिनमें 100 महिलाएं शामिल थीं।

शहीद सप्ताह का प्रचार कार्यक्रम इस पूरे इलाके में बड़े जोरदार ढंग से किया गया। कुल 6 प्रचार टीमों ने गांव–गांव जाकर शहीद सप्ताह के महत्व के बारे में लोगों को समझाया। गांवों में करीब 400 पोस्टर, सैकड़ों पर्चे और 30 बैनर लगा दिए गए। सीएनएम की दो टीमों ने प्रचार कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। ★

किताबें आ गई हैं...

"लुटेरों के मुनाफे के लिए विस्थापन मंजूर नहीं!"
– 'सेज और विस्थापन विरोधी मंच' का प्रकाशन

"हरी–भरी जिन्दगी पर कहर बरपाता राज्य!"
(सलवा जुडूम के तौर–तरीकों पर एक नजर)
– बी.डी. दमयन्ती

जरूर पढ़िए! पढ़ाइए!!

पीएलजीए के शौर्यपूर्ण हमलों से धधकता दण्डकारण्य

दुश्मन के घेरे पर घेरा

ताड़मेट्ला में पुलिस बलों पर पीएलजीए का जबरदस्त हमला

29 अगस्त 2008 : एक तरफ राज्य और केंद्र सरकारें 'सब कुछ खत्म कर डालो' के इरादे से जनता का घेराव कर भयंकर दमन अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ पीएलजीए हजारों जनता की मदद से दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रही है। उसके घेरे पर घेरा डाल कर उनके नापाक इरादों पर पानी फेर रही है।

15 अगस्त झूठी आजादी के दिन कोया भूमकाल मिलिशिया और जन मिलिशिया की 20 पलटनों के सैकडों कॉमरेडों और जनता कुल मिलाकर 1010 लोगों ने दक्षिण बस्तर डिवीजन में ताड़मेट्ला रोड़ को सैकड़ों जगह गड्ढ़े खोदकर तहस-नहस कर दिया। और 24 घंटे तक अपने कब्जे में रखा।

यह दुश्मन के लिये डाला गया चारा था। 29 अगस्त की दोपहर को शिविरों में रह रही जनता को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुये 35 सीएसएफ, डीएफ और एसपीओ की संयुक्त टुकड़ी रोड को चालू करवाने के लिये निकली।

पीएलजीए के योद्धा भी कई दिनों से इसी इंतजार में बैठे थे। जन मिलिशिया से खबर मिलने की देर थी कि लाल सैनिक भाड़े के सैनिकों को घेरने के लिये निकल पड़े। दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करते हुये उनके 12 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें जनता के दमन के लिये बदनाम थानेदार हेमंत मड़ावी भी था। और 4 पुलिस वालों को गंभीर घयाल कर दिया गया। दुश्मन के 14 हथियार, जिसमें 1 एके-47, 6 एसएलआर, 5 श्रीनाटश्री एक इंसास राइफल। एक टु इंच मोर्टार का अपने कब्जे में ले लिया गया। हेमंत मड़ावी के मर जाने से जनता में खुशी की लहर दौड़ गई।

पामुलवाई में भाड़े के सैनिकों पर पीएलजीए के दो शानदार ऐम्बुश

पश्चिम बस्तर डिवीजन के बीजपुर जिले में गंगलूर रोड पुलिस बलों पर पीएलजीए के हमलों के लिए प्रसिद्ध है। सलवा जुडूम के शुरू होने के बाद इस रोड पर स्थित सारे गांवों का दमन कर लोगों को 'राहत' शिविरों में जाने पर मजबूर करने से यह रोड शत्रु बलों के लिए आसान हो गया। दुश्मन की 'कार्पेट सेक्यूरिटी' की योजना के अंतर्गत हर 5 किलोमीटर में एक पुलिस कैम्प और शिविर खोला गया। रोड के दोनों तरफ 70-80 गज दूर तक फैला हुआ जंगल पूरा कटवा दिया गया ताकि पीएलजीए बलों को ऐम्बुश के लिए बैठने की कोई जगह नहीं मिल सके। इसके अलावा पिछले एक साल से इस रोड पर पीएलजीए की तरफ से कोई खास प्रतिरोध भी नहीं होने के कारण भी पुलिस व जुडूमी बल बेखौफ होकर आने-जाने लगे थे। इसी का फायदा उठाकर पीएलजीए ने शत्रु बलों पर हमले की योजना बनाई। इसके लिए उसने ऐसी जगह चुनी जहां जंगल कटने के बावजूद झाड़ियां उग चुकी हैं और जो पामुलवाई पुलिस कैम्प से मात्र एक किलोमीटर दूर है। एक बार नहीं दो-दो बार सफल हमले कर पीएलजीए ने यह साबित किया कि अगर जनता का समर्थन उसे हासिल है तो जनता की असीम ताकत पर निर्भर करते हुए वह जब चाहे तब और जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से हमले कर सकती है। चूंकि पीएलजीए जनता की सेना है, इसी में उसकी ताकत छिपी हुई है।

29 अक्टूबर 2007 (पहला ऐम्बुश) : एके, एसएलआर, एलएमजी, आदि अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुश्मन के भाड़े के बल कुल 20 की संख्या में रोड ओपनिंग के नाम से बीजापुर से निकल पड़े थे। सुबह के साढ़े दस बज रहे थे। स्काउट से इसकी खबर मिलते ही पीएलजीए के लाल सैनिक तैयार हो गए। अपने-अपने पोजिशनों में मुस्तैदी से दुश्मन का इंतजार करने लगे थे। उन पर कहां और कैसे धावा बोलना है इसकी योजना पहले ही तैयार हो चुकी थी। एक महिला कॉमरेड ने अपनी रायफल से गोली दागकर ऐम्बुश शुरू किया। बस, चारों तरफ से लाल योद्धाओं ने

गड़चिरोली में पीएलजीए की कुछ कार्रवाइयां

- 31-10-07 को गडचिरोली डिवीजन के कासनसुर से जारावंड़ी जाने वाले रोड पर पीएलजीए बलों ने घात लगाकर कर गड़चिरोली कमांडो बलों पर हमला किया। इस हमले में 7 कमांडो घयाल हुये जिसमें बदमाश कमांडो देवाजी कोवासी भी शामिल था।
- उसीर टोला में 3 कामरेडों की एक टीम नें सिंगल एंबुश किया। दुश्मन की जीप के परखचे उड़ गये लेकिन इसमें एक ही कमांडो मर पाया। बाकी बचे हुये पुलिस वालों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं मगर हमारे कामरेड सुरक्षित रिट्रीट हो गये।
- पेरिमिलि साप्ताहिक बाजार में 2 कामरेडों की एक्शन टीम ने एक पुलिस वाले को मार गिराया और उसकी एसएलआर अपने कब्जे में ले ली। साथ में उसके 20 कारतुस भी जब्त कर लिये। दूसरा पुलिस वाला घबरा कर भाग खड़ा हुआ। इस घटना से पुलिस दमन से त्रस्त जनता का मनोबल बढ़ा है।
- चंद्रा सिंगल एंबुश : भाम्रागढ़ से अल्लापल्ली जाने वाले रोड़ पर पीएलजीए की एक एक्शन टीम ने घात लगाकर हमला किया और जबरदस्त माईन का विस्फोट किया जिसमें 5 कमांडो बल घायाल हुये।

गोलियां बरसाते हुए बिजली सी तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़ने लग पड़े। दुश्मन सम्भल ही नहीं पाया, मौके पर ही 5 की मौत हुई और 8 अन्य घायल हुए। पीएलजीए के तेवरों को देख बचे हुये भाड़े के सैनिकों के हौसले पस्त हुए और बदहवास भागना शुरू किया। लाल योद्धा उन्हें करीब एक किलोमीटर दूर तक दौड़ाया। पामुलवाई कैम्प महज एक किलोमीटर दूर पर मौजूद होने के बावजूद भाड़े के सैनिकों ने उसमें से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं की। दुम दबाकर उसी के अंदर रह गए। दरअसल जनता की हत्या करने में, गांवों को जलाने में, सम्पत्तियों को लूटने में और महिलाओं के साथ पाशविकता बरतने में ये लोग बड़ी 'बहादुरी' दिखाते हैं पर जब पीएलजीए के प्रतिरोध का सामना करने की बारी आती है तो उनकी कायरता साफ दिखाई देती है। इसका कारण भी साफ है कि वो भाड़े के सैनिक हैं। उनका कोई राजनीतिक-सैद्धांतिक लक्ष्य नहीं है। बस, नौकरी करनी है और अधिकारी जो बताते है वो करना है उन्हें।

बहरहाल, इस सफल हमले के बाद पीएलजीए 6 इंसास और 2 थ्रीनाटथ्री रायफलें लेकर सकुशल लौट गई।

12 नवम्बर 2007 (ऐम्बुश) : पहले ऐम्बुश के बाद शत्रु बलों ने अपने रोड ओपनिंग के तौर-तरीकों में कई बदलाव किए। फिर भी उसे रोड ओपनिंग तो करना ही है। कभी रोड पर से तो कभी रोड के बगल खेतों से तो कभी जंगल के अंदर से आना-जाना करने लगे थे। सीआरपीएफ वाले भी मोटर सायकलों पर गश्त करने लगे थे। पीएलजीए के कमाण्डरों ने जनता की मदद से इसका बारीकी से अध्ययन किया। दो हफ्ते के अंदर ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पार्टी पर फिर एक हमला किया जा सकता है। तत्काल योजना तैयार की गई और 12 नवम्बर की शाम के 4 बजे सीआरपीएफ के मोटार सायकल काफिले को निशाना बनाया गया। जगह को लेकर इधर-उधर होने के कारण बाकी पुलिस वाले पार हो चुके थे। सिर्फ एक ही मोटार सायकल बचा हुआ था जिस पर तीन पुलिस वाले बैठे हुए थे। उन्हें मार गिराकर उनकी तीनों हथियार (एक एलएलजी और दो एसएलआर) छीन लिए।

तोंगुड़ में शनदार ऐम्बुश
11 पुलिस वालों का सफाया

2 नवंबर 2008: बीजापुर जिले के पामेड़ थाना से आंध प्रदेश के चेरला थाना के अंर्तगत से रसद-सामग्री लेने के लिए पुलिस हर रोज आना जाना करती थी। पामेड़ थाना उन 4 थानों में से एक है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हमलों के डर से कुछ भी नहीं पहुंचा पा रही है। हालत यह है कि हैलिकाप्टरों से राशन पहुंचाना पड़ रहा है। पामेड़ व चेरला थाना के समन्वय के लिए एक कच्चा रोड है जिसके दोनों ओर से 100-100 गज तक पेड़ काट दिये गये हैं। पुलिस जहां पर मिलती है उसी मैदान में पीएलजीए ने एंबुश लगाने की योजना बानाई। ठीक 2 बज कर 20 मिनट पर पुलिस का एक 21 जवानों का दल आया जिस पर लाल योद्धाओं ने जबरदस्त हमला कर 11 पुलिस वालों को मार डाला और 11 हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में लिया। डेढ़ घंटे तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। अंतत: बाकी बचे हुये पुलिस वाले भाग खड़े हुये। 11 हथियारों में 1 एके -47 (4 मेगजीन-84 कारतुस), एसएलआर-2 (कारतुस-196, मेगजीन-4), थ्रीनाटथ्री -2 (57 कारतुस), इंसास-5 (375 कारतुस व 21 मेगजीन) और एलएमएजी -1 (4 मेगजीनें) हैं।

पीएलजीए के इस जबरदस्त हमले ने जहां जनता में जोश का संचार किया, वहीं दुश्मन द्वारा रोड के दोनों तरफ पेड़ काटकर खुले आने जाने पर रोक लगा दी। और उसके मनोबल को चकनाचूर कर दिया। 'प्रभात' पीएलजीए के लाल योद्धाओं को इसके लिये लाल सलाम पेश करती है। जनता की सुरक्षा व सलवा जुडूम को हराने के लिए ऐसे हमलों की अनवरत कड़ी की आशा करती है।

गादेराज में पुलिस पर हमला
एक मरा और दो हथियार जब्त

2 दिसम्बर 2008 - 2 दिसंबर हमारी पीएलजीए की सातवीं वर्षगांठ का दिन। हमारे प्यारे शहीद-नेता कॉमरेड श्याम, महेश और मुरली का शहादत दिवस। दरभा डिवीजन के पीएलजीए योद्धाओं ने इसे शानदार ढंग से मनाते हुए एक हवलदार को मार गिराया, एक एएसआई को घायल किया और उनसे एक एके-47 और एक थ्रीनाटथ्री रायफल छीन लीं। उस दिन गादेराज में हाट बाजार चल रहा था। पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने सुनियोजित तरीके से उस जगह को चुन लिया। विभिन्न बलों के कुछ योद्धा पहले से बाजार पहुंचकर पूरी स्थिति का मुआयना किया। उनके पास थे कुछ चाकू और एक-दो देशी पिस्तौल। एक एएसआइ और एक हवलदार जब खरीदारी में व्यस्त थे और बाकी पुलिस वाले कुछ दूर पर थे, बस, इस मौके को हाथ से न जाने देने की सोच कर लाल सैनिक उन पर टूट पड़े। हवलदार का तो पलों में ही सफाया हो गया। पर एएसआई से कुछ समय तक ध क्का-मुक्की होती रही। पर थोड़ी देर के प्रतिरोध के बाद वह भी पीएलजीए योद्धाओं के मजबूत इरादों और लड़ाकूपन के सामने घुटने टेक दिए। बाद में हमारे कॉमरेड 'पीएलजीए जिंदाबाद', 'भाकपा (माओवादी) जिन्दाबाद', 'कॉमरेड श्याम-महेश-मुरली अमर रहें' आदि नारे लगाते हुए विजयोल्लास के साथ लौट आए। बाकी पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए घटना स्थल से तेजी से थाने की तरफ भागे। और बाजार में मौजूद जनता पीएलजीए की इस कामयाबी और पुलिस वालों की कायरता की गवाह रही।

सलवा जुडूम की रीढ़ पर चोट
जन दुश्मन बुधराम राणा का सफाया

बुधराम राणा ही है जिसने बीजापुर क्षेत्र की हजारों जनता को यातना शिविरों में धकेलने में खास भूमिका निभाई, जिसने गांव के गांव उजाड़ दिये। खेत में खड़ी फसलों को आग के हवाले कर दिया। महिलाओं के साथ अत्याचार करवाये। बीजापुर क्षेत्र की जनता ही उसके आंतक को जान सकती है। यही वजह है कि जब उसे 19 नवंबर 2007 की सुबह 9 बजे मौत के घाट उतार दिया तो पूरे इलाके की जनता ने मुर्गे-बकरे काट कर त्यौहार मनाया।

बुधराम राणा 2003 से ही जन विरोधी कार्रवाइयों में शामिल होने लगा था। जब उसे कांग्रेस पार्टी ने अपना तहसील अध्यक्ष

बनाया तभी से जनता से रिश्वत लेना, नौकरी का लालच देकर पैसे वसूलना शुरू किया था। जून 2005 में जब उसके आका महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में सलवा जुडूम फासीवादी हमला शुरू हुआ तो वह उसके मुख्य सरगना के रूप में उभर कर सामने आया। इसे सलवा जुडूम का बीजापुर जिला अध्यक्ष बनाया गया था। गुंगलूर और बीजापुर क्षेत्र में सलवा जुडूम को फैलाने में इसी जालिम का बड़ा हाथ था। 2005 जून के बाद उस एरिया में जितनी भी घटनायें हुईं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुधाराम राणा जरूर शामिल रहता था। यही वजह है कि उसकी सुरक्षा में 5 पुलिस वाले और 20 एसपीओ गुंड हमेशो तैनात रहते थे।

बुधराम राणा को मारने के लिये जनता ने हर जगह से आवाज उठाई थी। और बहुत सी कोशिशें की थीं। तमाम सुरक्षा के बाद भी बुधराम राणा को एक्शन टीम के तीन कामरेडों, जन मिलिशिया और जनता ने मिलकर उसके गांव के पास ही उसे मोटरसाईकल पर आते हुये धर दबोचा, जब वह बिना किसी सुरक्षा के ही आ रहा था। तपंचे की पहली ही फायरिंग से उसका मोटरसाईकल लुढ़क गया। कुछ ही मिनटों के अंदर उसका काम तमाम करके 35 के करीब जनता और जन मिलिशिया कॉमरेड नारे लगाते हुये लौट गये।

बुधराम राणा के मरने की खबर को गांव-गांव में पहुंचने में देर नहीं लगी। हर गांव में उत्सव सा महौल था। जनता अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। वो कितने ही सुरक्षा में रहें लेकिन जनता चुन-चुन कर उनसे उनके जुल्मों का हिसाब वसूल करती है। इसके सफाए के बाद बीजापुर से लेकर रायपुर तक प्रतिक्रियावादी खेमे में हड़कम्प मच गई। महेन्द्र कर्मा, रमन सिंह आदि नेता हड़बड़ा गए क्योंकि इसे कर्मा के बाद सलवा जुडूम दूसरे नम्बर का सरगना माना जाता था।

जनता द्वारा सलवा जुडूम सरगना शिखा मांझी की फसल जब्त

27 अक्टूबर 2007 की एक शाम। फसल कटाई का सीजन। पश्चिम बस्तर डिवीजन के गंगलूर पुलिस थाने से लगे 10 गांवों की जनता एक जगह इकट्ठी हुई। स्त्री-पुरुष सब मिलकर 450 लोग थे। सभी को ठीक से सूचना नहीं मिल पाई थी, वरना और 4-5 सौ लोग आने वाले थे। वे सब हाथों में हंसिए लेकर पार्टी की गंगलूर एरिया कमेटी के इस आह्वान पर वहां इकट्ठे हुए थे कि जुडूम का जालिम नेता और गंगलूर 'राहत' शिविर का मुखिया शिखा मांझी की धान की फसल को जब्त किया जाए।

गंगलूर एरिया में जबसे सलवा जुडूम का विस्तार हुआ तबसे शिखा मांझी मुख्य भूमिका निभा रहा है। यह जुडूम के बीजापुर जिले के प्रमुख सरगनाओं में से एक है। शिखा इस इलाके का एक जालिम जमींदार और बदनाम कबीलशाह है। इस इलाके की जनता पर इसका कई रूपों में शोषण, जुल्म और अत्याचार चलते थे। जब इस इलाके में जनयुद्ध तेज हुआ तब यह दब सा गया था। लेकिन ज्यों ही जुडूम शुरू हुआ यह अपने वर्गीय चरित्र के अनुसार ही न सिर्फ उसमें शामिल हुआ, बल्कि उसका मुख्य सरगनाओं में से एक बना। गंगलूर इलाके में जुडूम के शुरू होने के बाद से गांवों पर किए गए हमलों, घर जलाने, संपत्तियों को लूटने, लोगों को काट-काट कर मार डालने और महिलाओं पर किए गए तमाम अत्याचारों के लिए यह खुद जिम्मेदार है। गंगलूर में स्थापित तथाकथित राहत शिविर का यही मुखिया है। गांव की पूरी जनता इसके खिलाफ है, इसलिए सरकार ने इसके खेतों को ट्रैक्टरों से जुतवाया। इस इलाके में इसके और इसके गुण्डों-एसपीओ और पुलिस बलों द्वारा मचाए गए आतंक का बदला लेते हुए जनता ने फैसला लिया कि इसकी सारी फसल काट ली जाए।

गंगलूर पुलिस थाने में 200 पुलिस वाले रहते हैं। इसके अलावा एसपीओ और जुडूमी गुण्डे भी रहते हैं। इसके बावजूद उन सभी की आंखों में धूल झोंककर थाने से महज 3-4 सौ गज की दूरी पर स्थित शिखा के खेतों में जाकर लोगों ने सारी फसल काट लाई। सटीक योजना के मुताबिक 10-10 लोगों की संतरी टीमें अलग-अलग दिशाओं में पहरा देती रहीं ताकि दुश्मन के किसी भी संभावित हमले को नाकाम कर जनता को सुरक्षा पहुंचाइ जा सके। अंधेरा होते ही सभी लोग, जिनका नेतृत्व जनताना सरकार, जन मिलिशिया और जन संगठनों के नेता कर रहे थे, सब खेतों में गए। रात भर में उसके 4 एकड़ खेत में फसल पूरी तरह काट डाला। पौ फटने से पहले ही सभी धान के बोझा सिर पर लेकर वापस लौट गए। बाद में सभी ने उसकी मिंजाई कर अनाज को आपस में बांट लिया। एक-एक परिवार को ढाई पायली अनाज मिला। गौरतलब है कि इस फसल जब्त कार्रवाई में कुल 150 महिलाओं ने भाग लिया। भारी संख्या में तैनात पुलिस बलों की नाक के नीचे हुई इस जन कार्रवाई ने जनता के दुश्मनों को झकझोर कर रख दिया। ★

(...पृष्ठ 32 का शेष)

में गिरफ्तार किया गया। वहीं बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का बचाव किया जा रहा है। जेल के कर्मचारियों और छोटे अधिकारियों के साथ सरकार के इस भेदभावपूर्ण एवं तानाशाहाना रवैये की हमारी स्पेशल जोनल कमेटी कड़ी निंदा करती है।

इस जेलब्रेक के बहाने प्रदेश के अन्य जेलों में बंद हमारे कॉमरेडों समेत तमाम अन्य कैदियों का दमन करने की साजिश रची जा रही है। उन्हें सारे विधिसम्मत अधिकारों से वंचित कर जेलों को फासीवादी बंदी शिविरों में बदलने के प्रयास चल रहे हैं। उन्हें कोई कानूनी सहायता भी न मिले, ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बार-बार तलाशी के नाम से उन्हें मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। हम प्रदेश की मेहनतकश जनता और लोकतंत्र के प्रेमियों से अपील करते हैं कि जेलों में बंद कैदियों पर जारी सरकारी दमन का विरोध करें। हम यह भी अपील करते हैं कि आप सरकार से मांग करें कि जेलों में बंद तमाम क्रांतिकारियों को 'राजनीतिक बंदी' का दर्जा दिया जाए।

(कोसा)
सचिव
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (माओवादी)

(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (माओवादी)

गोल्लापल्ली ऐम्बुश– दुश्मनों के दिलों में हड़कम्प

इस शौर्यपूर्ण ऐम्बुश में अपनी जानें कुरबान करने वाले जांबाज लाल योद्धा कॉमरेड्स बामन, सुक्कू और उंगाल को लाल-लाल सलाम!

सलवा जुडूम के नाम से जारी पाशविक दमन अभियान में दक्षिण और पश्चिम बस्तर में अभी तक सैकड़ों आम जनता की हत्या की गई। इस जुल्मी अभियान से जनता और जनताना सरकार के बचाव के लक्ष्य से जनता और पीएलजीए द्वारा जारी प्रतिरोध की कार्रवाइयों ने दुश्मन को लगातार बैक फुट पर रखा हुआ है। इसीलिए जनता के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से तीखे दमन के बीचोबीच भी दुश्मन पर लगातार सफल हमलों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 20 दिसम्बर को दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा तहसील के दायरे में गोल्लापल्ली के पास पीएलजीए के विभिन्न बलों ने पुलिस बलों पर एक शानदार हमला किया। सीएएफ और जिला पुलिस के कुल 28 भाड़े के जवानों का दल जब किष्टारम की तरफ से आ रहा था, तभी पीएलजीए ने उन पर घात लगाकर हमला बोला। इस शौर्यपूर्ण हमले में पुलिस के कुल 12 भाड़े के जवानों का सफाया किया गया और उनसे 12 आधुनिक हथियार छीन लिए गए। एक एके-47 और 11 एसएलआर के साथ-साथ सैकड़ों गोलियां पीएलजीए के हाथों में आ गईं। बाकी बचे पुलिस वाले कुछ देर तक लड़ते रहे पर पीएलजीए के लाल सैनिकों के बुलंद हौसलों के सामने जल्द ही उनके पैर उखड़ गए।

पर इस शानदार उपलब्धी में हमारे तीन बहादुर कॉमरेडों - बामन (सेक्शन कमण्डर), सुक्कू (सेक्शन उप-कमाण्डर) और उंगाल (लाल सैनिक) की गर्म खून बहा हुआ है। इन्होंने अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं करते हुए जनता की मुक्ति के लिए मुस्कुराते हुए अपनी जानें दीं। अदम्य साहस और अनुपम पराक्रम का सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए इन कॉमरेडों ने पीएलजीए के गौरवशाली लाल झण्डे की लालिमा बढ़ा दी। एक के बाद एक कार्रवाई में दुश्मन से लड़ते हुए अनमोल अनुभव को हासिल कर चुके इन कॉमरेडों ने अपनी इस आखिरी लड़ाई में भी उन्नत स्तर की वीरता का प्रदर्शन किया। दुश्मन की तरफ से हो रही गोलियों की बौछार के बीचोबीच ही आगे बढ़ते हुए उसका सफाया करने के दौरान ही ये तीनों माटी पुत्रों ने अपना खून बहा दिया। (इन कॉमरेडों की जीवनियों पर विस्तृत रिपोर्ट हम अगले अंक में पेश करेंगे - सं)।

इस हमले के बाद पुलिस के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पूरे 48 घण्टे लग गए। इससे यही जान पड़ता है कि बड़े-बड़े नरसंहार रचकर आसानी से सैकड़ों निरीह जनता की जानें लेने वाले पुलिस अधिकारी दरअसल कितने कायर हैं। यहां तक कि मीडिया के पत्रकारों ने घटनास्थल पर जाने की हिम्मत की, पर बड़बोले पुलिस अधिकारी तो रायपुर और जगदलपुर में ही बैठकर उग्र बयानबाजी तक सीमित होकर रह गए। इस हमले ने इस इलाके की जनता को जबर्दस्त प्रेरणा दी और उनका हौसला बढ़ाया।✶

विश्रामपुरी थाने पर पीएलजीए का रेड

पुलिस के तीन जवानों का सफाया - एक घायल

12 दिसंबर 2007 को पीएलजीए के लाल सैनिकों ने अपने संघर्ष के इलाके से करीब 50-60 किलोमीटर बाहर जाकर एक पुलिस थाने को निशाना बनाया। बस्तर जिले के बड़े राजपूर तहसील के बिश्रामपुरी थाने पर रात के करीब 8 बजे एक पलटन की संख्या में पीएलजीए के योद्धाओं ने धावा बोल दिया। इत्तेफाक से ही सही, उसी दिन डीजीपी विश्वरंजन का यह बयान आया था कि वे अब संघर्ष के इलाकों के अंदर तक घुसकर नक्सलवादियों को मार डालेंगे।

उस समय थाने में सिर्फ 4 पुलिस वाले मौजूद थे। करीब एक महीने पहले ही इस थाने से सरकार ने सारे हथियार वापस ले लिए थे क्योंकि उसे डर है कि हथियार रहने से माओवादी गुरिल्ले हमला कर सकते हैं और उन्हें छीन सकते हैं। अंदर घुसते ही पीएलजीए के सैनिकों ने गोलियां बरसा दीं जिसमें तीन पुलिस वाले मौके पर ही मारे गए और एक घायल हुआ। कुछ ही मिनटों में इसे पूरा करके पूरे थाने की तलाशी ली। एक रिवाल्वर और वाकी-टाकी सेट कब्जे में लिया।

इस हमले का जबर्दस्त असर रहा। पीएलजीए के सैनिकों ने पहली बार रायपुर-जगदलपुर हाइवे को पार कर इस हमले को अंजाम दिया। यह इलाका अभी तक संघर्ष के क्षेत्र के दायरे से बाहर रहा। यहां पर वन विभाग, पुलिस, ठेकेदारों और प्रतिक्रियावादियों का दबदबा है। शोषण और उत्पीड़न से आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता बुरी तरह परेशान है। लोग चाह रहे हैं कि यहां पर भी पार्टी आए और उन्हें संघर्ष में संगठित करें। ज्यों ही पुलिस थाने पर पीएलजीए के हमले की खबर फैल गई शोषित जनता के बीच उत्साह का संचार हुआ। इस हमले के जरिए पीएलजीए ने इस क्षेत्र की जनता में शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के लिए सशस्त्र लड़ाई की जरूरत का पैगाम पहुंचाया। वहीं प्रतिक्रियावादी खेमे में इस हमले से खासी खलबली मच गई। सरकार को पुलिस जवानों की जान से ज्यादा हथियारों की फिक्र है, आदि आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मुखिया इस बात से ज्यादा चिंतित नजर आए कि पीएलजीए जब चाहे तब और जहां चाहे वहां जाकर उन पर हमला कर सकती है। ✶

मुरलीगुड़ा के पास मिजो जवानों की मौत के लिए केन्द्र व राज्य सरकार जिम्मेदार !

सलवा जुडूम बंद करो! मिजो और सीआरपीएफ बटालियन वापस भेजो!!

29 नवम्बर 2007 के दोपहर दो बजे दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) जिले के कोंटा तहसील के मुरलीगुड़ा के निकट हमारी पीएलजीए ने आतंकी मिजो जवानों पर एक जबर्दस्त हमला कर 10 को मार गिराया और 7 सारे हथियार छीन लिए। छीने गए हथियार - पांच एके-47 (12 मैगजीन, 230 गोलियां) और दो स्टेनगन (41 कारतूस)। स्थानीय जनता की मांग पर और उसके सक्रिय सहयोग से इस हमले को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी इस हमले को सफल बनाने वाले पीएलजीए के विभिन्न बलों के कमाण्डरों और लाल योद्धाओं तथा उस क्षेत्र की संघर्षशील जनता का लाल-लाल अभिनन्दन करती है। साथ ही साथ, हमारी कमेटी यह ऐलान करती है कि इनकी हत्याओं के लिए केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है। हमें अफसोस है कि इस घटना में 10 मिजो जवानों के साथ-साथ एक वाहन चालक और उसके एक किशोर सहायक की दुखद मौत हुई है। हम उनके शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।

जून 2005 से 'सलवा जुडूम' के नाम से जारी फासीवादी दमन अभियान की मदद करने के लिए पहले नगा बटालियन और बाद में मिजो बटालियन को बुलाया गया था। पिछले साल के अक्टूबर महीने से मिजो जवानों को यहां तैनात किया गया था। तैनाती से लेकर अभी तक इनके जुल्म और आतंक की कहानियां अखबारों और टीवी के जरिए छत्तीसगढ़ के लोग कई बार पढ़ और देख चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर के पास माना में इन लोगों ने उत्पात मचाया था। उसके बाद से इन लोगों ने न जाने कितने गांवों में जुल्म ढाया होगा, इसका हिसाब भी लगाना मुश्किल है। खासकर दक्षिण बस्तर के नकुलनार, कुआकोण्डा, कोंटा, विंजरम, भेज्जी, बंडा आदि इलाकों में इन्होंने जुल्म और हिंसा का तांडव मचाए रखा है। पिछले साल कुआकोंडा थाने के पुलिस अफसर ने खुद टीवी कैमरों के सामने कहा था कि मिजो जवानों की ज्यादतियां हद से पार हो गई हैं। इससे बस्तर के सुदूरवर्ती गांवों की भोलीभाली जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्होंने बस्तर में नहीं बल्कि 25 दिसंबर 2006 को पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश के चिंतूर गांव में भी महिलाओं के साथ जोर-जबर्दस्ती की थी। इसके विरोध में वहां की स्थानीय जनता ने एक जुलूस निकालकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। सलवा जुडूम के गुण्डों के साथ मिलकर इन्होंने कई गांवों पर हमले कर गांवों को जलाने, लूटने, निर्दोष लोगों की हत्या करने और यातनाएं देने में बढ़-चढ़कर भाग लिया। खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में मिजो (इसके पहले नगा बटालियन भी) बटालियन के जवानों का बड़ा हाथ रहा। एक प्रकार से कहा जाए तो बस्तर के हर तबके के लोगों के दिलों में इनके प्रति इतनी नफरत थी कि उसका किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।

मिजो जवानों के जुल्म और आतंक के खिलाफ हमारी पार्टी ही नहीं, बल्कि कई अन्य पार्टियों, जन संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने भी आवाज उठाई है। हाल ही में एक तथ्यान्वेषण टीम ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। इस पर मिजो जवानों के आला अधिकारी की प्रतिक्रिया यह थी कि उनके खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार के पीछे नक्सलियों का हाथ है और वे इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों पर मानहानि का मुकदमा ठोंकेगे।

आतंक का पर्याय बने मिजो जवानों को दण्डित करने का फैसला हमारी पीएलजीए ने जनता की मांग पर तथा उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही लिया है। इस कार्रवाई के जरिए हमने उन सैकड़ों बस्तरिया महिलाओं की तरफ से बदला ले लिया जिन पर इन जवानों ने अत्याचार, अपमान व जुल्म की कहर बरपाई और बरपा रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करता!

मिजो जवानों के हर जुल्म और हर अत्याचार के पीछे केन्द्र और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश और आदेश हैं। इसके बिना ये इतने बेखौफ होकर सुनियोजित तरीके से ऐसे अनगिनत अपराधों को अंजाम नहीं दे सकते। सरकारों ने ही उन्हें उन्मुक्त अधिकार देकर ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर रखा है। दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन की रणनीति के तहत यहां की संघर्षशील जनता पर जुल्म और आतंक ढाना इनका स्पष्ट लक्ष्य है। इसीलिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने नगा और मिजो बटालियनों को तैनात करने का फैसला लिया। यह दरअसल अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति का ही हिस्सा है - किसी खास इलाके की जनता के आंदोलन को कुचलना है तो वहां की भाषा और संस्कृति से पूरी तरह भिन्न सेना को तैनात करो। ऐसे में उनके अंदर एक आक्रमणकारी सेना की सोच अपने आप आ जाती है और स्थानीय जनता के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती। इस नीति को कश्मीर में और उत्तर-पूर्व के इलाकों में कई बार आजमाया जा चुका है। अब बस्तर में भी इसी नीति को लागू किया जा रहा है। इसीलिए हम इसके लिए केन्द्र की यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो अब मिजो जवानों की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और इस घटना पर हाय तौबा मचा रही हैं।

हम इस मौके पर मिजो जवानों से फिर एक बार अपील करते हैं कि आप बस्तर में अपनी तैनाती का विरोध करें। यहां से तुरन्त चले जाएं। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, यह लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है। अगर आपको मजबूरन यहां रहना भी पड़ा तो जनता पर जुल्म व अत्याचार फौरन बंद करें, वरना मुरलीगुड़ा जैसी घटनाएं और भी घट सकती हैं। ★

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ सरकार की दमनकारी नीतियों का जवाब है 'दंतेवाड़ा जेलब्रेक'!

18 दिसम्बर 2007

16 दिसम्बर 2007 को करीब 300 कैदियों ने क्रांतिकारियों के नेतृत्व में दंतेवाड़ा जेल को तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। दंतेवाड़ा जैसे शहर में, जहां सैकड़ों पुलिस, अर्ध-सैनिक और एसटीएफ बल तैनात हैं, कैदियों ने पूरी तरह अपनी ही पहलकदमी, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ यह कारनामा कर दिखाया। यह जेलब्रेक ऐसे माहौल में हुई है जबकि शोषक शासक वर्ग जुल्मी 'सलवा जुडूम' अभियान को जनता का स्वत:स्फूर्त एवं शांतिपूर्ण अभियान कहते हुए क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने की मंशा से बस्तर की आदिवासी जनता के खिलाफ एक भीभत्सपूर्ण युद्ध चला रहे हैं जिसके तहत अब तक करीब 1,000 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, सौ से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की गई है, 700 से ज्यादा गांव लूटे व जला दिए गए हैं। दूसरी तरफ बस्तरिया जनता तमाम तकलीफों को सहते हुए भी अपना जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जीवन-मरण का संघर्ष कर रही है। पुलिस, अर्ध-सैनिक और नगा-मिजो बलों पर जवाबी हमले कर रही है। इस पृष्ठभूमि में यह एक ऐतिहासिक घटना है। इनमें से अत्यधिक कैदी आदिवासी थे और पुलिस ने उन पर झूठे मामले दर्ज कर जेलों में बंद कर रखा था। लगभग सारे कैदी गरीब तबके के थे और कई लोगों के लिए तो कानूनी सहायता पाना भी संभव नहीं था। खासकर पिछले ढाई साल से जारी सलवा जुडूम दमन अभियान के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आकर झूठे मामलों में फंसाए गए लोगों के लिए तो यह और भी कठिन था क्योंकि सभी लोगों के परिवार बुरी तरह बिखर गए। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की मां, किसी की बहन, किसी-किसी का तो पूरा परिवार ही सलवा जुडूम द्वारा मार डाला गया। कई ऐसे कैदी थे जिनकी कोई सुध लेने वाला तक बाहर नहीं बचा था। जो भी बचे हैं सलवा जुडूम के हमलों के डर से जंगल में दर-दर भटक रहे हैं, कानूनी सहायता पहुंचाने की बात तो दूर की कौड़ी है।

एक तरफ देश के बड़े-बड़े चोर नेता, अधिकारी, माफिया सरगना और पूंजीपति खुलेआम बाहर घूम रहे हैं जिनके नाम पर करोड़ों के घोटाले, रिश्वतखोरी, कर-चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि अनेक आरोप हैं। वे अगर जेल जाते भी हैं तो उन्हें ऐशोआराम की सारी सुविधाएं मिलती हैं और जल्द ही उनकी रिहाई हो जाती है। उनको तुरंत जमानत मिल जाती है और मुकदमे सालों चलते रहते हैं और आखिरकार रफा-दफा किए जाते हैं। जब वे जेलों में रहते भी हैं तो उन्हें जेल प्रशासन व पुलिस अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता है। दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और अन्य गरीब तबकों के लोगों को छिटफुट मामलों में सालों साल जेलों में सड़ाया जाता है। छोटे-मोटे मामलों में भी बिना जमानत के सालों तक रहना पड़ता है। कई लोगों को इसलिए सजाएं दी जाती हैं क्योंकि अपने बचाव के लिए वकील रखने की भी उनकी हैसियत नहीं होती। एक शब्द में कहा जाए तो असली और खतरनाक गुनाहगार जेल के बाहर, सत्ता के संस्थानों और ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग जेलों में सड़ रहे हैं। जेल के अंदर भी पैसे वालों को बेहतर खाने से लेकर अन्य सारी सुविधाएं दी जाती हैं और गरीब कैदियों को तो यहां तक कि भूखों मरवाया जाता है। जेल मैनुअल का कहीं भी पालन नहीं किया जाता है। लगभग सारे जेलों में घूसखोरी और दादागिरी का बोलबोला है। बीमार पड़ने से इलाज की सुविधाओं के अभाव में कई कैदी बमौत मारे जाते हैं। सरकार जिन लोगों को खतरनाक व इनामी नक्सली कैदी बता रही है दरअसल उनमें से अत्यधिक लोग बेकसूर हैं और हमारी पार्टी के साधारण समर्थक भर हैं। क्रांतिकारी कैदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा न देकर उनके साथ बुरा बरताव किया जाता है और कई बार तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। संक्षेप में जेल और न्यायव्यवस्था मेहनतकश जनता के दमन करने और रईस लोगों की रक्षा करने वाले राजसत्ता के औजार भर हैं। लुटेरे वर्गों के शासन को बचाने वाले औजार!

उपरोक्त पृष्ठभूमि में दंतेवाड़ा जेल में बंद हमारे पीएलजीए और जन संगठनों के कॉमरेडों ने पहलकदमी लेकर इस 'जेलब्रेक' की योजना को सफल बनाया तथा कई अन्य लोगों के साथ-साथ खुद को कैदखाने से मुक्त कर लिया। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी इर सभी कॉमरेडों का तहेदिल से क्रांतिकारी अभिनंदन करती है और सभी आजाद हुए कॉमरेडों का स्वागत करती है कि आप फौरन ही पार्टी, पीएलजीए और जन संगठनों के कतारों में आ जुड़ें और सलवा जुडूम के नाम से जारी लुटेरे वर्गों के प्रति-क्रांतिकारी युद्ध के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी जनयुद्ध में अपनी-अपनी भूमिका निभाएं। आपके इस शौर्यपूर्ण कारनामे से निश्चित रूप से दण्डकारण्य की संघर्षरत जनता का हौसला और भी बढ़ेगी और उनकी ताकत दुगुनी हो जाएगी। आपकी यह सफल कार्रवाई लुटेरे वर्गों के सलवा जुडूम के मुंह पर करारा तमाचा है। हमारी पार्टी की ऐतिहासिक एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस ने दण्डकारण्य समेत देश के विभिन्न संघर्ष-क्षेत्रों को मुक्त अंचल में बदलने का जो कार्यभार निर्धारित किया, उसे सफलता के मुकाम तक पहुंचाने की दिशा में जारी हमारे प्रस्थान में यह जेलब्रेक एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस ऐतिहासिक जेलब्रेक से बौखलाए शासक वर्ग अपनी नाकामी का ठीकरा छोटे अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। जेल के कर्मचारियों को नौकरियों से बरखास्त करने की साजिश की जा रही है जबकि एक छोटे अधिकारी को तो 'देशद्रोह' के आरोप

(शेष पृष्ठ 29 में...)

पीएलजीए की जुझारू सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड कमला को लाला–लाल सलाम !

18 दिसंबर 2007 के दिन उड़ीसा राज्य के गुड़ारी के निकट गांव नीरपल्ली के पास हुई मुठभेड़ में पीएलजीए की सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड कमला शहीद हुईं। पीएलजीए के प्रधान बल की सदस्या होने के नाते फौजी जरूरतों पर उनका उड़ीसा राज्य में जाकर एक साल पूरा हो चुका था। कॉमरेड कमला का जन्म माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके के डुंगा गांव में हुआ था। वह 24 साल की थीं। यह गांव नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक में आता है। कॉमरेड कमला आदिवासी समुदाय के एक मध्यम किसान परिवार की थीं। घर में उनका नाम था मोड़ियम मंगलो। अपने गांव की स्कूल में 8वीं की पढ़ाई पूरी की थी।

इंद्रावती इलाके में सामंती सरगना महेन्द्र कर्मा का भाई और जालिम मुखिया पोदिया पटेल का दबदबा था। उसके परिवार द्वारा आसपास के गांवों के लोगों का खूब शोषण किया जाता था। महिलाएं कबीलाई पितृसत्ता की जकड़न में जैसे कैद रह गई थीं। ऐसे हालात में वर्ष 1998 में इंद्रावती इलाके में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां शुरू हुईं। एक-दो साल के अंदर ही पोदिया पटेल की सामंती सत्ता को ढहाकर जनता ने अपनी राजसत्ता के निर्माण के लिए कमर कस ली। गांव-गांव में क्रांतिकारी जन संगठनों का निर्माण का सिलसिला चल पड़ा। एक सैलाब की तरह इस इलाके में जन संघर्ष होने लगे। इस सबका कमला पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। 1999 तक डुंगा में क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की ग्राम इकाई बन गई और कमला उसकी सदस्य बनीं।

अपनी सक्रियता के चलते कुछ ही दिनों में वह उसकी उपाध्यक्ष बनीं। धीरे-धीरे वह शोषणकारी सरकार के जुल्म-उत्पीड़न को समझने लगी। क्रांतिकारी राजनीति की मदद से कमला ने शोषण व पितृसत्ता की जड़ को पहचाना, जड़ को उखाड़ फेंकने के लिये हथियारबंद होने की आवश्यकता महसूस की। 'बिना क्रांति के महिला की मुक्ति संभव नहीं' - इस सच्चाई को उन्होंने आत्मसात किया और अपनी पूरी जिंदगी इसके लिये लगा दी। जून 2000 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने का निर्णय लिया। स्थानीय सांगठनिक दस्ते की सदस्या बन जनता के साथ घुलमिल गईं। शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संगठित होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जनता को संगठित करना शुरू किया। दस्ते की सदस्या रहते हुए जनता के बीच के अंतरविरोधों को समझने और हल करने के तारीकों को सीखा।

जून 2001 में वह पार्टी सदस्य बनीं। क्रांति की जरूरतों को देखते हुये मार्च 2002 में उन्हें मेडिकल टीम में तबादला किया तो पहले उस प्रस्ताव को उन्होंने इंकार किया था। यह बात 2002 की थी। बाद में उन्हेंने जब चीन की लांग मार्च की एक कहानी पढ़ी, जिसमें क्रांति में आदर्शों को लेकर एक महिला कॉमरेड के आत्मसंघर्ष का चित्रण था। कहानी से उन्होंने समझ लिया कि 'जिंदगी में हरेक के कई प्रकार के आदर्श हो सकते हैं पर एक क्रांतिकारी का आदर्श क्रांति ही होना चाहिए।' यानी क्रांति के लिए जो भी काम दिया जाता है उसे पूरे लगन के साथ करना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि कहानी की नीति को उन्होंने खुद पर ईमानदारी से लागू किया। अपनी आत्मालोचना के साथ पार्टी का प्रस्ताव स्वीकारते हुये पत्र लिखा। डॉक्टर टीम में रहते हुए उन्होंने एक तरफ चिकित्सा के गुर सीखते हुए ही दूसरी तरफ बीमार लोगों और गुरिल्ला कॉमरेडों की निष्ठापूर्वक सेवा की। उस टीम में आई समस्याओं को हल करने के लिए कॉमरेड कमला ने संघर्ष और एकता और आलोचना-आत्मालोचना को सही ढंग से लागू किया। उन्हें हल करने में कॉमरेड कमला की बेहद सकारात्मक भूमिका रही।

2004 में कमला का पीएलजीए की पलटन-6 में तबादला हुआ। पलटन में वह डॉक्टर के साथ-साथ शिक्षक भी बनीं। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करती थीं। जिस माहौल में भी रहना हो तो वहां के माहौल को आत्मसात कर लेती थीं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वह खूब पढ़ती थीं और जो भी पढ़ती थीं उसका विश्लेषण कर यह सोचती थी उसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। पलटन-6 में रहते समय उनके कामकाज की शैली को याद करते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यूं कहा, "कमला ऐसी होनहार लड़की थी जिसे एक बार कोई काम बता दें तो हर हालत में उसे बिल्कुल सही ढंग से पूरा कर देती थी। यानी कमला को कोई जिम्मेदारी देकर हम निश्चिंत रह सकते थे।"

जून 2005 में सलवा जुडूम फासीवादी हमला शुरू हुआ। नवंबर महीने तक उसका विस्तार नेशनल पार्क से इन्द्रावती एरिया तक हुआ। 29 नवंबर के दिन नगा पुलिस व सलवा जुडुम के गुंडों ने उनका गांव डुंगा के साथ-साथ वेडमा पर भी हमला बोलकर दोनों गांवों को जला दिया था। जुडूम के हाथों जलकर राख हुये घरों में कमला का घर भी शामिल था। उस समय कॉमरेड कमला ने पूरी कम्युनिस्ट दृढ़ता के साथ खड़ी होकर अपने माता-पिता व सगे-संबंधियों की हिम्मत बांधने का भरपूर प्रयास किया। सलवा जुडुम को हराने के लिए 2006 जनवरी से जून तक चलाए गए विशेष कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान (टीसीओसी) में बड़ी हिम्मत के साथ भाग लिया। सलवा जुडुम के गुंडों को सजा देने में, दुश्मन पर हमला करते समय वह अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती थीं। कई मुठभेड़ों में पुलिस बलों का डटकर मुकाबला कर अपनी सैनिक क्षमता का बढ़िया प्रदर्शन किया।

जनवरी 2007 में उन्हें आंध्र-उड़ीसा सीमा क्षेत्र में भेजने का निर्णय हुआ। इसे सुनकर बहुत खुश हुईं। दूसरा राज्य, नई भाषा, अपरिचित जनता, अलग संस्कृति - किसी भी बात को लेकर

(शेष पृष्ठ 36 में...)

पीएलजीए योद्धा कॉमरेड सुधाकर (रामजी) अमर रहे!

(कॉमरेड सुधाकर की शहादत 16 अगस्त 2006 को फैल्सिपारम बीमारी से हुई थी। हमें खेद है कि इस शहीद की जीवनी समय पर नहीं मिलने के कारण इसके प्रकाशन में बहुत देर हुई। - सम्पादक मण्डल)

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन में आज की युवा पीढ़ी सभी (राजनीतिक, फौजी और सांस्कृतिक) मोर्चों में बड़ी ही तेजी से विकसित हो रही है। निश्चय ही विकास की इस तेज गति की प्रेरक-शक्ति जनयुद्ध है। जहां एक तरफ शासक वर्ग दण्डकारण्य में पनप रही जनता की राजसत्ता का खात्मा करने की मंशा से फासीवादी दमन पर उतारू हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्पीड़ित जनता की सेना पीएलजीए अपने जवाबी हमलों और मुहिमों से इसका मुकाबला करते हुए जनता की राजसत्ता का बचाव कर रही है। जनयुद्ध दिन-ब-दिन तीव्रता और व्यापकता में विकसित होता जा रहा है ताकि जनता की राजसत्ता को दुश्मन के हमलों से बचाया जा सके और उसे उन्नत स्तर पर विकसित किया जा सके। विकासशील जनयुद्ध जनता के जीवन को, पार्टी और पीएलजीए को झकझोर रहा है। जनयुद्ध की गतिशीलता युवाओं को साहसिक जन मिलिशिया के योद्धाओं में बदल रही है। और जन मिलिशिया पीएलजीए के प्रधान और माध्यमिक बलों को पैदा करने वाला कुंआ सा बन गई। बढ़ता जनयुद्ध साहसिक कमाण्डरों और जांबाज योद्धाओं का जन्म दे रहा है। पढ़े-लिखे न होने पर भी कई कॉमरेड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स सम्बन्धी प्राथमिक नियमों और गतीय नियमों को समझकर फ्लैशों की तैयारी से लेकर बूबी ट्रैपों को विविध तरीकों से विकसित कर रहे हैं। जन डॉक्टर बन एक तरफ गांवों में बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ युद्ध के मोर्चे में डॉक्टर बन घायल जन सैनिकों का इलाज कर रहे हैं। इन सभी में अग्रिम पंक्ति में रह रही है यह युवा पीढ़ी और यह नई पीढ़ी। ऐसे नए जमात का ही नौजवान था अपना मड़ावी रामजी (सुधाकर)।

अपनी शहादत के समय कॉमरेड सुधाकर की उम्र लगभग 21 साल थी। उनका जन्म माड़िया गोंड समुदाय के एक मध्यम परिवार में हुआ था। पिता कटिया मड़ावी और माता इरपे मड़ावी की पहली संतान और इकलौता बेटा था। उनकी दो छोटी बहनें थीं। बचपन में ही, यानी 6-7 साल के उम्र में ही हैजा महामारी ने उनके पिताजी को निगल लिया। कुछ ही दिनों के भीतर उनकी मां दूसरी ब्याह करके चली गई। तीनों बच्चे अनाथ से हो गये थे। उन्हें अपने काका के पास रहने पड़ा। गांव में स्कूल न होने के कारण उन्हें पढ़ने-लिखने का मौका नहीं मिला। बचपन से ही गुरिल्ला दस्ते के साथ वह घुल-मिल जाया करते थे और क्रांतिकारी गीतों से प्रभावित थे। वह मन ही मन गीतों को गुनगुनाता था और इस तरह वह बाल संगठन का सदस्य बन गया।

उनके गांव में पेपर मिल वालों का कैम्प रहता था। वह पेपर मिल के अधिकारियों और बाबू लोगों के भ्रष्ट आचरण को समझ लेते थे। गांव में मुखिया लोगों के अन्यायों को समझ लेते थे। जन संगठन के नेताओं पर भी उसकी नजर रहती थी और वह उसकी रिपोर्ट गुरिल्ला दस्ते को दिया करते थे।

16 साल की उम्र में (2001 में) वह स्थानीय गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हुआ। शुरू में उन्होंने 2-3 महीनों तक भामरागढ़ दस्ते में काम किया। फौजी मामलों में सुधाकर की रुचि को देख पार्टी कमेटियों ने उन्हें पलटन-3 में भेजा। जनवरी 2002 से जून 2004 तक उन्होंने पलटन-3 में काम किया।

जुलाई 2004 में दण्डकारण्य में पीएलजीए की पहली कम्पनी का गठन किया गया। उस पहली कम्पनी के महत्व को देखते हुए एसजेडसी के प्रस्ताव के अनुसार सभी डिवीजनल कमेटियों ने अपने-अपने डिवीजनों से फौजी रूप से दृढ़ संकल्पी और साहसी तथा पार्टी व फौजी अनुशासन का कड़ाई से पालन करने वाले कॉमरेडों को कम्पनी-1 के लिए चुना। इस प्रकार गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने कॉमरेड सुधाकर को इसके लिए योग्य समझकर कम्पनी के लिए भेजा। इस प्रकार जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक उन्होंने कम्पनी-1 के सदस्य के रूप में काम किया।

युद्ध की कार्रवाइयों में...

फरवरी 2002 में गड़चिरोली जिले में जिला परिषद के चुनावों के मौके पर पलटन-3 ने अलवेर-कियेर के बीच पुलिस वालों पर ऐम्बुश किया। इस ऐम्बुश में तीन पुलिस वाले घायल हुए थे। इस में सुधाकर ने भाग लिया था।

सितम्बर 2002 में कोठी के पास पुलिस वालों की जीप पर ऐम्बुश किया गया जिसमें दो पुलिस वाले घायल हुए थे। इसमें भी कॉमरेड सुधाकर शामिल थे।

अगस्त 2003 में गड़चिरोली डिवीजन में चलाए गए डिवीजन स्तर के टीसीओसी के तहत पलटन-3 को केन्द्र बनाकर पीएलजीए बलों द्वारा कुम्मरिगुड़ा के पास किए गए ऐम्बुश में 6 कमाण्डो कुत्ते की मौत मारे गए थे। इस ऐम्बुश में पलटन कमाण्डर के गार्ड के रूप में कॉमरेड सुधाकर ने हमलावर दस्ते में रहकर बहादुरी का प्रदर्शन किया।

2003 के आखिर में जिनगनूर और कोप्पेला के बीच हुए ऐम्बुश में भी सुधाकर ने भाग लिया। 2003 और 2004 में किए गए मोरुमबूसी और बारदा ऐम्बुशों में भी कॉमरेड सुधाकर शामिल थे। बारदा ऐम्बुश में सीआरपीएफ के 5 जवान मारे गए थे।

मई 2005 में डौला में किए गए रेड में भी कॉमरेड सुधाकर ने भाग लिया था। हालांकि वह रेड विफल हुई थी, फिर भी सुधाकर ने हिम्मत के साथ भाग लिया और घायल कॉमरेडों को ढोकर ले जाने में बाकी कॉमरेडों के साथ सुधाकर का भी बड़ा योगदान रहा।

अक्टूबर 2005 में मूकावेल्ली के पास पुलिस और सलवा जुडूम के गुण्डों पर किए गए हमले में तथा फरवरी 2006 में किए गए कड़ियानार अपार्चुनिटी ऐम्बुश में भी सुधाकर शामिल थे।

अप्रैल 2006 में किए गए मुरिकिनार रेड में सुधाकर ने सपोर्ट ग्रुप के सदस्य के रूप में भाग लिया। ज्यों ही रेड शुरू हुई असल्ट ग्रुप की मदद करते हुए छीने गए हथियारों को इकट्ठा करने में उत्साह से भाग लिया।

उन्होंने जिस किसी भी कार्रवाई में भाग लिया, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, सफल या विफल हुई या आंशिक रूप से सफल हुई, बहादुरी के साथ भाग लिया। किसी भी कार्रवाई में उसके अंदर घबराहट कभी नहीं देखी गई। जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे बखूबी से निभाया।

पार्टी सदस्य के रूप में...

दस्ते में भर्ती होने के कुछ ही समय में सुधाकर ने पढ़ना-लिखना सीख लिया। आंदोलन की जरूरतों के मुताबिक स्थानीय दस्ते में कुछ ही समय तक काम करके प्रधान बलों का सदस्य बन पलटन में गए। अपने परिचित स्थानीय इलाके से दूर पूरे जोन, सब-जोन और डिवीजन भर में पलटन के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। पलटन में वह एक जिम्मेदार व अनुशासित सदस्य बने थे। उनकी वर्गीय पृष्ठभूमि, पढ़ाई प्रति उनकी जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और अनुशासित व जिम्मेदाराना बरताव को देखकर पलटन पार्टी कमेटी (पीपीसी) ने उन्हें 2003 में पार्टी सदस्यता प्रदान की। पार्टी सदस्य बनने के बाद सुधाकर और भी जिम्मेवार कॉमरेड बने थे। पार्टी सदस्य के रूप में वह अपनी राजनीतिक चेतना और सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए आखिर तक दृढ़तापूर्वक प्रयास किया।

गार्ड के रूप में...

पलटन-3 में कुछ समय काम करने के बाद सुधाकर ने पलटन कमाण्डर के गार्ड के रूप में काम किया। जनवरी 2005 से अगस्त 2006 में अपनी शहादत तक तक सीसी के एक कॉमरेड के गार्ड के रूप में काम किया। सीसी सदस्य के गार्ड बनकर जाने से पहले गार्ड की जिम्मेवारियों के बारे में कम्पनी कमाण्डर ने उन्हें जो-जो समझाया उसका सुधाकर ने आखिर तक पालन किया। पार्टी नेतृत्व की सुरक्षा के महत्व को सही ढंग से समझकर कॉमरेड सुधाकर ने बड़ी जिम्मेदारी से काम किया। गार्ड के रूप में रहते हुए भी कम्पनी के हर काम में वह सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। अध्ययन, ड्रिल, लकड़ी काटना, रसोई का काम, सभी सामूहिक कामों में वह आगे की लाइन में रहा करते थे। गार्ड की जिम्मेदारी के नाम पर बाकी सामूहिक कामों से जी चुराने का रुझान उनमें कभी नहीं देखा गया। जब सामूहिक काम नहीं रहते थे तब वह सीसीएम के साथ हर पल तैयार रहते थे।

तकनीशियन के रूप में...

घर में प्राथमिक शिक्षा भी सुधाकर को नहीं मिल पाई थी पर पार्टी में बहुत जल्द ही प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी विषयों के व्यवहार के दौरान ही सीखकर उसके बुनियादी नियमों को समझ लिया। इससे फ्लैशों की तैयारी के साथ-साथ बैटरी खराब होने या शार्ट सरकिट होने से भी उनकी मरम्मत किया करते थे। सोल्डरिंग करते थे। इसके अलावा गुरिल्ला कैम्पों में जेनरेटर चलाने और उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी कॉमरेड सुधाकर को अक्सर दी जाती थी। सुधाकर की मौत से हमने एक उभरते तकनीशियन को भी खोया जिसकी आवश्यकता इस बढ़ते जनयुद्ध को थी।

16 साल की उम्र में भर्ती होकर 21 साल की उम्र में मलेरिया से उनकी मुत्यु होना हमारे लिए दुखद घटना है। मलेरिया के शिकार होने पर पहले सुधाकर को क्लोरोक्विन की गोलियां दी गईं। उससे कम नहीं हुआ तो एंटीबयोटिक की गोलियां दी गईं। फिर भी एक महीने के अंदर तीसरी बार बुखार आने से तब समझ में आया कि वह फैल्सिपारम का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद क्विनाइन और फैल्सिगो की दवाई देकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक जानलेवा मलेरिया ने सुधाकर को लगभग आधा निगल डाला था। फैल्सिपारम को समय पर नहीं पहचानने के कारण हमारा इलाज काम नहीं आया और सुधाकर चल बसे। एक प्रकार से कहा जाए, तो कॉमरेड सुधाकर को नहीं बचा पाना संबंधित नेतृत्वकारी कॉमरेडों की विफलता है। इस विफलता से सबक लेंगे। दरअसल यह बीमारू व्यवस्था ही कॉमरेड सुधाकर की मौत के लिए जिम्मेदार है। आज भी मलेरिया जैसी बीमरियों की रोकथाम नहीं हो पाने के लिए यह शोषणकारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप हमारे देश में हर साल हजारों लोग मलेरिया के चपेट में आकर मारे जा रहे हैं। इस बीमारू व्यवस्था के उन्मूलन के लिए लड़ना ही कॉमरेड सुधाकर को सच्ची श्रद्धांजली होगी। एक साहसिक योद्धा और तकनीशियन के रूप में उभर रहे कॉमरेड सुधाकर का शहीद होना जनयुद्ध के लिए नुकसान है। इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए हजारों युवाओं को गुरिल्ला योद्धाओं और सैकड़ों लोगों को तकनीशियनों के रूप में विकसित करेंगे।

सुधाकर एक सीधा-सादा लड़का था। क्रांतिकारी आंदोलन में 5 साल काम करने पर भी वह कभी विलासिताओं और आधुनिक रंग-ढंग की तरफ नहीं गए। उनका पोशाक और बात करने का निराला अंदाज सभी कॉमरेडों का मन मोह लेता था। वह हर काम में सभी साथियों के साथ घुलमिल जाते थे। पार्टी और फौजी अनुशासन का कड़ाई से पालन करते थे। वह किसी रास्ते से एक बार भी चलते थे उसे अच्छी तरह याद रखते थे। दिशाओं को याद रखकर गुरिल्लों के सफर में जरूरत पड़ने पर गाइड का काम करते थे। अपरिचित इलाकों में युद्ध की कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए इस तरह के नैविगेटर्स (दिशाओं के आधार पर सफर में रास्ते निकालने वाले) की बहुत जरूरत हाती है। उनके ये सारे आदर्श पीएलजीए के तमाम योद्धाओं के लिए अनुसरणीय हैं।

रिपोर्ट लिखते हुये ध्यान देने योग्य बातें -

'प्रभात को संघर्ष की रिपोर्टें देरी से मिल रही हैं उनमें भी भेजने वाले पाठक कुछ चीजों को भूल जाते हैं। कृपया रिपोर्ट लिखते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखें।

कब हुआ? कहां हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? और कैसे हुआ?

रैली, आम सभा, प्रतिरोधी कार्रवाइयों की घटनाओं में यह नियम लागू होता है। कितनी जनता ने भाग लिया। क्या तैयारियां की गईं। इन सब बातों को लिखना मत भूलिएगा।

संपादक मंडल

'प्रभात'

उरपलमेट्टा वीर शहीद
युवा गुरिल्ला कॉमरेड दूलाल अमर रहे!

कॉमरेड दूलाल का जन्म एक गरीब दोरला आदिवासी परिवार में हुआ था। दन्तेवाड़ा जिले के कोंटा तहसील के गगनपल्ली गांव में वह पले-बढ़े थे। इस गांव में हमारे पार्टी के गुरिल्ला दस्तों का प्रवेश 1985-86 में हुआ था। मुखिया सोयम जोगाल का इस गांव पर पूरा दबदबा था। बोगाल कुछ समय भाजपा और कुछ समय कांग्रेस में रहा। एक बार विधायक का चुनाव लड़कर हार गया था। लम्बे समय तक इस गांव में पार्टी को जनता का सहयोग नहीं मिला था। एक बार तो हमारे दस्ता कमाण्डर की रायफल छीनने की भी कोशिश की थी इस गांव के मुखिया के लोगों ने। जोगाल पार्टी के कॉमरेडों को चोर, डाकू कहते हुए दुष्प्रचार करता था। मुखिया के परिवार ने पूरे गांव को काबू में रखकर दस्ते को खाना न देने और कोई सहयोग न करने का फरमान जारी कर रखा था।

आसपास के गांवों में पार्टी के नेतृत्व में जनता जन संगठनों मे संगठित होने लगी थी। इसका प्रभाव इस गांव के गरीब तबकों पर भी पड़ने लगा था। गांव में सोयम जोगाल के भ्रष्टाचार और जुल्मों के कारण जनता उसके खिलाफ लड़ने का मन बनाकर पार्टी के करीब आ गई। धीरे-धीरे जन संगठनों की गतिविधियां इस गांव में भी शुरू हुईं। गांव के मुखिया लोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। विकास के नाम पर सरकार से मिल रहे पैसों की सरपंच, सचिव आदि द्वारा की जा रही हेराफेरी को लेकर संघर्ष भी हुए और पैसे जनता को लौटा दिया गया। इसके बाद गरीब और भूमिहीन किसानों की समस्याओं, जैसे बीज और जमीन, को लेकर जन संगठनों की गतिविधियां तेज हुईं। इससे इस गांव के भी युवक-युवतियों की जन संगठनों में गोलबंदी शुरू हुई।

कॉमरेड माडिवी दूलाल 2005 में पीएलजीए में भर्ती हुए। इसके पहले वह गांव में जन मिलिशिया में काम करते रहे। वह जब भर्ती हुए तब तक कोंटा इलाके में सलवा जुडूम शुरू हुआ। एर्राबोर एक बड़ा केन्द्र बना था जुडूम के लिए। हजारों लोगों को जबरन इस शिविर में रखा गया। सोयम जोगाल का बेटा सोयम मूका ने जुडूम का नेता बन जनता पर हमले तेज किए। ऐसी स्थिति में जनता को बचाने के लिए पार्टी ने कोया भूमकाल मिलिशिया का गठन कर तथा जन मिलिशिया को मजबूत बनाकर प्रतिरोधी संघर्ष को तेज किया। इस दौरान गगनपल्ली गांव पर पुलिस बलों और सोयम मूका के गुण्डा गिरोहों द्वारा कई दफे किए गए हमलों में इस गांव के कुल 15 लोग शहीद हुए।

कॉमरेड दूलाल ने पहले जन मिलिशिया पलटन और एलजीएस में काम किया। 2007 में उन्हें पलटन-4 में स्थानांतरित किया गया। 2005 से शुरू किए गए दुश्मन के सलवा जुडूम का मुकाबला करते हुए कोंटा इलाके में की गई लगभग सभी कार्रवाइयों में कॉमरेड दूलाल की भागीदारी रही। कई ऐम्बुशों और बूबी ट्रेपों की कई कार्रवाइयों में कॉमरेड दूलाल शामिल थे। जून 2006 में एर्राबोर 'राहत' शिविर पर हमला कर जन विरोधी गुण्डा तत्वों का सफाया करने में कॉमरेड दूलाल ने बहादुरी के साथ भाग लिया। दुश्मन के ऊपर वर्ग-नफरत के साथ चढ़ाई करने में दूलाल का साहस हम सबके लिए आदर्श है।

आदिवासी जनता के खिलाफ लुटेरे शासक वर्गों द्वारा सलवा जुडूम के नाम पर छेड़े गए फासीवादी सैन्य आक्रमण शुरू होने के बाद बस्तर में लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया। लोग तितर-बितर हो गए। कोई जंगल में, कोई 'राहत' शिविरों में ध केल दिए गए। सलवा जुडूम के चलते यहां के गांव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कितने टूट गए, इसका उदाहरण है गगनपल्ली गांव। फरवरी 2006 में इस गांव के 40 साल के एक किसान बोडी मुत्ताल को जुडूम के गुण्डों ने पकड़कर हाथ-पांव बांधकर जिंदा जला दिया।

इन सारी हत्याओं से युवा गुरिल्ला दूलाल काफी आहत हुए। शत्रु वर्गों के इस अन्यायपूर्ण युद्ध का मुकाबला जनयुद्ध के जरिए ही किया जा सकता है, इस सच्चाई को समझकर दूलाल जनयुद्ध का एक आदर्श योद्धा बन गया। कोंटा इलाके में जनता की सुरक्षा के लिए पार्टी के नेतृत्व में अपनाए गए हर कार्यक्रम में दूलाल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जनता जुडूम के हमलों से बेघर हुई तो उनका ढाढ़स बांधते हुए उनके पुनर्वास के लिए पार्टी द्वारा उठाए कदमों को लागू करने में दूलाल ने सराहनीय योगदान दिया। 9 अगस्त 2007 को करीब 120 सीआरपीएफ, पुलिस और एसपीओ गुण्डों ने गगनपल्ली और मराइगुड़ा की जनता पर हमला बोला था। अपने गांव जला दिए जाने से लोग जंगलों में झोंपड़ियां बनाकर जी रहे थे। अपने 'सर्व विध्वंस' की योजना के तहत ये दरिंदे ने इन झोंपड़ियों को भी जला कर खुशी से वापस जा रहे थे। उनका अंदाजा था कि इस तरह बार-बार लोगों के आवासों को जलाने से वे उनके तथाकथित राहत शिविरों में जाने पर मजबूर होंगे। लेकिन दुश्मन के बलों के इस हमले का पता चलते ही पीएलजीए के कॉमरेडों ने उन पर जवाबी हमला किया। चारों तरफ से दुश्मन को घेरकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। कॉमरेड दूलाल ने एक पुलिस वाले से 5 गज दूर तक जाकर उसका सफाया कर उसकी एके-47 रायफल छीन ली। जब वह लौट रहे थे तब झाड़ियों में छिपे हुए दुश्मन ने उन पर गोली चलाई तो वह वहीं गिर पड़े। लेकिन दुलाल की शहादत से गुरिल्लों का जोश और बढ़ा। दुश्मन के साथ आमने-सामने लड़कर कुल 24 पुलिस वालों का सफाया कर 21 हथियार छीनकर अपने पराक्रम से जनयुद्ध के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। अगले दिन सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में कॉमरेड दूलाल का अंतिम संस्कार कर उन्हें श्रद्धांजली दी गई। ✶

(...पृष्ठ 33 का शेष)

उन्हेंने आगे-पीछे नहीं किया। उनकी सोच और कदम हर दम आगे की तरफ रहते थे। उनके द्वारा अपने दोस्तों व सहेलियों को लिखा संभवत: आखिरी पत्र क्रांति की अंतिम जीत और जनता पर उनके अटल विश्वास का सबूत है।

अपने हंसमुख व मिलनसार स्वभाव, सेवा भावना, लड़ाई के मोर्चे में दुश्मन के नाकों चने चबा देने वाला पराक्रम, अध्ययनशीलता, विनम्रता आदि गुणों से अपने सभी साथियों व जनता के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गईं हमारी कमला। लड़ाई के मोर्चे पर वह एक साथ स्नेहिल डॉक्टर भी थीं और एक जुझारू कमाण्डर भी। उनकी शहादत से पीएलजीए ने एक सहनशील डॉक्टर और होनहार सैन्य कमाण्डर खो दिया। 'प्रभात' शहीद कॉमरेड कमला को विनम्र श्रद्धांजली पेश करती है। उनके शोक संतप्त परिवार जनों, दोस्तों, गुरिल्ला सहेलियों और कॉमरेडों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। ✶

जनता की अदालत से कुछ खबरें

दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन

तीन मुखबिरों को सजा-ए मौत सुनाई

नाम – अर्का ओझा, गांव मरपल्ली, इलाका–अहेरी ऐरिया। जिम्मालगाटा रेजं। दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन। घटना 07–07–2007। अपराध 4 साल से पुलिस मुखबिरी।

2003 में मसाद गांव मे मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारा एक कॉमरेड घायल होकर गिर गाया था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर गोलियों से भून दिया था। तहकीकात से पता चला कि इसमें सरपंच दीपक गावड़े व अर्का ओझा का हाथ था। दीपक गावडे को 2005 में मार गिराया गया था, लेकिन अर्का ओझा तभी से पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। ऐसा करते हुऐ उसने अपने दो बेटों को भी कमांडो बलों में भर्ति करवा दिया। वह साथ में जगंल विभग में चौकीदार भी था जगंल में लकड़ी लाने गए लोगों, महिलाओं से बदसलूकी करना, दस्ते के समाचार इकट्ठे करना, गांव वालों को धमकाना, कामरेड्स के घर वालों पर दबाव डालना और दुष्प्रचार करना उसका रोज का काम हो गया था। इन सब हरकतों से जब वह बाज नहीं आया तो जनता ने वही किया जो वह अपने दुश्मनों के साथ करती है। और उस भाड़े के टट्टू को सजा–ए–मौत दी गई।

ऐसा ही हुआ दोगे नरोटे के साथ। दोगे नेरोटे गांव हेडरी का निवासी था जो पेरिमिलि ऐरिया में आता है। दोगे 2002 से पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। वह जन सगंठनों के कामकाज में एक बड़ा रोड़ा बन गया था। 2003 में जन अदालत लगाकर उसे सुधारने का मौका दिया गया लेकिन इस कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई। जब नगा पुलिस ने कैम्प डाला तो उसके काले कारनामे ओर ज्यादा बढ़ते ही चले गये। गांव में पहुंचते ही वह पुलिस के पास दौड़ा जाता। जन सगंठन के सदस्यों को तंग करता था। इस कारण से उसके गांव में 2006 में दमन ज्यादा बढ़ गया। उसकी ऐसी हरकतों के खिलाफ कई बार चेतावनी दी गई लेकिन डाक के वही तीन पात। वह लगातार जनविरोधी कार्यवाहियों में तल्लीन रहा। 12 जून को उसके गांव में जाकर उसे सुबह–सुबह धर दबोचा, जिसे बाद में जन अदालत में गांव वालों की मांग पर मौत के घाट उतार दिया गया।

मासा पोदाड़ी भी इसी प्रकार का जन विरोधी तत्व था जो जन मिलिशिया के हाथों से बच नहीं सका। यह पदेड़ा गांव का निवासी था। कई सालों से पदेडा व मरकानार की जनता उसके कारनामों से तंग आ चुकी थी। बेवजह गांव वालों से झगड़ा करना, मार –पिटाई आदि करता था। 2002 में एक बार खुद को चाकू से घायल करके भामरागढ़ पुलिस थाने में चला गया और दोनों गांव के कुछ निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाये। ऐसे ही मार्च 2002 में पंचायात व जिला परिषद चुनाव के समय किया, पदेड़ा गांव के एक युवक को गोरगा पिलाने के बहाने जगंल में ले गया और उसे भरमार बन्दूक से घायल कर दिया। उसी समय बिनागुण्डा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, मासा ने उसी दिन लाहेरी थाने में जाकर कहा कि जो जन मिलिशिया कमांडर बिनागुण्डा मुठभेड़ में घायल हुआ है वह हमारे गांव में है। अगले दिन उस निर्दोष युवक को पुलिस ने पकड़कर यातनाएं दीं और झूठा केस लगाकर जेल भेज दिया।

उसके बाद मासा लाहेरी थाने में रहने लगा। तबसे वह आसपास के गांवों में पुलिस मुखबिरी कर रहा था। एक दिन जन मिलिशिया हांथों पकड़ा गया जिसे मौत की सजा दी गई।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

दमन–प्रतिरोध

4 जुलाई को पुलिस, सीआरपीएफ और एसपीओ मिल कर गल्लागुड़म गांव में घुस गये। घुसते ही जो भी सामने आया उसी पर टूट पड़े। गांव में जितने सुअर–मुर्गे मिले पकड़ कर ले गये। आगे चलकर इन दरिन्दों ने दो महीलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, उनके साथ सामूहिक अत्यचार किया।

5 जुलाई को बिक्रम गांव पर हमला किया गया जब गांव में कोई नहीं मिला तो इन आतााइयों ने दो घरों को जलाकर रख कर दिया। घरों में रखे चावल व धान को भी आग की भेंट चढ़ा दिया।

6 जुलाई को इनका निशाना बलिजय गांव बना। इसमें भी गल्लागुड़म को दोहराया गया। दो घरों को जला डाला गया, 70 के आसपास मुर्गीयां पकड़कर ले गये और दो महिलाओं के साथ बेहरहमी से बल्ताकार किया गया।

7 जुलाई को एक बार फिर बिक्रम गांव इनका निशाना बना। चार लोगों को पकड़ लिया और बेहोश होने तक पिटाई करते रहे।

9 जुलाई को दुरमी गांव में जन मिलिशिया के तीन सदस्यों को पकड़ कर गोली मार दी गई। कॉमरेड उयका सन्नाल, तामो देवाल और मिड़ियम इरालू – तीनों ही ग्राम रक्षा दल के बहादूर सदस्य थे।

11 जुलाई को पोलम गांव पर हमला हुआ जिसमें सात झोपड़ियों को जला दिया गया, 1500 किलो धान व करीब करीब सौ मुर्गियां पकड़ कर ले गये। यहां तक कि लोगों के घरों में रखे पानी के बर्तनों को भी तोड़ डाला गया।

मुखबिरों को नही बख्शा जनता ने!

कई दिनों से इस इलाके में हमले जारी थे। इन सबमें पुलिस को रास्ता दिखने वाला व सूचनायें पहुंचाने वाला था जोन्नागूडाम का भीमाल। इस कुत्ते को जेगुरगुण्डा के जल्लाद थानेदार ने पाला हुआ था। यह पुलिस के पास ही रहता था। 11 जुलाई को कोया भूमकाल मिलिशिया के हाथों पकड़ा गया। भरी जन आदलत में इस जन विरोधी तत्व ने अपने जुर्मों को कबूल किया। जनता ने उसके गुनाहों को माफी के काबिल ना समझकर उसे मौत कि सजा सुनाई। अगले दिन इसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। ★

देश और दुनिया की खबरों पर एक नजर

इराकी घटनाक्रम

इराकी घटनाक्रम पर इन दिनों बहुत ही दिलचस्प सुर्खियां छाई हुई हैं। आज इराक में अमेरिकी साम्राज्यवाद की ऐसी स्थितियां हो गई हैं जैसे कुता कांटेदार झाड़ियों में फंस जाता है, निकलता है तब भी झाड़ के कांटे चुभते हैं, वरना पड़े-पड़े तो चुभ ही रहे हैं। फिलहाल खबर यह गर्म थी कि अमेरिका की संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इराक को 3 स्वायत्त प्रदेशों में बांटने का सुझाव दिया है। इराक के शिया-सुन्नी दोनों समुदायों ने इसका जमकर विरोध किया है। इस तरह का साम्राज्यवाद का चिर परिचत रूप है कि 'फूट डालो और राज करो', जिसको अमेरिका ने नये संस्करण यानी नव उपनिवेशवादी नीति में भी ऊपर के स्थान पर जगह दी है। साफ तौर पर कहें तो अमेरिका इराक के 3 टुकड़े करके 3 हमीद करजई जैसी कठपुतिलियों को बैठाना चाहता है। एक अल मलिकी और अपनी 1,63,000 सेना से वह इराकी जनता के प्रचंड आंदोलन को कुचल नहीं पा रहा है।

दूसरी खबर है- 'ब्लैक वाटर' हां, काला पानी की। यह अमेरिका की एक प्राईवेट कम्पनी है जो बगदाद में 9 वर्ग किलोमीटर के 'ग्रीन जोन' की सुरक्षा करती है। ग्रीन जोन वो इलाका है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी या अन्य आने-जाने वाले राजनेता रहते हैं। इराक में सबसे सुरक्षित इलाका इसे ही माना जाता है। लेकिन इराकी मिलिशिया यहां पर भी कई बड़े आत्मघाती हमले कर चुकी है। पिछले दिनों इस कंपनी ने 17 इराकी नागिरकों को गोलियों से भून दिया। इनको शक था कि ग्रीन जोन के पास घूमने वाले ये आंतकवादी हो सकते हैं। इन 17 लोगों में ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों की है। जब इनको इराकी कोर्ट में सजा दिये जाने की बात आई तो अमेरिकी संसद ने खुलकर उन दरिंदों का बचाव किया और कानून पास किया कि इराक में काम करने वाली तमाम निजी सुरक्षा कंपनियों पर मुकदमे केवल अमेरिका की कोर्ट में ही चलाये जा सकते हैं। सुरक्षा कंपनियों की जवाबदेही इराक की सरकार के प्रति नहीं, अमेरिका के प्रति है।

कुछ आंकड़े ये भी -

➢ जब अमेरिका ने युद्ध शुरू किया तो कहा था मैं आ रहा हूं आपे के लिये, रोटी और जनतंत्र लेकर। लेकिन आज ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे 42 लाख युद्ध शरणर्थियों को देश से धक्के देकर बाहर किया जा रहा है। एक रेडियो चैनल के अनुसार इराकी शरणार्थी इस ग्रह के सबसे भयंकर यातनायें झेल रहे हैं।

➢ इराक की पुलिस और सेना की 1,95,000 एके-47 राइफलें गुम हो गई हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है कि वो कहां गयीं। इराक में हर 5 सिपाहियों में से केवल एक पर ही राइफल है, जिस कारण से रक्षा विभाग चीन से 10,000 करोड़ डॉलर के हल्के हथियार खरीदने का समझौता कर रहा है। जनता किस प्रकार दुश्मन के हथियारों पर निर्भर होकर संघर्ष करती है इससे साफ समझ में आता है।

म्यान्मार में जनवादी आंदोलन

म्यान्मार (बर्मा) भारत के उत्तर-पूर्व में एक छोटा सा देश है जो इस समय निरंकुश सैन्य शासन के खिलाफ चल रहे जन आंदोलनों के कारण से सुर्खियों में रहा। 16 सितंबर से लेकर लगभग 30 सितम्बर तक म्यान्मार में तानाशही के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रर्दशनों का सिलसिला चलता रहा। सेना और पुलिस के भयंकर दमन के चलते धार्मिक भिक्षुओं का नेतृत्व टिक नहीं पाया। म्यान्मार में पिछले 3 दशक का इतिहास सेना की निरंकुश शासन का इतिहास है और उसके खिलाफ आंदोलनों का भी इतना ही पुराना इतिहास है। वहां पर कोई भी सरकार का पदाधिकारी प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जनवादी लड़ाई लड़ रही आंग-सांग सूची को 30 सालों से उसके घर में नजरबंद बना कर रखा जा रहा है जिसे कोई राजनीतिक गतिवधियों में हिस्सा लेने या कोई भाषण तक देने की आजादी नहीं है।

अमेरिका म्यान्मार सरकार के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर चुका है और संयुक्त राष्ट्र का दूत इब्राहाम गम्बारी भी बार-बार यहीं मंडरा रहा है और कह रहा है कि सैनिक शासन का अंत होना ही चाहिये। आप भी असमंजस में होंगे, आखिर अमेरिका को म्यान्मार के नागरिकों की आजादी की इतनी चिंता क्यों लगी हुई है? आइये, जरा राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से थोड़ी नजर दौड़ायें। म्यान्मार बहुत ही छोटा सा खेती-प्रधान देश है जिसे वहां के सामंती राजशाही और दलाल पूजिंपति सयुंक्त रूप से वहां की जनता का खून निचोड़ कर पी रहे हैं। भारतीय विस्तारवादी और चीनी सामाजिक पूंजीपति वहां के प्राकृतिक संसाधानों का दोहन कर रहे हैं। पूरे देश के उद्योग धन्धों पर पहले नंबर पर चीन का और दूसरे नंबर पर भारत का कब्जा है। म्यान्मार की सरकार इन दोनों देशों की पिट्ठू है। अगर देखें तो अमेरिकी कंपनियों की वहां पर ज्यादा घुसपैठ नहीं है। इस समय दक्षिण एशिया में दो ही हित सबसे ऊपर हैं कि एक तो ज्यादा से ज्यादा देशों में, उनकी सरकारों पर नियंत्रण किया जा सके जिससे अमेरिका के आर्थिक हित पूरे होते रहें, दूसरा उनको डराये-दबाये रखने के लिये सैनिक अड्डे स्थापित करने के। अब अमेरिका पूरा चीख रहा है कि जनता को जनवाद दो। असल बात तो यह है कि वो म्यान्मार में अपनी कंपनियों के लिये दरवाजे खुलवाना चाह रहा है। सैनिक शासन पर अगर उसे सचमुच आपत्ति है तो वो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ पर क्यों नहीं चिल्लता! क्योंकि वह बुश की एक ही आलोचना पर उत्तरी वजीरिस्तान की विद्रोही आदिवासी जनता पर बमों की बारिश कर देता है। म्यान्मार उसके सैनिक अड्डे के लिये भी भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है। म्यान्मार दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े देशों की सीमा पर स्थित है। इससे भारत और चीन दोनों को डरा कर रखा जा सकता है। वैसे हिंद महासागर में भी अमेरिका का एक सैन्य ठिकाना तो पहले से ही स्थापित है।

भारतीय विस्तारवाद व चीनी सामाजिक पूंजीवाद अपने आर्थिक

हितों के कारण से म्यान्मार की जनता के जनवादी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारत का सैनिक हित भी म्यान्मार के शासक वर्ग से जुड़ा हुआ है। उत्तर-पूर्वी राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों का दमन करने में सीमांत क्षेत्रों में म्यान्मार की सैनिक राजशाही सरकार पूरी मदद करती है। भारत उस मदद को खोना नहीं चाहता।

आज म्यान्मार की जनता के आन्दोलन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वह साम्राज्यवादियों और पड़ोसी देशों की सरकारों की नीतियों को समझे और उनसे मदद की कोई आशा ना पाले। किसी राजनीतिक बदलाव का कारण उस देश की जनता की शक्ति होती है। बाहरी देशों की सरकारी मदद नहीं। कोई भी पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देश जनवादी आंदोलनों की मदद नहीं करता, बल्कि उनके अंदर अपने दलाल पैदा करने के लिये उसके सर्मथन की ड्रामेबाजी करता है ताकि राजनीतिक परिर्वतन की स्थिति में उस देश पर नियंत्रण या अपने आर्थिक हित साधे जा सके। आज इब्राहिम गंबारी और एंजिला मेरीकल (जर्मनी की चांसलर) यही नाटक कर रहे हैं और म्यान्मार के चक्कर काट रहे हैं।

आज जनवादी आंदोलन का कर्तव्य केवल राजशाही या सैनिक तानाशाही के खिलाफ लड़ने से पूरा नही हो जाता। यह युग साम्राज्यवाद और विश्व सर्वहारा क्रांतियों का युग है, जिसमें जनवादी या राष्ट्रीय आंदोलन राजशाही और सैनिक शासन के साथ-साथ साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ कर ही सच्चा जनवाद स्थापित किया जा सकता है।

राष्ट्र मुक्ति चाहते हैं, जनता क्रांति चाहती है और देश आजादी चाहते हैं। यह आज भी सच है। म्यान्मार की जनता को चाहिये की वह अपने देश के सामंतवाद और दलाल पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाये। साम्राज्यवाद को अपना दुश्मन घोषित करे। जनवादी लड़ाई सर्वहारा के नेतृत्व में ही जीती जा सकती है। बाकि सभी प्रकार का नेतृत्व जनता को एक शोषण की चक्की में से दूसरी शोषण की चक्की में ही लेकर जायेगा। या कहें कि साम्राज्यवाद का पिछलग्गू बनकर रह जाएगा।

'प्रभात' म्यान्मार की जनता के जनवादी आंदोलन का पुरजोर सर्मथन करती है और आशा करती है कि वहां के सर्वहारा की अगुवाई में तमाम शोषित वर्ग मिलजुलकर और संगठित होकर सशस्त्र क्रांति के जरिए अपने देश में जनवाद की स्थापना करेंगे तथा साम्राज्यवादियों की हर किस्म की साजिश को नाकाम करेंगे। हम भारत की विस्तारवादी नीतियों का, चीन की सामाजिक पूंजीवाद की शोषणकारी नीतियों का और साम्राज्यवादियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की ड्रामेबाजी की पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। भारत की क्रांतिकारी संगठनों व जनवादी आंदोलनों से अपील करते हैं कि म्यान्मार की जनता की आवाज में अपनी आवाज मिला कर आंदोलन का संमर्थन करें।

परमाणु करार पर तकरार

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का 2005 से ही विभन्न प्रगतिशील व जनवादी ताकतें विरोध कर रही हैं जिनमें से हमारी पार्टी प्रमुख है। परमाणु असैनिक समझौता पूरी तरह से भारत की जनता के खिलाफ है। अमेरिका को लूटने की खुली छूट देता है। इस समझौते से भारत पूरी तरह से हर मामले में अमेरिका के कब्जे में चला जायेगा। देश की प्रभुसता और देश के संसाधनों को अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथों गिरवी रखने वाला समझौता है यह। हर देशभक्त, देश से प्यार करने वाला नागिरक इसका विरोध कर रहा है।

अमेरिकी सिनेट (संसद) ने इस समझौते को लागू करने से पहले एक कानून पास किया जिसका नाम है 'हाईड एक्ट' यानी छुपा हुआ कानून। उस छुपे हुये कानून की धारा 123 के तहत इस समझौते पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश ने हस्ताक्षर किये। धारा 123 के तहत होने के कारण इसे एक-दो-तीन समझौता भी कहा जाता है। इस धारा के दो नियमों से ही इस छुपे हुये कानून के मंसूबे सामने आ जाते हैं। (1) 'सैफगार्ड' लगवाने होंगे यानी कि भारत को अपने सारे परमाणु संयत्र चाहे वह सैन्य हो या उर्जा जरूरतों वाले, उनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था (आइएईए) की निगरानी में रखने होंगे। अमेरिका या अन्य उसकी चमचे संस्था के अधिकारी कभी भी भारत के परमाणु कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं। (2) अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो या अन्य पेचीदा परिस्थितियों में अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति किसी भी समय भारत से अपने सारे उपकरण वापिस ले सकता है। पहले से वहां भारत के सारे परमाणु हथियारों की जानकारी लेना चाहता है और परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है। दूसरे से वह भारत की सरकार को पूरी तरह नव उपनिवेशिक ढंग से अपने घर का कुत्ता बनाना चाहता है। जिस परमाणु तकनीक व उर्जा का वह आज लालच दे रहा है उसके ही जरिये वो भारत को अपने इशारों पर नचायेगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले पर या अन्य मामलों पर भारत अगर उसका समर्थन नहीं करेगा तो उपकरण, तकनीक को वापिस ले जाने की धमकियां देगा। और आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणाओं का खेल शुरू करेगा जो वह आज इरान, सिरिया, उत्तर कोरिया और अन्य देशों के खिलाफ कर रहा है। हर क्षेत्र में अमेरिका की दखलअंदाजी बढ़ेगी।

'आप खाये जलेबी और दूसरों को बताये परहेज'

खुद अमेरिका के पास इतने परमाणु बम हैं कि पूरी दुनिया को वह 10 बार तबाह कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका 1100 के आसपास परमाणु परीक्षण कर चुका है। इसके बाद नम्बर रूस का आता है जिसने 600 परमाणु परिक्षण किये। लेकिन उत्तर कोरिया या इरान, सिरिया जैसे देशों ने जिन्होंने एक भी परमाणु परीक्षण नहीं किया, उनको शक के बिना पर ही पूरी दुनिया के लिये खतरा बता रहा है। भारत को भी 'छुपे हुये कानून' के तहत इसके लिये परहेज बता रहा है। दादागिरी का अंदाजा हाल ही में आये अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से लग सकता है, जब समझौता लागू ना होने की चर्चाओं का बाजार गर्म है तभी उसने कहा, "ऐसा नहीं हुआ तो भारत को इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे।"

एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि इससे भारत के बढ़ते बाजार की उर्जा जरूरतें पूरी होंगी और सस्ती उर्जा प्राप्त होगी। सस्ती विदेशी उर्जा का स्वाद क्या हमने महाराष्ट्र में अमेरिकी

कंपनी 'एनरॉन' से नहीं चखा था? जिसने सस्ती बिजली के नाम पर 8 रूपये प्रति यूनिट बिजली बेची थी और बाद में अपने आप को दिवालिया दिखाया था। उस समय में भी भारत की सरकार ने उसे करोड़ों डॉलर का मुआवजा देकर अमेरिका भेजा था। दूसरा इस उद्योग में पूंजीनिवेश करने वाली कंपनी दुनिया की सबसे लुटेरी कंपनी है जो देशों के तख्तोताज बदलवाने के लिये कुख्यात है। उनसे सस्ती दरों पर उर्जा की उम्मीद करना बेइमानी ही होगी। साम्राज्यवाद कभी अपनी चीजें जनता के लिये सस्ती नहीं कर सकता। और महंगाई बढ़ाना उसके चरित्र में शुमार है। एक उदहारण यहां इराक के तेल का ले सकते हैं। इराक में सद्दाम हुसेन के शासन के दौरान प्रति वर्ष 34 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता था, और उस समय तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कभी भी 30 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा नहीं हुई थी। और औसतन लागत केवल 75 सेंट आती थी। अमेरिकी साम्राज्यवाद के कब्जे के बाद हाल यह है कि तेल की कीमत कभी 60 डॉलर प्रति बैरल से कम नहीं हुयी है और अब के सितंबर महीने में तो यह 80 डॉलर प्रति बैरल को छू गई है। साम्राज्यवाद के इस झांसे से जनता को दूर ही रहना चाहिये।

मार्क्सवाद के नाम पर धंधा करने वाले ठेकेदारों के विरोध के पीछे सच्चाई क्या है?

केरल में सीपीआई (एम) सरकार में चल रही सस्ती राजनीति और विजयन और अच्युतनंदन की जुतमपजैर तथा सिंगूर व नंदीग्राम में हुये नरसंहारात्मक दमन ने सीपीआई (एम) के लाल नकाब को उतार फेंका और शोषणकारी विद्रूप चेहरे को सामने ला दिया है। टाटा और 'सलीम ग्रुप' से बुद्धदेव के 'व्यावहारिक प्रेम' से भी पार्टी को 'वाम' दलों के ही बुद्धिजीवियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। प्रकाश करात ने तो ऐसे कामरेडों को 'नरोदिनिक' ही घोषित कर दिया जिसके विरोध में बुद्धिजीवियों के एक हिस्से ने उसे 'स्टोलिपिन' तक की संज्ञा दे डाली। अब स्थिति ऐसी आ गई कि प्रगतिशीलों का एक तबका जो पहले वाम दलों की नीतियों को ठीक मानता था, वह भी उसकी असलियत को पहचान गया और जनता भी। अब 'वाम' दलों को ऐसे विचारधारात्मक मुद्दे की जरूरत थी जो उनकी खोई हुई साख लौटा सके। सो परमाणु मुद्दे के गर्मागर्म मुद्दे को उठा लिया ताकि लाल दिख सके। दो साल से इनकी नाक के नीचे ये खिचड़ी पक रही थी तो शुरू में ही क्यों सरकार गिराने की बात नहीं कही? अब 'वाम' दलों की ड्रामेबाजी यहां तक पहुंच गई कि लगा अब की बार तो 'वाम' दल सरकार को गिरा ही देंगे। 'वाम' दलों को सरकार ना गिराने के लिये उनका सत्ता सुख है जो वो तीन साल से भोग रहे हैं। दूसरा देश में अभी की परिस्थितियों में 'वाम' दलों को इसका राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा। लोगों के दिमाग से नंदीग्राम व सिंगूर में लोगों पर चलती गोलियों, भंयकर दमन के दृश्य अभी उतरे नहीं है। दूसरा एक बात तो इस मुद्दे से अच्छी प्रचारित हो गई है कि 'वाम दल ऐसे कुत्ते हैं जो भौंकते तो हैं पर काटते नहीं'। एक सही मुहावरा भारतीय गठबंधन की राजनीति ने ढूंढ़ लिया है।

अब बात करते हैं भाजपा के नाटक की -

वो भी इस मुद्दे पर उछले थे। क्या भाजपा का अमेरिकी प्रेम किसी से छिपा हुआ है? नहीं! तो क्या इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है? उन्होंने साफ-साफ कहा, भई! हम करार का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका का नही। क्योंकि पता है कल सत्ता में आते ही वहां हाजिरी लगाने जरूर जाना होता है। बुश सहाब को नाराज करके वो अपनी दलाली बंद नहीं करवा लेना चाहते। लेकिन वो देख चुके हैं कि हिन्दुत्व की राजनीति से जनता अब ऊब चुकी है। सांप्रदायिकता का नंगा नाच अब और वोट नहीं दिलवा सकता। सो वह भी रस्म अदायगी के तौर पर इस आयोजन में शरीक हो गये थे। परंतु पार्टी की आपसी कलह और गुजरात के चुनाव के कारण से आजकल उनके सुर सुनाई नहीं दे रहे हैं।

चलते-चलते एक और कि अब वाम दल, कांग्रेस और पूरा युपीए किसी भी हालात में सरकार को बचाना है, इसी मुद्दे पर लगा हुआ है और कुछ नहीं! ✶

(...पृष्ठ 17 का शेष)

कारण ही 34 हजार बच्चों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस प्रकार से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की संख्या 75 हजार तक पहुंच गई है। दक्षिण-पश्चिम बस्तर में सलवा जुडूम के कारण ग्रामीण जीवन व शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गई है। यहां पर कोई नागरिक शासन नहीं है। केवल और केवल पुलिस, अध सैनिक बलों, सलवा जुडूम का जुल्मी आंतक चल रहा है। किन्तु राज्य की लुटेरी व दमनकारी सरकार आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़ने का दोष हमारे ऊपर लगा रही है। परंतु सच्चाई यह है कि आश्रम शालाओं के पुलिस के अड्डे बनने से बच्चे और शिक्षक दोनों ही भयभीत हैं। इसलिये आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाले सलवा जुडूम सरकारी दमन अभियान को तुरंत बंद करें। आश्रम स्कूलों में बैठाये गये पुलिस गुण्डों के अड्डों को तुरंत हटाया जाये। अन्दरूनी इलाकों के आश्रम स्कूलों को वापिस उनके गांवों में बहाल किया जाये। सलवा जुडूम में शामिल ना होने वाले गांवों के बच्चों की पढ़ाई में डाली जा रही बाधा बंद की जाये। अंदरूनी इलाकों के स्कूलों के शिक्षकों से अपील है कि बच्चों को पढ़ायें। हम सभी जनवादी, लोकतांत्रिक शक्तियों से अपील करते हैं कि वह स्कूली शिक्षा को सलवा जुडूम, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के आंतक से मुक्त करवाने के लिये और शिक्षा सत्र के सुचारू संचालन के लिये संघर्ष करें। आज इसकी आवश्यकता है। सरकार व उस के मीडिया द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ किये जा रहे दुष्प्रचार को निरस्त करें।

आज बस्तर की जनता को, पढाई करने वाले नौजवानों को और शिक्षकों को चाहिये कि वे दण्डकारण्य में विकसित हो रही जनताना सरकार को मजबूत करें। जनयुद्ध को तेज करते हुये आधार इलाके की स्थापना करें। ऐसा करके ही सही जनवादी वैज्ञानिक वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जा सकती है। केवल जनताना सरकार ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकती है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी निडर हो कर पढ व पढा सके, जिससे से सही विकास के पथ पर बढा जा सके। ✶

(...अंतिम पृष्ठ का शेष)

यह सिलसिला 1977 में रुका जब मार्च में आपतकाल खत्म हो गया। अजय दा को 1977 के मध्य में रिहा किया गया। उन्होंने राज्य सराकर की नौकरी ना कर सक्रिय क्रांतिकारी जीवन जीने की शपथ ली और कुछ अन्य कामरेडों के साथ मिल सीपीआई (एम-एल) पार्टी युनिटी का गठन किया।

नवंबर 1978 में सीपीआई (एम-एल) पार्टी यूनिटी के गठन के साथ अजय दा ने उसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और वह नेतृत्वकारी टीम में चुने गये थे। इसके बाद कुछ छोटे-छोटे ग्रुपों के साथ एकता हुई और एक अन्य विलय के बाद 1982 में सीपीआई (एमएल) पार्टी यूनिटी का पुर्नगठन हुआ। तब अजय दा पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी में थे। 1987 के पार्टी अधिवेशन में वह पीयू की केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी में चुने गये थे। कॉमरेड अजय दा में काम करने की बढ़िया क्षमता थी। वह पार्टी के मुखपत्र के प्रभारी रहे, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अखिल भारतीय सांस्कृतिक संगठन बनाने में उनका योगदान रहा। 1978-79 में छात्र संगठन की देखरेख की। कॉमरेड अजय दा ने ऐतिहासिक नादिया जिले के किसान आंदोलन में एक शानदार भूमिका निभाई थी। उन्होंने हावड़ा और हुगली में भी काम किया। हुगली से उन्होंने हल्दिया औद्योगिक एरिया में भी संपर्क स्थापित किया और कुछ एरिया में काम खड़ा किया। वे खड़गपुर गये और वहां भी कुछ काम किया। 1978-79 के कुछ समय उन्होंने बांडमुंडा (उड़ीसा) गए और रेलवे मजदूरों में काम किया।

वह सीपीआई (एम-एल) के पहले राज्य कमेटी सदस्य व सीपीआई (एम-एल) पार्टी यूनिटी के संस्थापक सदस्य थे। अनुभवी नेता व केंद्रीय कमेटी सदस्य होने के नाते सीपीआई (एम-एल) पार्टी यूनिटी व सीपीआई (एम-एल) (पीपुल्सवार) की एकता में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस तरह पीपुल्सवार व एमसीसीआई की एकता में भी उनका अहम योगदान रहा। 1998 में अजय दा नव गठित सीपीआई (एम-एल) (पीपुल्सवार) के और 2004 में नवगठित भाकपा (माओवादी) के भी संस्थापक केंद्रीय कमेटी सदस्य बने।

60 के दशक में पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। वह शुरू से ही आंदोलन का हिस्सा रहे और बर्बर दमन का डटकर मुकाबला किया। 70 के दशक में बहुत भारी नुकसान हुए, पूरे देश के क्रांतिकारी आंदोलन में एक लंबा दौर ऐसा आया जब आंदोलन पिछड़ गया। उस दौर में भी अजय दा ने पार्टी लाईन को दृढ़ता के साथ ऊंचा उठाये रखा। उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने दुश्मन के निर्दयी खूनी चेहरे का सामना किया और उस समय में भी उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में जड़ जमाये बैठे संशोधनवाद को बेनकाब किया। अजय दा ने अपने लंबे क्रांतिकारी जीवन में हमेशा ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल झण्डे को ऊपर उठाये रखा। अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। केवल भारत के प्रति-क्रांतिकारी शासक वर्ग व उनके आका साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं, बल्कि संशोध नवाद के तमाम रूपों के खिलाफ वह बोल्शेविक ऊर्जा के साथ लड़ते रहे।

न उसका दुबला-पतला शरीर, न बीमारियां, न ही उनकी बढ़ती (63) उम्र उनकी क्रांतिकारी उर्जा और आदर्शों को कभी कमजोर नहीं कर पाई। वे क्रांतिकारी जिम्मेवारियों को उठाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। 1980 में पार्टी यूनिटी में उत्पन्न आंतरिक संकट में व अन्य मौकों पर भी पार्टी में आये भटकाओं के खिलाफ भी उन्होंने जबर्दस्त संघर्ष चलाया। सीपीआई (एम-एल) (पीपुल्सवार) की 2001 में हुई पार्टी कांग्रेस के बाद दो साल तक उन्होंने केन्द्रीय राजनैतिक शिक्षा विभाग (स्कोप) के मुखिया के तौर पर अपनी सेवायें प्रदान कीं। उन्होंने भारत के खेतिहर संबंधों का बहुत गइराई से अध्ययन किया। वो जनता और पार्टी कतारों में आसानी से घुलमिल जाते थे। कॉमरेड अजय दा पुरानी पार्टी यूनिटी व नई एकीकृत पार्टी पीपुल्सवार में लम्बे समय तक पार्टी प्रकाशन विभाग व पार्टी पत्रिकाओं के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते रहे। वो इंग्लिश और बंगाली में धारदार लेखन करते थे। दोनों भाषाओं पर उनकी जबर्दस्त पकड़ थी। उन्होंने एम-एल-एम का राजनीतिक व सैद्धांतिक अध्ययन बहुत ही गहराई से किया और अपने व्यवहार में भी ताउम्र लागू किया।

अजय दा ने अपने क्रांतिकारी जीवन में सदा ही कम्युनिस्ट नैतिक मूल्यों व विचारों को ऊंचा उठाये रखा। वो दूसरों के उकसाने के बाद भी कभी अनावाश्यक तर्क नहीं करते थे। वह सभी कॉमरेडों के साथ बहुत दयालुता और प्यार से रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रांति के लिये जनता की सेवा में न्यौछावर कर दी।

उनके द्वारा स्थापित आदर्श हमें सदा उनकी याद दिलाते रहेंगे। हमें प्रेरणा देते रहेंगे। 60 के दशक के नौजवानों में एक आदर्श व्याप्त था कि शादी करना क्रांति में एक बड़ी बाधा है। इसको मानते हुये वह ताउम्र अविवाहित रहे। उनके विचार, आदर्श और उनकी उर्जा हमारे कम्युनिस्ट जीवन को सदा ही रोशनी देती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिये वह प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

कॉमरेड अजय दा की शहादत हमारी पूरी पार्टी के लिये बहुत बड़ा धक्का है। कॉ. अजय दा को हमें ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में खोया है जब हमारी नई पार्टी अपनी एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी है। और अपनी राजनीतिक सैद्धांतिक एकता को और मजबूत बना रही है। ऐसे समय में उनकी और उनके अनुभवों की हमें और ज्यादा जरूरत थी। हमारे केन्द्रीय कमेटी (सीसी) के प्यारे साथी कॉमरेड मुरली की फर्जी मुठभेड़ में हुई शहादत के दो महीनों के अंदर ही अजय दा को खोना हमारे लिये और बड़ा नुकसान है। 'प्रभात' को दृढ़ विश्वास है कि जनता और पीएलजीए के योद्धा इस क्षति की पूर्ति के लिये अपनी पूरी संकल्प-शक्ति के साथ काम करेंगे। जिस अदम्य सहास और बोल्शेविक उर्जा के साथ कॉमरेड अजय दा क्रांति के लिये दृढ़तापूर्वक संघर्ष करते रहे, वैसे ही हमारे कॉमरेड आगे बढ़ेंगे। हमारी ऐतिहासिक एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस और सीसी ने हमारे सामने महान लक्ष्य रखा है - पीएलए का निर्माण करो! आधार इलाकों का निर्माण करो!! पूरे देश की मुक्ति के लिये सामंतवाद, साम्राज्यवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की सत्ता को तबाह कर डालो। और जनता की नई जनवादी सत्ता की स्थापना करो।

हमारे वरिष्ठ व प्यारे नेता अजय दा अमर हैं! सदा उनका नाम गूंजता रहेगा।

आइये, उनके सपनों को पूरा करने की शपथ लें और उनके उच्च कम्युनिस्ट नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाये रखें। ★

अपने परमप्रिय नेता अजय दा (परिमल सेन) को लाल–लाल श्रद्धांजली अर्पित करें।

उनके सच्चे विचारों और आदर्शों को अपनाते हुये आगे बढ़ें!!

यह हमारी पूरी पार्टी के लिये बहुत दुखद समाचार है कि अजय दा नहीं रहें। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ व बहुत प्यारे नेता थे। 15 अगस्तर 2007 को उन पर दिमागी मलेरिया का हमला हुआ, जिससे अजय दा शहीद हो गये। इसके साथ ही हमने उस महान शख्स को खो दिया जिसने भारतीय क्रांति में तीन दशकों तक व नई पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कॉमरेड अजय दा पर अगस्त के पहले सप्ताह में मलेरिया का हमला हुआ था। तब वह एक गुरिल्ला जोन में ईआरबी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिये गये हुये थे। शुरू में हमारे कॉमरेडों ने सोचा था कि यह वायरल बुखार होगा। परंतु वो वहीं गंभीर रूप से बीमारी के चपेट में आ गए थे। इसके बाद भी उन्होंने अपने विभाग की मीटिंग में बड़ी शिद्दत के साथ शिरकत की थी, पर शाम को हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बैठने के काबिल नहीं रहे। उस शाम (13 अगस्त) से 14-15 अगस्त तक अजय दा डॉक्टरों की टीम की देखरेख में थे। लेकिन डॉक्टर साथियों के तमाम प्रयासों के बावजूद 15 अगस्त 2007 को शाम के 7.30 बजे अजय दा ने आखिरी सांस ली। वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था व शासकों की साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के चलते हमारे देश में ऐसे ही बीमारियों से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। अजय दा की शहादत हमारे लिये गहरा धक्का है।

कॉमरेड अजयदा हमारी पार्टी के एक बुजुर्ग नेता थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक तमाम कठिनाइयों, बाधाओं को पार करते हुये क्रांतिकारी जीवन बिताया। पश्चित बंगाल में 1960 के दशक में वह कम्युनिस्ट राजनीति से प्रेरित हुये, तब वह छात्र थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुये थे व अपने भाई-बहनों के साथ कोलकत्ता युनिर्वसटी से एमकॉम की पढ़ाई की। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुये पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी भी की। वह उस समय उस नई पीढ़ी के नौजवानों में से थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माओ के नेतृत्व में चल रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनैतिक-सैद्धांतिक संघर्ष को देखकर बड़े हो रहे थे। वो संघर्ष सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पैदा हुये आधुनिक संसोधनवाद के खिलाफ था। उसी दशक में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति भी दुनिया के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी। अजय दा बहुती अच्छी राजनैतिक-सैद्धांतिक परिस्थितियों की पैदावार थे। जब सीपीआई व सीपीआई (एम) के संशोधनवादी व नव संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ हमारे देश में संघर्ष चल रहा था, वे तब ऐतिहासिक सशस्त्र नक्सलबाड़ी आंदोलन व कॉमरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व से बहुत ही प्रभावित हुए। 1960 के अंत में वह सीपीआई (एम-एल) के सदस्य बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल के फासीवादी राष्ट्रपति शासन व देश के 'आपातकाल' के काले दिनों में बहुत ही भयंकर अमानवीय परिस्थितियों में जेल के अंदर 5 साल बिताये।

अजय दा ने क्रांतिकारी तूफानी पक्ष को चुना। उन्होंने कलकत्ता शहर की डलहौसी यूनिट से नक्सलबाड़ी से प्रेरित राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। डलहौसी सीपीआई (एम-एल) युनिट ने ना केवल महान जन आंदोलनों का नेतृत्व किया बल्कि भयंकर दमन के बीच दूसरे राज्यों के आंदोलनों से समन्वय करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तब राजसत्ता के दमन का तांडव अपनी चरम सीमा पर था। बहुत सा केंद्रीय नेतृत्व या तो जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था या उनकी हत्यायें कर दी गई थीं।

सीपीआई (एम-एल) में शामिल होने के बाद उन्होंने डलहौसी एरिया पार्टी कमेटी में काम करना शुरू किया। हमारे प्यारे कॉमरेड परिमल सेन (अजय दा) ने 1972-73 के अंत में उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब आंदोलन पिछड़ गया था और बहुत से कामरेड निष्क्रय हो गये थे। वो समय कांग्रेस पार्टी के श्वेत आंतक का समय था। पूरे कलकत्ता में कांग्रेस के गुंडा तत्वों (प्रतिरोध वाहिनी) ने आंतक मचाया हुआ था। 1972-73 में कलकत्ता से क्रांतिकारी ताकतों को पीछे हटना पड़ा था।

तब भी कॉमरेड अजय दा ने पूरी दृढ़ता से अपने इलाके में क्रांतिकारी गतिविधियों की मशाल को जलाये रखा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं कांगेस के बाद लिन पियाओ की लाईन के सावाल पर पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। कॉमरेड अजय दा महादेव मुखर्जी के नेतृत्व वाली सीपीआई (एम-एल) में पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी सदस्य के रूप में शामिल हुये। बाद में 1974 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में वह कुछ अन्य कॉमरेडों के साथ अलग हो गए। महादेव मुखर्जी की सेकेंड सीसी की भ्रांतिपूर्ण कार्यनीतिक लाइन से बाहर आये और कलकत्ता की प्रेसीडेंसी जेल में कुछ कॉमरेडों के साथ मिलकर पुरानी गलतियों पर पुनरविचार किया। जेल में उनको बहुत सी यातनायें दी गईं। हाथ तोड़ दिया गया और उन्हें प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता से बधवान जेल भेज दिया गया। 24 फरवरी 1976 को जेल से कुछ कैदियों के भागने की घटना के बाद अजय दा के साथ और अन्य बहुत से कॉमरेडों को जो कामरेड चारू मजुमदार की लाइन को मानने वाले थे, अलग-थलग करके 24 घंटे तक यातना गृहों में रख कर क्रूर यातनायें दी गईं और यह सिलसिला चलता ही रहा।

(शेष पृष्ठ 41 में...)